[Shri Joytirmoy Bosu]

shown as Rs. 1790.4 crores, by 1978-79 it has gone up to Rs. 2401.4 crores. In 1975-76, it was Rs. 2178.2 crores. Besides, there is a huge amount of black money mainly kept with their distributors, agents dealers and benamidars. It is estimated that an amount of Rs. 1500 crores go out of the country through invoice manipulation every year. A big part of this money is given in Indian rupees to the foreign agents and missionaries for anti-India activities in the country.

The Managing Director of a Motor Company, a Britisher who has shifted his activities from Calcutta to Shillong, has given millions of rupees to foreign missionaries in Indian rupees and took back the same in foreign currencies, abroad with a premium.

Detailed reply from the concerned Ministry is called for.

12.52 hrs.

*

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL, 1980-81—*Contd.*

MINISTRY OF INDUSTRY—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Industry.

Mrs. Krishna Sahi.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में जब माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज, भाषण दे रहे थ, तो मैं ने बहुत ध्यान से उसको भी सुना और तीन वर्ष का उनका और उनकी पार्टी का परफामेन्स भी देखा । वह अपने भाषण में अपनी सरकार की नीतियों की दुदुभि भी जोर से बजा रहे थे और अपनी उपलब्धियों की झड़ी भी लगा रहे थे । लेकिन मैं समझती हूं कि उस श्रृंखला में वह कुछ कड़ियों को जोड़ना भूल गये । मैं अपनी ोर से उनकी तथा-कथित सफलताओं को उसमें जोड़ना चाहती हूं ।

मैं जानना चाहती हूं कि जनता पार्टी के शासन-काल के तीन वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों में कितनी हड़तालें हुईं, कितने लाक-आउट्स हुए, हमारे कितने उद्योग-धंधे बन्द हो गये और कितने मैनडेज का लास हुआ । इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन कहां तक पहुंच गया ? गत वर्ष हमारा उत्पादन शून्य तक पहुंच गया, उससे हमारी कितनी राष्ट्रीय क्षति हुई ? ये सारी बातें हमारे सामने प्रश्न-चिन्ह बन कर उपस्थित हैं ।

जनता पार्टी की सरकार तीन वर्षों तक रही और अपने औद्योगिक साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों पर से सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटा लिया । मनोपलीज कमीशन की भूमिका नगण्य रह गई और उसके अधिकार बहुत सीमित हो गए । बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सूद की रियायत मिल गई और उनकी साधन आसानी से उपलब्ध किये गये । कहने का मतलब यह है कि जहां उनके अपने खजाने मोटे हो गये, वहां औद्योगिक क्षमता निम्नतम स्तर पर पहुंच गई ।

देश को आर्थिक स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की ओर ले जाना प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था । उनका दर्शन देश मे औद्योगिक क्रान्ति का अग्रदूत बन कर आया था । जब तक हमारी पार्टी की सरकार रही, तब हम आत्म-निर्भरता की ओर जा रहे थे । लेकिन जब जनता पार्टी का शासन आया, तो इस दर्शन पर कड़ा प्रहार हुआ और इसका सब से बुरा असर औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ा । मैं उसका एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहती हूं । तीन वर्षों में राची के एच ई सी को खोखला बना दिया गया । पता नहीं किस को व्यवस्थापक के रूप में इन्होने भेजा, मैं किसी का नाम नही लेना चाहती, लेकिन जो व्यवस्थापक यहां से गए उन्होने तीन वर्षों में उस को खोखला ही नही बना दिया बल्कि सब तरफ से उस को अपंग बना कर छोड दिया । 77, 78 और 79 तक 65 करोड़ का तो कारखाने का लास हुआ है और इस के अलावा जो उस के एस्टैब्लिशमेंट पर खर्च था वह तो बढ़ता ही चला गया । इसी एच ई सी में 76 और 77 में इस के उत्पादन के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी और मुनाफा भी हुआ था । एच ई सी हिन्दुस्तान की आर्थिक ऊंचाई का एक बहुत बड़ा स्तम्भ है । लेकिन वहां ऐसे व्यवस्थापक गए जो उस की निगरानी तो कुछ कर नहीं सके, उस का उत्पादन कुछ कर नहीं सके उलटे वहां जो उत्पादन हो सकता था और होता था उस को भी बन्द कर दिया । तत्कालीन उद्योग मंत्री ने संभवत: जैसी कि हम लोगों की जानकारी है, वैस्ट जर्मनी की एक

*Moved with the recommendation of the President.

बहुत बड़ी फर्म को करोड़ों का कांट्रेक्ट दिया। मैं जानना चाहती हूं कि यदि हमारे यहां उत्पादन हो सकता था और जिन चीजों की उत्पादन क्षमता हमारे यहां थी, वह यहां क्यों नहीं बनाई गई और बाहर विदेशी मुद्रा क्यों उस पर खर्च हुई जिस के लिए हम कर्जदार हो गए ? पहली बार जब हमारी सरकार आई है तो एच ई सी को करोड़ों का कांट्रैक्ट बाहर से मिला है। मैं कहना चाहती हूं कि इस में मैनेजमेंट के ऊपर निगरानी रखने की जरूरत है और चुस्ती की जरूरत है क्योंकि एग्जीक्यूट करना उन का काम है। इस से हमारी जो आर्थिक क्षति हुई है वह बहुत अंशों में पूरी होगी।

वाइजैग में भी एक स्टील प्लान्ट है। वहां भी उस की जो आवश्यकताएं हैं वह बाहर से आती हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी एच ई सी को आर्डर दिया जाय और उस को कांट्रेक्ट दिया जाये ताकि वह वाइजैग में उस को सप्लाई करे और उसकी आर्थिक उन्नति हो सके।

उद्योग विभाग के अनुदान का समर्थन करते हुए मैं भारत सरकार का ध्यान बिहार की विपन्नता की ओर ले जाना चाहती हूं। उन से अदब के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि यह एक विडम्बना है कि उपजाऊ धरती है, प्रचुर खनिज पदार्थ हैं, अगाध जल-स्रोत है, यह सब रहते हुए भी बिहार क्यों नंगा और भूखा है? देश में जितने कोयले के उत्पादन की क्षमता है उसका 40 प्रतिशत अकेले बिहार में है। अभ्रक 60 प्रतिशत है। तांबा, लोहा, बाक्साइट, क्रोमाइट, जस्ता, मैंगनीज, जिंक, ऐस्बेस्टस, फायर-क्ले, चूना-पत्थर आदि काफी मात्रा में बिहार में है। लेकिन हमारे यहां आर्थिक दिवालियापन है ? क्यों? इसलिए कि जो हमें रायल्टी मिलती है वह बहुत पुराने दर पर मिल रही है और जो मैंगनीज है, अभ्रक है या और भी जितने खनिज पदार्थ हमारे यहां पर मिलते हैं उन के आधार पर कोई इंडस्ट्री हमारे यहां नहीं लगाई गई है। बहुत दिनों से इस की मांग चली आ रही है। मैं भारत सरकार से कहना चाहती हूं कि यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिहार में पैदा होता है जो कि भारत में क्या विदेशों में भी बहुत कम जगहों में उपलब्ध होता है।

छोटा नागपुर के लोहरदगा एवं उस के आस पास में एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा भण्डार है, फायर-क्ले और बौक्साइट का भी बहुत बड़ा भण्डार है। यह सारी सम्पत्ति वहां ऐसी हैं कि जो बिहार की आर्थिक उन्नति अकेले कर सकती है। 20–25 लाख टन बौक्साइट का लदान प्रति वर्ष वहां से होता है। लेकिन कोई यातायात की सुविधा नहीं है। यदि इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की सहायता वहां दी जाय तो कागज और एल्यूमिनियम के कारखाने वहां खड़े हो सकते हैं।

बिहार इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने लटेहाट में एल्यूमिनियम फैक्ट्री की स्थापना के लिए आवेदन पत्र दिया है। सभी फार्मलिटीस बहुत साल पहले ही तय कर दिये गए हैं लेकिन मैं नहीं जानती कि क्यों उस में भारत सरकार विलम्ब कर रही है और दुख की बात है कि जब बिहार ने आवेदन पत्र दिया था उस के बाद दूसरे प्रान्तों ने जो आवेदन पत्र दिया तो दूसरे प्रान्त को तो दे दिया गया लेकिन बिहार सरकार को नहीं मिला। यह आश्चर्य की बात है कि दो ढाई साल पहले ही यहां से पश्चिम बंगाल की एक प्राइवेट फर्म को यह दिया गया है।

धनबाद में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड है जहां जस्ते और सीसे का उत्पादन होता है। उसकी क्षमता 18 हजार टन है। इस के भी आधुनिकीकरण के लिए हमारी योजना भारत सरकार के पास पड़ी है। 20 करोड़ की यह योजना है। इस से इस की कैपेसिटी बढ़ जायेगी तो उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। लेकिन पता नहीं भारत सरकार के उद्योग विभाग में यह कागज कहां पड़ा हुआ है।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि उत्तर बिहार में सहरसा और पूर्णिया में चीनी और जूट की मिलें हैं, जिनमें काफी मात्रा में उत्पादन होता है, जो कि वैस्ट बंगाल की बहुत सारी फैक्ट्रियों में सप्लाई होता है, लेकिन हमें अभी तक इसका आशय पत्र भी नहीं मिला है। हमारी जूट की मिलें बन्द हैं और चीनी के कारखाने बन्द हैं, इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

13 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें जो इनके विभाग से संबंध नहीं रखती हैं, फिर भी मैं कहना चाहती हूं। हमारे यहां पैट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स

[श्री मती कृष्णा साही]

की स्थापना की मांग बहुत दिनो से चली आ रही है, इससे न सिर्फ बिहार की उन्नति होगी, बल्कि इसका भारत-वर्ष पर भी असर पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो इन का सिस्टम है, जो तरीका है, वह उद्योग विभाग देखे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है । यदि कहीं पर कम्पनीज एक्ट में परिवर्तन करना पड़े तो वह भी करना चाहिए । यह तभी हो सकता है, जब हमारे पास ऊर्जा होगी । आज हम हाइड्रो और थर्मल पावर पर निर्भर कर सकते है, लेकिन एक समय आयेगा जब हमे एटम से ऊर्जा लेनी पड़ेगी और इसके लिए जरूरी है कि हमारे बिहार मे एटोमिक पावर अथोरिटी की स्थापना हो । न्यूक्लियर और फयूअल से हम बिजली ले सकते है, लेकिन हमे यूरेनियम की भी उपेक्षा नही करनी चाहिए, जो कि बिहार में काफी तादाद में मिलता है ।

मैं अंत में यह कहना चाहती हू क यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो बच्चा रोगी होता है, जो बच्चा रुग्ण होता है, उसको मा विशेष ख्याल करती है, इसलिए मेरा माननीय मत्री जी से अनुरोध है कि बिहार बहुत ही रुग्ण है, बहुत अस्वस्थ है, इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको पैरो पर खडा करने के लिए, आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए ।

मैं बड़े अदब से यह भी कहना चाहती हू कि बिहार मे डिफेंस की इन्डस्ट्रीज की बहुत दिनो से मांग चली आ रही है और टुरिज्म पर भी हम इन्डस्ट्रीज वहा पर स्थापित कर सकते है । हमारे यहा बहुत ही ऐतिहासिक सुन्दर-सुन्दर जगहे हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य हैं, जिनको यदि इन्डस्ट्री का रूप दिया जाए, तो हमारे बिहार की काफी आर्थिक उन्नति हो सकती है । गाधी जी बिहार को भारत का दिल कहा करते थे । मै जानना चाहती हू कि यदि हम लोगो का दिल ही रोगग्रस्त रहेगा तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते है । रिजनल इम्बेलेंस का बात होती है, चारो तरफ आन्दोलन छिड जाते हैं, बहुत अधिक विपन्नता बढ जाती है, तो इसके लिए उद्योग विभाग उत्तरदायी होता है । मैं मत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करती हूं कि सभी विभाग जो इन्डस्ट्री बढाने से संबंधित हैं, उनका को-आर्डिनेशन होना चाहिए, नही तो निजी उद्योग के छोटे-छोटे लोग परेशान होकर काम को छोड देते है कि कैसे आगे उद्योग करेंगे । इसलिए मेरा मत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस ओर भी ध्यान दे ।

इन शब्दों के साथ मैं पुन उनसे अनुरोध करती हू कि वे बिहार की ओर विशेष ध्यान और मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान का मांगों का समर्थन करती हूं ।

*SHRI D. S. A. SIVAPRAKASAM (Tirunelveli): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, welcoming the Demands for Grants of the Ministry of Industry, I wish to make a few suggestions in regard to industrial development of backward areas.

When our present Finance Minister, Shri R. Venkataraman was the Industries Minister in Tamil Nadu, I should say that his entire tenure was an era of industrial development and Tamil Nadu came to occupy third place in the industrial map of India. This happy situation continued till the D.M.K. Government lasted in Tamil Nadu. Due to the ineptitude of AIADMK Government in Tamil Nadu, the state has slided to 13th position in industrial development. In his public speech some ten days ago, Shri R. Venkataraman referred to this unfortunate position and stated in unequivocal terms that it was primarily due to lack of initiative on the part of AIADMK Government. The AIADMK Government of Tamil Nadu does not offer incentives to entrepreneurs. Because of this, the second unit of Ashok Leylands, proposed to come up in Tamil Nadu, has been taken away to another State. Similarly, the Railway workshop which the Central Government intended to set up in Tamil Nadu has been taken away to some other State because of inaction on the part of AIADMK Government. I request that the Central Government should take direct interest in the industrial development of Tamil Nadu. Even one Tamil Weekly which was unashamedly the mouth-piece of AIADMK Government, has editorially commented upon the callous attitude of AIADMK Government in Tamil Nadu so far as industrial development of the State is concerned and it has blamed the present Government for large industries being taken away from the State of Tamil Nadu.

The Central Government should ensure that heavy industries are not set up only in particular States. They

*The original speech was delivered in Tamil.

should be set up in all the States of the country so that the industrial development of the country is put on even keel. I have to regretfully point out that in my constituency Tirunelveli the Central industrial undertakings are negligible in number. Only the Heavy Water Plant is located in Tuticorin and no other notable central industrial undertakings are there. I request that the Central Government should take steps to set up industries in this permanently drought-afflicted part of the country. An industrial survey should be conducted and suitable industries should be organised in these parts. The Government should consider the proposition of putting up a shipyard in Tuticorin. Tuticorin products the largest quantum of salt in the country. With salt as the basic raw material, chemical industries can be set up here. In my parliamentary constituency, the assembly constituencies of Vilathikulam and Ottapidaram are always facing drought conditions and naturally they are backward in every aspect of human life. There is not even one lathe in this area. The Government of India should conduct a survey of this area and assist in the matter of organising suitable industries here. There should be a permanent Industrial Survey organisation which should take up particular areas which are backward industrially and suggest suitable industries.

At present, only the affluent section of society are able to get financial assistance from Industrial Investment Corporation, Credit Corporation etc. The Unit Trust of India sells units to the public and buys shares in industrial undertakings. Another such institution can be started to take money from the public and buy shares of industrial undertakings. I request the Government to consider this proposition favourably. The Government should give direct assistance to the setting up of small industries and cottage industries. The Khadi and Village Industries Commission is giving financial assistance for the settng up of tiny match units. Simlarly for other cottage units also, the Government should extend financial assistance.

In Tamil Nadu, like my constituency Tirunelveli which is industrially backward, Periyar District is also industrially backward. The Government of India should declare it as such and fix a time-limit for developing industrially this district. If no time-limit of 5 years or 10 years is fixed, then the adjacent areas also might become industrially backward. The Central Salt Commissioner should ensure that ships are allocated only to salt manufacturers and not to middlemen traders, who are the prime-movers in creating artificial scarcity of essential commodities. If an entrepreneur wants to set up an industry, a minimum period of 2 years is consumed in observing all the rules and regulations. I suggest that these rigid rules and regulations should be relaxed to such an extent that from the date of application within six months the industry should start production. All the other infra-structure amenities like power, raw materials etc. should be made available by the Government of India without any delay.

Before I conclude I would refer to Beedi industry. The Government with a view to encouraging self-employment among common people has given excise exemption for label-less beedis. The former Government had given excise exemption for label-less 60 lakhs of beedis and the present Finance Minister has reduced it to 30 lakh beedis for such tax exemption. An individual can manufacture 1000 to 1500 beedis a day and he can go up to 5 lakh beedis in a year without paying any excise duty. This concession is given for generating self-employment. But big beedi-manufacturers have intruded into this sector for evading excise duty. Such excise-evasion on a large scale is taking place in Kerala, West Bengal and U.P. They manufacture beedis and

[Shri D. S. A. Sivaprakasam]

sell them without labels upto 30 lakhs without paying excise duty. The Government is being deprived of its legitimate revenue. The Government should remove this kind of excise distinction immediately in the interest of survival of beedi industry. If it is not done, the beedi industry would be decimated. I demand that the Government should take immediate action in this regard.

Before I conclude, I would like to point out that last year there was no increase in industrial investment but there was 22 per cent increase in savings, which is necessary for capital formation. I would like to know the reasons for this.

With these words, I conclude my speech.

श्री चक्रधारी सिंह (सरगुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो अनुदान की मांगें पेश की गई हैं, उन का मैं समर्थन करता हूं । ये मांगें जो हैं अनुकूल एवं वाजिब है ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे देश में बहुत से उद्योगों की स्थापना हो सकती है, जिस के लिए प्रयास जारी है। इस देश में बहुत से अच्छे खदान हैं और जो कच्चा माल है, उस की उपलब्धि विपुल मात्रा में भी है । अगर उस की खोज की जाए । अभी हमारे देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर उद्योगों का निर्माण होना अति-आवश्यक है । जिन क्षेत्रों में अभी तक उद्योगों की स्थापना नहीं हुई है, वहां अगर छोटे लघु उद्योग या मध्यम वर्ग के उद्योग स्थापित किये जाएं, तो उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है और देश में जो आर्थिक कार्यक्रम है, उस में वे सहायक हो सकते हैं । ये जो छोटे-छोटे लघु उद्योग और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, उन की तरफ़ मैं विशेष ध्यान आप का आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस देश में अभी भी बहुत से ऐसे अनएम्पलायड लोग हैं, जो नौकरी प्राप्त नहीं कर सके हैं । अगर इन उद्योगों की स्थापना की जाए, तो उन को रोजी और रोटी मिल सकती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, इन की स्थापना जहां अभी नहीं हो पाई है, वहां अवश्य की जाए । मैं सरगुजा जिला, मध्य प्रदेश से चुन कर आया हूं वहां की विशेष जानकारी देना चाहूंगा । वह एक पिछड़ा हुआ और जंगली इलाका है, जहां अभी तक कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है और कोई भी औद्योगिक प्रगति नहीं हो पाई है, जिस से वहां के लोगों को फ़ायदा हो सके और वह जिला प्रगति की ओर बढ़ सके । पिछले कई वर्षों से वहां जो मेनेपाठ का क्षेत्र है, वहां पर अल्युमीनियम बाक्साइट की खदानों के लिए सर्वे का काम चल रहा था लेकिन वह भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है । इस की मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन 3, 4 साल हो गये हैं, इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अगर सर्वे पूरा हो गया होगा, तो निसंदेह उस जिले में बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्थापित हो सकती है । जो पूरे देश में अल्यूमिनियम और बोक्साइट पाया जाता है उसका छठा हिस्सा जैसा कि सर्वे रिपोर्ट से पता लगा है कि मेनेपाठ में पाया जाता है । इस प्रकार से मैं सोचता हूं कि वहां पर अल्युमिनियम और बोक्साइट की इंडस्ट्री स्थापित होनी चाहिए जहां कि इतना अधिक अल्युमिनियम और बोक्साइट पाया जाता है। इस से देश को आर्थिक दृष्टि से बहुत मदद मिलेगी और उस क्षेत्र में जहां कि अनएम्प्लाएमेंट बहुत ज्यादा है, उसको कम करने में भी मदद मिलेगी। वहां के लोगों को वहां नौकरी और रोजी मिल सकेगी ।

दूसरे वहां एक प्रतापपुर इलाका है जहां पर यूरेनियम का सर्वे चल रहा है । वहां सर्वे कर के वहां पर यूरेनियम के उद्योग स्थापित कर दिये जाए । यूरेनियम के वहां पर प्लान्ट स्थापित कर दिये जाएं । इस से उद्योग को बहुत बड़ा स्रोत एनर्जी मिल जाएगा और देश को जो दूसरी चीजों के लिए शक्ति चाहिए वह भी इस यूरेनियम के द्वारा मिल सकती है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो हमारा जिला है यह बहुत पिछड़ा हुआ है । क्षेत्रफल की दृष्टि से सरगुजा जिला मध्य प्रदेश में शायद दूसरे नम्बर पर आता है । वहां जनसंख्या कम है । जंगल, पहाड़, नदी, नाले वहां अधिक हैं । उस ऊबड़-खाबड़ जमीन का सही प्रयोग नहीं हो रहा है । वहां के जंगलों में बांस बहुत पाया जाता है । उसका उपयोग कागज की इंडस्ट्री लगा कर किया जा सकता है इस से वहां के लोगों को मजदूरी और नौकरी मिल सकती है और वहां इंडस्ट्री स्थापित हो जाने से वहां के लोगों के आर्थिक विकास में भी मदद और सहायता मिल सकती है । हमारे सरगुजा जिले में तीन बड़े-बड़े पठार हैं । उनकी भूमि समतल है । वहां मैं एक डेरी फार्म खोलने की सिफारिश करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर सैकड़ों एकड़ पठारी जमीन है जो कि खाली पड़ी हुई है। इस जमान का आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ है । इसलिए वहां पर डेरी फार्म खोल दिया जाए जिससे कि दूध और दूध से बनी चीजें देश में वितरित हो सकें । उस से जो लगा हुआ क्षेत्र

दूध और दूध से बनी चीजें सप्लाई की जा सकती हैं । इसलिए वहां एक बहुत बड़ा डेरी फार्म स्थापित किया जाए ।

इसी तरीके से मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विश्रामपुर थर्मल प्लांट की जो वहां की योजना है वह यहां पर प्लानिंग कमीशन में पड़ी हुई है । वहां जल्दी ही उसकी स्थापना होना बहुत आवश्यक है । वहां जो बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यक चीजें के रूप में पायी जाती हैं उनको भी इस थरमल प्लांट में बहुत मदद मिल सकती है । उसके आसपास कोयले की खदानें हैं जिन से कि हिन्दुस्तान को विपुल मात्रा में कोयला प्राप्त होता है । थरमल पावर स्टेशन को जो कोयले की जरूरत होती है उसके लिए वहां से पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरगुजा जिले की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और वहां पर इंडस्ट्रीज की स्थापना की जाए ताकि जिले का उद्धार हो सके और देश भी लाभान्वित हो सके

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have got to complete this discussion at 3.30 P.M. The hon. Minister will reply to the debate at 3.30 P.M. The entire demands have to be passed at 4.30 P.M. Then we have to take up the next item. Therefore, every Member will take 5 minutes only.

SHRI A. A. RAHIM (Chirayinkil): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, let me congratulate the Finance Minister for his budget which has been welcomed by almost all sections of the people of India. The budget reverses the trend set by the earlier ones introduced by the previous regime. In this era of advanced technology and development it needs considerable courage to propagate and implement a theory against industrialisation of the country. This was what the present opposition tried to do when they were in power and mercifully failed. Without rapid industrialisation, the country can never progress. To pose agriculture *versus* industry is to say the least, childish. If agriculture alone is to be developed and industry ignored, this country would continue to be an under developed country with permanently poor peasants and life-long bee-keepers. As a matter of fact, for development of agriculture, industrialisation is an absolute must. It is no wonder that our industrial growth rate has become negative. I am not denying that there were a variety of economic factors which work behind this phenomenon of negative growth rate. But let it be recognised that the main factor responsible for this phenomenon was a total lack of political will and direction. Luckily, the people were quick to see the impending danger and they turned out of office those who brought the national economy to the brink of disaster. Here we are with a legacy of mismanaged economy but with a clear mandate to remove the distortions that have been introduced in the nation's economic life. Mismanagement was pervasive during the last three years so much so that not only have several healthy industrial units tended to be sick, but the industrial climate itself has been vitiated. It is now our task to recreate this climate by inducing the much needed discipline among workers and alertness and efficiency among managers. Our industrial scene has been based on a culture of conflict, so to say. The conflict of interest between workers and the management has been at the root of the strikes and lockouts which we have cynically learned to live with. I am not going to the details of the growing loss of mandays. At the same time, I would like to emphasise the need to enact a new industrial relations law so as to bring about a new industrial culture based on mutuality of interest, instilling in the minds of workers a sense of participation. Moreover, the number of unions in a unit should also be limited. And while bringing forward such a legislation, we will do well to bear in mind those aspects of the previous regime's draft which met with universal opposition. Such a law should take into account also the need to cater to the thrust for development of industry and not merely regulating labour relations. It is customary for our industrial managers to put the blame for all this failure at the door

[Shri A. A. Rahim]

of workers. I would not blame workers nor would I blindly defend all of them. I have my own suspicion about our militant comrades who pose as the guides, friends and philosophers of workers. Even so, I believe many of our industrial centres could be made healthy if it is brought home to workers that they are a vital part of the institution in which they work.

Sadly, this has not been achieved even in some major public sector undertakings which are supposed to occupy commanding heights of the economy. I will refer to just one public sector project which has had labour problems from time to time in my State. The Hindustan Paper Corportation's Newsprint Project in Kerala was to be commissioned two years ago but the target date of commercial production goes on being revised from time to time. It is perhaps time that the Government ordered an enquiry into the functioning of the Corporation particularly to find out what exactly ails the Kerala Newsprint Project.

Coming as I do from Kerala I cannot help highlighting the industrial backwardness of the State. I am indeed distressed that this year also there is practically no allotment for any major industry in Kerala. I am sure you will agree that in the larger interest of this country it is very necessary to ensure a fair distribution of public sector industry in all the States. We have abundance of manpower and we are the only State which could boast of surplus hydroelectric power. As a matter of fact we have gone to the rescue of our neighbouring States at moments of crisis. Our well-trained manpower is exported to all sorts of places. We must have more industrial units in the State if the resources are to be tapped adequately. Moreover we got plenty of natural resources such as mineral wealth and rich forests. The State is fairly well served so far as communications are concerned, whether it is by sea, road or rail. Yet the Government have been staying away from setting up new public sector units there. It is an ideal place for locating industries that need a large number of educated persons as well as industries that consume large quantities of power. We have no major central public sector undertakings in the State. The investment in such undertakings in the State falls very much short of our eligibility on the basis of, say, population. Advances, investments by the national financial institutions is an index of the industrial activity. By this yardstick, Kerala has fared very poorly. Public in Kerala have been voicing concern with regard to a number of projects such as Aromatic complex, Caprolactum Project of F.A.CT, Railway Coach Factory and defence production units, expansion of Indian Telephone Industries unit and also Instrumentation Ltd. These are projects, which are agitating the minds of the people. Kerala State stands prominent in earning foreign exchange by way of exporting cash crops, marine products and also by remittance from Keralites abroad. I would, therefore, request the Minister for Industries to pay special attention to Kerala in the matter of location of new public sector units, especially at a time when our traditional industries like coir, cashew, handloom are facing serious crisis.

The problem of educated unemployment that has reached menacing proportions cannot be solved unelss there is an aggressive effort at promoting extensive development of small industries throughout the country. It is particularly so in my State where educated unemployment is the highest. For the last thirty years considerable work has been done in this direction, no doubt. But I do not think the results achieved so far have been commensurate with the money spent on it. I would like to draw the attention of the Minister particularly to certain aspects. Firstly, I would say that the banks have not

played their due role in the matter of promoting small industries the way they ought to have done. The Hon'ble Finance Minister also admitted the other day, in this House, unless a positive effort is made by the banks themselves to assist in the setting up and mothering of small industries, we will not be able to solve the problem of educated unemployment in this country. I believe, the Industry Ministry will take up some initiative in arriving at an effective procedure, that would involve the State Government departments, the banks and the enterpreneurs together at district levels. The banks and the departments concerned may be made accountable for their performance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are 35-40 speakers. You please conclude now.

SHRI A. A. RAHIM: I am sure the energetic young Industry Minister will do well to solve the many problems which beset industrial development of our country. I strongly support the Demand.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. R. K. Mhalgi: Your party has got 9 minutes.

*SHRI R. K. MHALGI (Thane): Mr. Deputy-Speaker Sir, the industrial policy of our country should have a firm foundation, if we want to put an end to poverty. The Central Government declared its industrial policy in 1956 and again in 1977. The key note of both these policies was that of "Mixed Economy". Considering the present situation, I feel that "Mixed Economy" should be the lodestar of our industrial policy. It must aim at achieving a balanced development of the public, cooperative and private sector. The public sector is, no doubt, important but at the same time, private and cooperative sectors should not be neglected. The Central Government should solve the problems faced by the private and cooperative sectors.

The Janata Party announced its industrial policy in 1977. It laid greater emphasis on the development of the small scale industry. The majority of Indians live in rural areas and it is necessary, therefore, that industries should be decentralised. The Janata Government's policy was that of encouragement to small scale industries and it aimed at achieving this objective. I request, Sir, that the present Government should also maintain the same policy.

Sir, presently thousands of small scale industries are sick. The condition of some of them is serious. I feel that four causes are mainly responsible for this state of affairs. (i) Scarce supply of raw materials; (ii) The power famine; (iii) Lack of financial assistance and (iv) Lack of marketing facilities.

Regarding the shortage of the supply of raw materials, I would like to cite one or two instances pertaining to Maharashtra State which will highlight the requirements of the State and the supply arranged by the Centre. Presently Maharashtra's requirement of cement is 1,31,000 metric tonnes a quarter. But the supply is only 35,000 metric tonnes. The requirement of coke and coal is 5600 wagons per month, but we receive only 2700 wagons. Against a requirement of 18,000 metric tonnes per year of paraffin wax, we receive only 11,140 metric tonnes. We need 6,500 metric tonnes pig iron per month, but we get only 2,480 metric tonnes per month. The difference between what we need and what we get, clearly brings out the position. The supply of raw material should equal the requirement of the State. Some States receive a bigger quantity of raw materials and some less. The Government of India should start the "nodal agency" scheme. It should be made more effective. Nodal agencies could perform the following functions. (i) Determine periodically quotas of raw material for different States taking into consideration the

*The original speech was delivered in Marathi.

[Shri R. K. Mhalgi]

need of the small scale industrial units (ii) monitor supply and movement of allocated raw materials to respective States and (iii) to have liaison between Central and Government agencies and State Governments.

Nodal agencies should hold meetings of the representatives of various States and solve the problems. This will remove the inequality of supply of raw materials.

The Central Government brings out a periodical "Small Scale Industries" which is published in English and Hindi. It shoud also be published in regional languages. This will enable all the people connected with small scale industries to obtain the information regarding the supply of raw material. Now, English and Hindi knowing people alone get the information published in this periodical. It is wrong to presume that all the people who run small scale industries know Hindi and English only. It is necessary, therefore, that this periodical should be published in regional languages also.

13.37 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair*]

Regarding the shortage of electric supply, it is needless to insert that industry and energy are closely linked. No industry can run without power. The Government of Maharashtra have sent six schemes to the Central Government for their approval. But many of them are pending since September 1977. I need not read the list, but Pavana scheme, Girana scheme and some other schemes are pending with the Central Government. The Government should take immediate steps to sanction these schemes.

The Ministry of Industry should pay greater attention to supply of energy for industrial units. The Ministry of Energy should be convinced that small scale industries cannot run unless there is sufficient and regular electric supply. The coordination between the Ministries of Industry and Energy, is therefore, very essential.

I want to make a few suggestions regarding financial assistance by the Central Government. A Credit Guarantee scheme was launched by Government of India in 1960. Many more schemes were also started. The credit guarantee scheme was enforced to integrate institutions giving credit facilities. The Central Government appointed a working group to integrate these institutions. It submitted its Report. I request, Sir, that this report should be published. The Central Government should take immediate decisions on the Report. This will help small scale industries to get required subsides in time.

The financial position of the small scale industries needs to be examined. The big industrialists purchase goods from small scale industries. But they do not make payments for more than six months. Big industrialists should be compelled to pay the amounts due within a month. It is for the Government to see how the statutory sanction can be created or any other means for this purpose.

The Government have given certain clear guidelines regarding marketing facilities to the effect that the Central Government, public undertakings and State Governments to purchase the goods manufactured by the small scale sector. The Minister should see whether all these agencies purchase the prescribed quantity of goods from the small scale sector. A report on the subject should be submitted to the House. This will help the small industries to sell their goods.

Commercial Estates should also be established on the lines of industrial estates. This will give better marketing facilities. There should also be 'mini-trade' centres. Testing facilities should also be introduced.

Fishing industry in my constituency faces some problems. Today in reply to unstarred question No. 5272, from my friend Mr. Parulekar, the Government replied as follows. I quote:

"Whether Government would treat fishing business as a small scale industry and give all the benefits arising out of it to the fishermen."

"No such proposal is under consideration."

I demand Sir, that the fishing should be declared a small scale Industry and fishermen should also get the benefits and facilities available to Small Scale Industries.

In 1977 the Janata Government started the District Industrial Centres. This was a very good innovation of the Janata Government and it should be continued.

It is said that these Centres will no longer function in future but the Government should take responsibility and run these centres effectively and help small scale industries. Presently, we see that they are not running as efficiently as they should. An action plan formulated in this connection should be implemented with phased programme. An employment target should be fixed for these centres.

The officers of these centres should behave courteously when owners of small industries come to seek guidance. They should give good guidance and help.

Let me briefly mention a point of my friend from Bihar desires to make since he may not get an opportunity to speak. Four thousand workers have lost their jobs as the K.E.W. Engineering Works in Bihar has closed down since last so many months. Something must be immediately done as it is a question of 4000 employees losing their livelihood. It is not proper that such a big factory should close down. I urge upon the Government to solve the problem of these employees immdiately.

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : माननीय सभापति महोदय, ढाई साल के जनता शासन के बाद पहली बार श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में यह बजट पास हो रहा है, जिस में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को रोकने के लिये और उत्पादन के तमाम क्षेत्रों में फिर से आत्म-विश्वास पैदा करने के लिये प्रयास किया गया है । कुछ विरोधियों को छोड़ कर इस बजट का सारे देश में स्वागत हुआ है । कल हम ने इस सभागृह में एक जाने-माने नेता श्री जार्ज फरनान्डीज साहब का बहुत लम्बा भाषण सुना । इसी सन्दर्भ में मैं आप से कहना चाहूंगा— हमारे उद्योगों की आज जो स्थिति है और हम लोग जो अपने-अपने क्षेत्रों से चुन कर आये हैं, सब के सामने यह तथ्य है कि इस देश की 50 फीसदी आबादी का जो क्षेत्र है वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और हर सदस्य चाहता है कि वह अपने क्षेत्र के बारे में यहां पर कहे, ऐसी स्थिति में जो समय यहां बोलने के लिये दिया गया है, वह बहुत अल्प है । उस में हर सदस्य अपनी बात को कह नहीं सकता है ।

कल जब जार्ज साहब इस सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस सरकार की कोई औद्योगिक नीति नहीं है । मैं इसी सन्दर्भ में कहना चाहूंगा—जब उनकी सरकार इस देश में सत्ता में थी, तो औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़े इलाके हैं, उन का विकास करने का उस सरकार ने फैसला लिया । फैसला लेने के बाद, प्रश्न पैदा हुआ कि विकास किस तरह से किया जाये, विकास की नीति क्या हो ? उनके पास इसका कोई मापदण्ड न होने की वजह से उन्होंने एक "नेशनल कमेटी फार दि डवेलपमेंन्ट आफ़ बैकवर्ड एरियाज" की स्थापना की, जिस के अन्दर इस देश के आइ० ए० एस० अफसरों को, ऐसे लोगों को जो हजारों रुपया तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, जो एअर-कण्डीशन्ड रूम में बैठने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों की लम्बी-चौड़ी कमेटी बनाई । इस तरह से हमारे औद्योगिक विकास के प्रश्न को आइ० ए० एस० अफसरों की गोद में, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को किसी आया की गोद में डाल दिया जाय, उसी तरह से डाल दिया गया । इस कमेटी की टर्म्स-आफ़-रेफेन्स यह थी—

To examine the validity of the various concepts of backwardness underlying the definitions in use for present policy purposes.

इस का मतलब है कि हमारे पास कोई उचित मापदण्ड नहीं था । इस कमेटी का यह काम भी था—

[श्री विलास मुत्तेमवार]

To recommend an appropriate strategy or strategies for effectively tackling the problem of backward areas.

सभापति महोदय, इस कमेटी की पिछले दो सालों में कई बैठकें हुईं । यह प्लानिंग कमीशन के अन्तर्गत आती है, जिस के बारे सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये राष्ट्रीय समिति की मापदण्ड तय करने के लिये कई बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक इस समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है । आज जब देश के सामने पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने या औद्योगिक विकास करने का कोई उचित मापदण्ड नहीं है, उचित रण-नीति नहीं है, तो हम किस तरह से इन का विकास कर सकते हैं ।

मैं उद्योग मंत्री जी तथा हमारी सदन की नेता से यह कहना चाहूगा कि उस कमेटी में हमारे जैसे संसद सदस्य एक भी नहीं हैं । जिन संसद सदस्यों का देश के मतदारों से, जनता से, डायरेक्ट कमिटमेंट है, आइ० ए० एस० अफसरों का कमिटमेंट नही होता है, हम जनता के सामने जवाबदेह हैं, इस लिये जो भी समिति बने उस में संसद के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । इस के साथ ही समिति के लिये कोई कैलेण्डर होना चाहिये, कोई समय निश्चित होना चाहिये, जिस में कि वह समिति अपनी रिपोर्ट दे दे । प्रायः ऐसा नही होता है कि समितियां निर्धारित समय में रिपोर्ट दे दें । इस समिति की भी यही स्थिति है और हमें बताया गया है कि इस की मियाद दो साल के लिये बढ़ा दी गई है । इस का मतलब है कि फिर इसकी मीटिंग्ज चलती रहेंगी और रुपया खर्च होता रहेगा ।

सभापति महोदय, मै इस सदन में पहली बार आया हू और मेरे जैसे कई युवक इस सदन मे आये हैं, जो देश के युवको का प्रतिनिधित्व करते है । हम ने इस सदन में आने के बाद एक बात देखी कि हिन्दुस्तान के उन सभी क्षेत्रों से, जिनका अभी विकास नही हुआ है, एक माग बड़े जोर-शोर से आ रही है कि पिछड़े क्षेत्रों मे रेलवे लाइन बिछाई जाय तथा जहा पर छोटी लाइन है, उस को बड़ी लाइन मे परिवर्तित किया जाय । आज उन क्षेत्रो की तरक्की के लिये जनता मे बड़ी तड़प है, उन के अन्दर अपना विकास करने का उत्साह जाग गया है । वे विकास के लिये मचल रहे हैं । यह एक अत्यन्त आशाजनक वातावरण है । इस लिये मैं उद्योग मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि रेलवे लाइनों की जल्द से जल्द व्यवस्था करायें, इस देश की औद्योगिक नीति को बढ़ाने में रेलवे लाइनो का बिछाया जाना बहुत सहयोग दे सकता है ।

हमारे मित्र--महालगी जी ने भी इसी सन्दर्भ में बोलते हुए कहा है तथा महाराष्ट्र में जो हमारी अभी नई सरकार बनी है, जिस के मुख्य मंत्री श्री अंतुले जी हैं, उनकी तरफ से भी केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रपोजल आई है कि एक नाडल ऐजेन्सी की स्थापना की जाय । जिस का कार्यक्षेत्र प्रधान मंत्री के अन्तर्गत चले । अभी यह होता है कि उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित जितने काम हैं, उन का एक दूसरे से कोई समन्वय या कोआर्डीनेशन नहीं है । उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी और रेलवे मंत्रालय के सेक्रेटरी का आपस में कोई परिचय नही है, एनर्जी विभाग के सेक्रेटरी और उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी का आपस में कोई परिचय नही है, उन का कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उस को आप सही कर दीजिए । जो तथ्य हैं, वे मैं आप के सामने रख रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट सामने आने चाहिएं, वे आ नही रहे हैं, परिणाम सामने नही आ रहे हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि कामों को एफीशियेंटली करने के लिए एक नाडल एजेन्सी की स्थापना की जाए, जो कामों को इफेक्टिवली कर सके । इस देश में उद्योगों के मामले में जो ऋण नीति होनी चाहिए, वह नहीं होती है और तकरीरें कर दी जाती है । जो हमारी टेकनोलोजी है, उस में भी क्रांति लानी चाहिए ।

जब हम इन बातों की चर्चा करते हैं तो एक बात मैं यह कहना चाहता हू कि हमारे देश के जो औद्योगिक घराने हैं, बिग बिजनेस हाऊसेज है, मोनोपली हाऊसेज हैं, वे एक तरफ तो बड़ी बड़ी मोटरें बनाते हैं और एटोमिक एनर्जी पैदा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि वे छोटी छोटी चीजें जैसे साबुन की टिकिया और नमक की पुड़िया तक बनाते हैं जो चीजे काटेज इन्डस्ट्री और कुटीर उद्योगों में बनाई जा सकती हैं लेकिन वे उन को बनाने की हिम्मत नही कर पाते क्योंकि उन को बिरला और टाटा से स्पर्द्धा करनी पड़ती है । इसलिए मैं चाहूगा कि हम एक उचित नीति अपनाए । जब हम एशिया मे जापान देश को देखते है, तो वहा के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, वे अपने देश के भीतर लोगो से मजा नही लड़ाते बल्कि वे अमरीका और दूसरे प्रगतिशील राष्ट्रो के उद्योगपतियों से वर्ल्ड मार्केट में जाकर पंजा मिलाते है और वहां उन से स्पर्द्धा करते हैं । वहा की जो काटेज इंडस्ट्री होती है, उन छोटे छोटे उद्योगों से माल लेकर वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं और इस तरह से अपने यहां के छोटे उद्योगों को मार्केटिंग की सहूलियतें वे देते हैं । इसलिए मेरा यह कहना है कि ये जो छोटी छोटी चीजें बड़े उद्योगों में बनाई जाती हैं, उन पर पाबन्दी लगाई जाए । जो सामान छोटे छोटे उद्योग और सामान्य आदमी बना सकते हैं, उन की बनाने के लिए उन लोगों को तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

इस सम्बन्ध में मैं प्लास्टिक उद्योग का भी जिक्र करना चाहता हूं । आज जो प्लास्टिक बनाने वाले उद्योग हैं, वे प्लास्टिक भी बनाते हैं और प्रोसेस का काम भी वही करते हैं । इस तरह से प्रोसेस करने वाले उद्योग का बड़ा नुकसान हो रहा है और इस से स्माल सेक्टर इंडस्ट्री को खतरा पैदा हो रहा है । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो प्लास्टिक का निर्माण करने वाले उद्योग हैं, वे प्रोसेस करने का काम न करें ।

मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, वह विदर्भ विभाग में, महाराष्ट्र में है और यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र उद्योगों के मामले में काफी आगे बढ़ा हुआ है और इस बात पर मुझे फक्र है । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पूना, थाना और बम्बई, इन तीन को छोड़ कर, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोकण और विदर्भ का क्षेत्र विकास की दृष्टि से हिन्दुस्तान के किसी भी विभाग की तुलना में उतना ही पिछड़ा हुआ इलाका है जितने और हिस्से हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है । मैं नयी इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में नहीं कहूंगा : लेकिन जिस इंडस्ट्री का सर्वे हो चुका है उसकी तरफ आप ध्यान दें । एक कोच फैक्ट्री, वेगन फैक्ट्री के निर्माण के बारे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दो साल पहले कहा था मैं उसी के सन्दर्भ में चाहूंगा कि नागपुर में उस वैगन बनाने वाली फैक्ट्री की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि उसके लिए वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

हमारे महालगी साहब ने बीमार उद्योगों के बारे में कहा कि बीमार उद्योगों की एक महामारी-सी आ गयी है । उन्होंने इसका कारण यह बताया कि रा-मैटेरियल की कमी है, एनर्जी की कमी है, फाइनेंस की कमी है, लेबर ट्रबल है लेकिन एक कारण बताना वे भूल गये कि मिल-मालिकों के आपसी झगडो की वजह से भी उद्योग बन्द किये जाते हैं । हमारे संविधान में जो निजी सम्पत्ति का फण्डामेंटल अधिकार दिया हुआ है कि किसी भी मिल को ताला लगा दिया जाए तो बहुत से उद्योग इस तरह की तालाबन्दी के कारण भी बन्द हो जाते है ।

हमारे यहां एक उद्योग है शिवराज फाईन आर्टस लिथो वर्क्स जिसमें आधुनिक मशीनरीज लगी हुई है और जिसकी ख्याति एशिया भर में है । 1959 में जवाहर लाल नेहरू जी वहां आये थे और उन्होंने वहां शिवाजी के पुतले का उद्घाटन किया था । लेकिन 6 साल से वह फैक्ट्री बन्द है । अभी हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं श्री वसंत साठे, जो मजदूरों के नेता रहे हैं उन्होंने अपने जमाने में उस फैक्ट्री के बारे में बहुत कोशिश की थी कि वह उद्योग चले लेकिन वह उद्योग अभी तक बंद पड़ा है । इस संदर्भ में भी मंत्री जी ध्यान दें ।

आज प्रश्नोत्तर काल में मंत्री महोदय ने बताया था कि औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनमें रेल लाइनें बिछाने पर विचार कर रहे है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चन्द्रपुर, नागभीड़ गोविन्दया, जबलपुर की जो रेल लाइनें हैं यह नेरो गेज रेल लाइन है । इसको ब्राडगेज में कंवर्ट करन के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास प्रपोजल आये हैं और रेलवे विभाग को भी गये हैं । हमारे चन्द्रपुर और भण्डारा में कोयला है, मिनरल हैं और बड़ी मात्रा में लकड़ी है । इसलिए इस लाइन का ब्राडगेज में कंवर्शन बहुत जरूरी है । इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा आदिवासी एरिया है और आदिवासियों के हित के लिए हमारी सरकार और हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उद्योग मंत्रालय की ओर से रेल विभाग को रिकमण्ड किया जाए कि उस नेरो गेज रेल लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाए । इस से उस चन्द्रपुर और भण्डारा के आदिवासी इलाके का विकास तो होगा ही साथ ही आंध्र और कर्नाटक से जो गाड़ियां कलकत्ता जाती है वे— अगर गोंदिया और जबलपुर हो कर जाएंगी तो साढ़े तीन सौ किलो-मीटर की दूरी कम हो जाएगी और मद्रास से कलकत्ता और कलकत्ता से मद्रास जा कर जो माल बिकता है उसके भाव भी कम हो जाएंगे ।

ये सब बातें कहते हुए मैं उद्योग मंत्री जी से कहूंगा कि वे हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, योग्य मंत्री हैं वे इन बातों पर विचार करें । हमारे जैसे युवक जो इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में इस सदन में आये हैं वे चाहेंगे कि उद्योग मंत्रालय को आप गति प्रदान करें और गति ही विकास का सार तत्व है ।

इतना बोलते हुए मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI (Banaskantha): Mr. Chairman, Sir, first of all our Industry Minister deserves congratulations because the legacy that he got was that his Ministry was completely in a mess.

The ex-Minister of Industry, Mr. George Fernandes, who spoke here yesterday very loudly talked against monopolies. But during his time, he always adopted two standards, double standard. While he was speaking and we were hearing, I just remember a dialogue by Mr. Bottom in the Mid-summer Nights Dream where a lion used to roar like a nightingale. Mr. George Fernandes, when he was Minister in charge of Industry, used to roar against big monopolists, but

[Shri Bheravandan K. Godhavi]

his roaring was so sweet to the big monopolists that they were hearing it as if it was from a nightingale. (*Interruption*). He was roaring like a nightingale, not like a lion.

14 hrs.

It is a good sign and a happy augury that, now there is a tendency for industrial growth. But let me tell you that, now, we have to start acting upon a different concept. Those poor people living in the backward areas where there is no industry are longing, are looking forward, that immediately something would be done for the development of their areas. All my learned friends have spoken about this and I also share with their concern. A Committee had been set up to identify the areas, which areas are backward. They have had a number of sittings, but still they have not given their report. After all, what have they to find? Only whether an area is backward or not. You can see with your naked eyes what are the areas which are industrially backward. When we ask why a particular area is not declared backward under the State Government or under the Central Government subsidised scheme, the reason given is that there is no infrastructure. Is it possible for a man who wants to venture into a small scale industry or a medium industry to set up the infrastructure? Is it possible for an individual to set up the infrastructure? If that is the excuse given, then let me tell you that that is not the proper thing.

In Gujarat—I hail from Gujarat—our States has asked for a petro-chemical industry to be set up there, has asked for licence. But there is no reply from the Centre. In Gujarat there is a great potentiality, there is a good scope, so many industries can come up. In today's situation when we have got a very heavy burden on agriculture—and land in not going to expand—setting up small scale and medium industries would prove to be a great relief, would provide alternative employment and woul help in uplifting the standards of living and contribute to industrial growth and national income. In this respect, what I want to emphasize is this. Let there be a better coordination between, as some of my friends have rightly said, the Railways, the Ministry of Industry and the Ministry of Energy, there should be concerted and coordinated efforts on the part of all these Ministries. Otherwise, there will be only excuses. which will be given. Why is there no power? Because there is no coal. Why is there no coal? There is no wagon. Why no wagon? Something else is not there. Therefore, we are thinking of setting up power houses near the coal fields. But that would not be applicable to industry because we have to make the entire country hum with industries, make it a beehive of industries. For that, the remotest corners of the country are to be looked upon. Now, what has been our experience? We talk a lot about industries. I do not criticise, but I just want to point this out. When small entrepreneurs go to the district unit or the State unit or to the other officers for guidance, they are not getting the proper guidance. If the technical engineers want to set up a small unit, they are not in a position to set it up because they do not get the proper data, the proper information, proper financial assistance, and so many other things. As has been rightly pointed out by some of my friends here ,the big monopoly houses are, either directly or indirectly, scuttling the growth of small scale and medium industries. So, that aspect will have to be taken care of.

Tatas, Birlas are manufacturing soap. They are manufacturing trucks also. But look at the premium on trucks. Driver is the person to whom first attention is to be given as owner-driver. But trucks are being sold with a premium of Rs. 40,000. Are we checking it? Only those people who register themselves and who have got the money get it but the poor needy people are not getting. It is only the

blackmerketeers, profiteers and agents who get it and make money out of it. Sir, something will have to be done in this regard also. I know from my constituency so many taxi-drivers are there in Bombay and so many people have applied for trucks. Their registration is there for the last 3 or 4 or 5 years but they are not getting. But if you pay Rs. 40,000 you will get it. I think the Minister must be knowing about the facts and he should do something to stop this racket.

Then, Sir, so far as petro-chemicals are conerned, I have already said and I would repeat it. The Gujarat government has asked for a licence for a petro-chemical industry. It is not yet cleared by the government of India. I do not insist that it should be exclusively on the State Government sector. Let the Centre also have a share in it. There is IPCL of Central Government at Baroda. Let there be a competition so that we may know who is working better. There should be a healthy competition in industries. This point also, I hope, the hon. Minister will bear in mind.

Much has been talked about sick units, about the tendency to make the units sick and to declare lock-outs, etc. Sir, it is surprising that those who were managing the sick units which were ultimately taken over by government, those proprietors have never gone sick monetarily. They have become fat and this aspect also should be taken care of.

Sir, I know the time is very short and a lot of things I have to say. One aspect I would tell you. There should be more emphasis given on agro-industries so that agriculture is brought in harmonious fusion with agro-industries. There is a lot of scope here and it will revitalise the rural economy which will give a great fillip and momentum to the village activities. Presently, we hear a hue and cry that there is a lot of migration to cities and there is a lot of congestion in the big cities. If we can set up agro-industries in different parts of the country and even in the remotest parts of the country, I think that the problem of great density and concertration of population in the big cities leading to so many evils would be solved to some extent. Therefore, on this point also I ask the government to take due care and pay proper attention to this question.

The Banaskantha district which I have the honour to represent here in this House is a bakward district. It should be declared a backward district and I wrote to the Prime Minister while she was in Ambaji. The reply that I got was that a committee will examine this aspect. I hope you would expedite the matter.

North Gujarat is a industrially very backward region of Gujarat State. It is said that Gujarat is an industrially well-advanced State. But let me tell you that all your industries have come up only on the two sides of the national highways or the State highways and not in the remote villages. They have come up only on the sides of the national highways just as we have got roadside planations but behind them everything is barren. But take the case of Jaisalmer or take the remotest corner like Barmer or Banaskantha. Nobody is paying any attention to those places. Sometimes it is very surprising that we talk here about a particular area, harly people here in charge know where that area is in our country. This is a sad state of affairs and sometimes we cut a sorry figure. I hope with the present government's zeal we will no longer cut any such sorry figure.

Therefore, while supporting these grants—I do not think I would be able to finish several points within the time because the bell would be rung by you and I may have to sit down—I only urge upon the Minister that he should make concerted efforts for a proper coordination between three or four ministries as they are inter-linked with this Ministry. Let there be the

[Shri Bheravadan K. Gadhavi]

bold concept; let the red carpet treatment given to big monopolies, big business, go away and let the small entrepreneurs, small people come to the office of the Industries Minister of any offices barefooted and receive equal treatment that is given to these big business men. Unless you do that, I do not think you will be able to develop the country the way in which we want to develop it. Certainly we want to see that there should be more production of essential commodities. There should be more production efforts made in that regard at a much less cost.

I hope the Minister of Industry will make his concerted efforts in this regard. He will have to look to the aspect of coal first to be sent to the areas where it is not available or where the same cannot reach within a short time to places like Gujarat, Rajasthan and other parts. We have a vast coastal area. Now there is a new concept of generation of energy from sun and waves. We have to depend very heavily on our solar energy. Atomic energy would be the alternative source of energy for this country if we want to remove poverty from this country. We all have been dedicated for this. Therefore, I would submit that all these aspects will have to be looked into by the Industries Ministry. We have seen in this Parliament the Minister's zeal and enthusiasm. So, I hope he will take due care and will pay proper attention to these.

With these words, I support the Demands for Grants of the Ministry of Industry.

MR. CHAIRMAN: Mr. Unnikrishnan. You have nine minutes.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Mr. Chairman, Sir, I am conscious of the fact that the time at my disposal is short. So, I shall confine my remarks only to some far reaching and major areas of policy and I do not want to go into many details although there is a lot of scope and provocation to do so. We are debating the Demands of this vital ministry six months after the new Government, under the leadership of the Prime Minister, Mrs. Gandhi has got a massive mandate. At this point of time, certainly, this House is entitled to know what are the contours and dimensions of the new Government's Industrial policy and the details the thrusts, of the policy.

I am conscious of the fact—I shall certainly concede—that the Minister and the Ministry certainly have not time long enough for many achievements because they have been here only for the last six months. But certainly, it is time enough to find out what exactly are the dimensions of the new policy. Also I want to emphasise on what is more important than this, that is what are the departures that they propose, or are they under way, from the basic industrial policy that this country had adopted for the last thirty years?

Now, Sir, this policy, as embodied in the Industrial Policy Resolution of 1956, if I may add, had historical roots in the freedom movement because, after the Karachi Congress of thirties, the Indian National Congress, as a National Liberation Movement, had adopted an economic perspective to which we contributed not only from that side but from this side as well. It was subsequently incorporated in the planning process and the perspective that was unfolded before the country by the late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru.

So, this Industrial Policy Resolution of 1956 is not something to be trifled with. It has a basis; it has its social roots. It answers to the needs of the country not only for the present but also possibly—I am sure at least for a few decades more to come. That does not mean that the country is at a standstill and there is no movement forward. That certainly is not the idea. That is why I am rather disturbed by the whispers, or even by the

loud talk in the corridors of power, about the changes in the Industrial Policy Resolution. That is why when spokesmen from their (ruling) party who were sitting on this side during the last two years and some of us firmly resisted the earlier attempts by proponents or exponents of ruralism to change the direction of this policy.

Now, Sir, I would particularly refer to some of the reports that have appeared in the Press. I quote from a document which has appeared in the *Business Standard* of July 18, which is called the background note for discussion between Planning Commission and the Ministry of Industry. Sir, I know that it is a high pedigreed document! I also know that there are more than national possibly even international ramifications behind this document. I am also conscious of the fact that World Bank and IMF have been demanding structural changes in the economy and there has also been correspondence and talks on this aspect.

But what I am immediately concerned with is and I quote—first, I quote Mr. Marathe:

> "Mr. Marathe said at the meeting that it might be necessary to re-examine the Industrial Policy Resolution which was prepared with different historical perspective etc....."

Afiain "Dr. Manmohan Singh also built up a case for private sector. He said that Sixth Plan would have to operate within severe resource constraint and expansion of public sector in industrial field would have to be very selective" and he added "that even there was justification for public sector not to expand in a big way." Again the note says "that the private sector is now in a position to make huge investment in areas involving sophisticated technology and where gestation period is long." Now, there are many more things to be quoted but I do not want to go into the whole note.

This then is precisely the problem. What are we trying to do in this country? Is this a drifting, mindless government or has the Minister—I concede that he is a very busy man—found time to apply his mind or has his party or leadership applied its mind to the problem? I am conscious of the fact of natural inhibitive factors on the industrial environment, *viz.*, lack of power, crisis in transportation and so on and so forth.

But with all this do you have a strategy? Have you changed the strategy? What I want to say and say emphatically is that there is a clear-cut effort to change the course of the Industrial Policy Resolution of 1956. Our strategy of industrialisation as envisaged by the planning process and Industrial Policy Resolution of 1956 was not only to raise natioanl output and achieve self-sustained growth but also to achieve even income distribution and social equality. There was also a strong case made out by the Prof. Mahanolobis Committee on concentration of income and even by Industrial Licensing Policy Committee for preventing concentration of economic power. There was a larger social purpose, as I said earlier, which emanated from the goals that the freedom movement had itself set before the nation and in the hands of Jawahar Lal Nehru new tools were fashioned and subsequently followed by the successive governments of this country. It was because of this effort and perspective that we were able to raise not only a substantial area of public sector and to achieve if not commanding heights, major heights in economy but also we created the third biggest reservoir of technological manpower in this country. This is a major and an important point which I wish to stress. It is closely related to self-reliance and self-sustained growth.

I am disturbed because I find that in many public sector organisations many of our engineers and scientists are demoralised. I thought that with the coming in of this government and with the departure of the previous government all such issues would have been settled but on the contrary I find that their morale is at a lower ebb today than at any time before. I wish to

[Shri K. P. Unnikrishnan]

say that the public sector was equally in bad shape in late sixties and early seventies but subsequently during the next 3 or 4 years they were nurtured and they were allowed to grow so that sufficient gains were achieved compared to the earlier results, after the 1971 Government took over and the gross profits from these public undertakings had gone up from Rs. 146 crores in 1970-71 to Rs. 668 crores in 1975-76, a rise of 290 per cent and a net profit of Rs. 306 crores, a rise of almost unbelievable 1400 per cent! But still we are told by the planners and the officials: I don't know what exactly they have said, but from these reports it is clear there is a move for a systematic denigration of the public sector. I don't know, whether we will go back to the primacy of agriculture which was the main theme of the Janata Government. Where do we stand? I want a categorical answer. Are you going to succumb to pressures that have developed around? Are you going to depart from the time tested industrial policy resolution of 1956 or do you want to go ahead? Now, Sir, Bharat Heavy Electricals is a prize plant which has been built up with great care. With pride I would say, it is one of the biggest achievements of the public sector in India. Their order books are getting blank today. On the contrary efforts are made for importing equipments which can be made here. And our great voluble Minister for Power said the other day— Mr. Ghani Khan Chaudhury went to the extent of saying that he "would hand over power houses to foreign experts." Sir, I was really astonished. But that is what he has been saying. He went to the extent of saying that we shall invite them to run power plants. It is a new concept. If law and order breaks down do you get policemen and experts in criminology from other countries? Because, that is what it amounts to!

Sir, there are many distortions already even otherwise in the developmental process. The Minister is not here now; he himself is an economist The first problem in the development process is the high capital intensity of the Indian industry. It used to be around Rs. 32,980 for every job in 1968 according to an ICICI study; now it may have gone up to around Rs. 48,000. But I would say capital intensity is not the only major problem, nor capacity utilisation.

But there are some inherent difficulties in the demand pattern of Indian industry. One problem which I have always been stressing is the structure of demand. People don't have the wherewithal and the capacity to buy goods produced by Indian industry, particularly in the consumer industries sector. That is what it amounts to put it in very simple terms. For example, in 1969, out of a total urban market of industrial goods which was at Rs. 1600 crores, Rs. 568 crores (or 35 per cent) were consumed by top 10 per cent of the urban rich and again out of Rs. 4600 crores worth of rural market, 10 per cent of the rural rich consumed goods worth Rs. 1724 crores or 37.6 per cent. So, this is a basic constraint of Indian industry. The constraint is the distortion in the demand structure. So, Sir, unless you have far-reaching inter-related changes in the agrarian scene like land reform, unless you are able to put money in the pockets of people there will always be these natural inhibitive factors operating in the development of Indian industry. Another point I want to stress is the question of regional imbalance. Sir, I am all for regulatory framework. This regulatory framework has a meaning and content in the context of our industrial policy. But I am not for bureaucratic controls like the price control on automobiles. How does it matter I have never understood our concern for an Ambassador car being sold for Rs. 75,000 or Rs. 80,000 which must find its own price of market level. Now whom does this price control help? Now, there is a price control on cement, may be the Government can certainly take over a portion of the production of cement. But the Government is willing to pay more money and import cement on

higher price than what it offers to the cement manufacturers here even if they happen to be the big business houses. Now, this kind of bureaucratic controls generate black money and it harms not only the economy as a whole but it brings distortions even in the levels of incomes. So, if we have to fight this, it is very important that they do have a look at the regulatory frames work but keeping in mind the basic perspective of Industrial Policy which cannot be, as I said earlier, trified with.

Now, Mr. George Fernandes, talked about the monopolists and multi-nationals. On the question of multi-nationals very often it is said that even the Soviet Union has invited the multi-nationals like Fiat or Monsanto Chemicals. But the Soviet Union after 40 years of socialist revolution and development has acquired a rich capital base with powerful technology and material base which can absorb foreign technology without damaging or changing the essential features of its economy. But we has not here in this country so far reached the point where we can afford a large infusion by multi-national participation unless you want an export led growth. I know there is a pressure. The world Bank is demanding structural changes in the economy. But, Sir, as I said earlier, self-reliance has been our goal, self-reliance can only be sustained over a period of time, if we adopt policies where our own engineers, our own designers, our own scientists have a key role to play in national economy, particularly in the Heavy Industry sectors. But what do you find today? You find that whatever design organisations we have built up, we are trying to pass it back to the private sector, that too multinationals. It is very relevant here because I want to make this known to the House. I am glad that the Minister for Petroleum is here.

Now, there is the Fertiliser Corporation. In the Research and Design Wing we have many brilliant engineers and in the FEDO Design Wing of FACT also they have handled and designed 7 or 8 fertilizer plants. Nearly 95 per cent of this was wholly designed by these men. Now, I find that they are jobless because the new urea plants that we want to establish, I am told, have been handed over to SNAM PROGETTI and Ammonia plants to American multinationals. I do not know whether it is in this way we are going to develop if for marginal advantages we invite multinational technology. You can always argue on this. But what happens to these men? As Mr. V. N. Gadgil pointed out the other day about H.A.L. it is affecting the entire area of industrial production and activities. There is a backslide from our cherished goals and policy of self-reliance. Now, the basic question is the policy you want to adopt. You cannot at this stage of development, I would contend, adopt any other policy than what we had followed. I am not here suggesting that the same control which was necessary yesterday should be continued today. It is very important.

I was a little surprised at the Finance Minister's announcement during the budget when he had allowed and had given a blanket guarantee to big business that even if we put money from the public financial institutions, we shall come nowhere near you. No Minister had ever said this before; that was not a part of the policy. The convertibility clause has a serious impact. Whatever maybe the argument, you are saying that you would not come anywhere near them. On the other hand, you say that you shall take over every sick undertaking. Recently in this House on 23rd March, the hon. Minister for Industry who is absent now, had said that he would take over Kumar Dhubi Engineering Works. He had given an assurance but now I am told that it is being handed over back to the private sector. I would conclude by saying that it is time for people to realise that there cannot be any departure from the basic postulate that we had adopted.

श्री महादीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगो के समर्थन में खडा हुआ हूं जोकि केवल आर्थिक विकास की आधारशिला ही नही है बल्कि हमारे सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, वैज्ञानिक विकास, रक्षात्मक विकास और आत्मनिर्भरता के आधार पर प्रभावित वैदेशिक नीति की भी आधारशिला है । किसी भी देश की औद्योगीकरण की नीति को देखने के लिए कि वह कहा तक सफल रही है, हम उस की सफलता को तभी देख सकते है जबकि हम यह देखें कि विकास की दर क्या रही है, औद्योगिक विकास की गति क्या रही है । इस संदर्भ में हम को भारत की विकास दर को तीन अवधियो के अन्दर देखना होगा । पहली है 24 मार्च 1977 से पहले की अवधि, फिर 24 मार्च 1977 के बाद और जनवरी 1980 के बीच की अवधि और तीसरी है जनवरी 1980 के बाद की अवधि । इस प्रकार जब हम देखते हैं तो इस माननीय सदन मे बहुत से माननीय सदस्यों ने आलोचना और समालोचना की है । इस बारे मे सदस्यो ने तरह तरह की बातें कही हैं । हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने कहा है कि उनकी सरकार के जमाने मे उद्योगो में काफी प्रगति हुई है । मै केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर यह कहना चाहता हू कि अगस्त 1979 मे यह हम देखते हैं कि जो सूचक अक था, वह अन्तिम छ माही के अन्तर्गत 0 6 प्रतिशत था जबकि उसी अवधि मे सन् 1977-78 के बीच मे वह 7 7 प्रतिशत था । इस तरह से औद्योगिक विकास की जो गति रही है, उद्योगीकरण की जो दर रही है, वह हम देखते है कि इस के पहले अर्थात जनता पार्टी की सरकार जब पदारुढ़ हुई, उस के जमाने में औद्योगिक विकास की प्रगति में कमी आई है । इसलिए हम यह मानते हैं कि कल जो हमारे माननीय जार्ज फर्नान्डीज, जो यहां पर बहुत जोरो से औद्योगिक नीति के बारे में बोल रहे थे, आज वे इस माननीय सदन में हमारी बात सुनने के लिए नही आए हैं, उन के जमाने मे औद्योगिक विकास में कमी आई थी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि जहां तक भारतीय औद्योगिक विकास का सवाल है, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विकास की गति में वृद्धि हुई थी और हम औद्योगिक उन्नयन की तरफ जा रहे थे लेकिन जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन में औद्योगिक विकास पीछे गया है, उस की अधोगति हुई है ।

हम इस चीज को दो पक्षों में देखना चाहते हैं । एक भारी उद्योगों की नीति और दूसरी लघु उद्योगों की नीति । माननीय सदस्यों ने यहा पर भारी उद्योगों में सारी संरक्षण की बात कही है । जो भारी उद्योग चलते हैं, उन में क्या हमारी सरकार ने मदद की थी ? और ढाई वर्ष की जनता पार्टी की अवधि में उसने क्या खर्च किया था ? मान्यवर जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो 1976-77 की अवधि में 32 सौ करोड़ रुपया भारी उद्योग में खर्च किया गया था लेकिन मान्यवर चालू वित्तीय वर्ष में जब से कि समाजवादी व्यवस्था के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई है उस सरकार ने इस पर 50 सौ करोड रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है । इस से मन साफ हो जाता है कि हम भारी उद्योग में कहां जा रहे है ।

मान्यवर हम लघु उद्योगो को भी आगे बढाना चाहते है । इनमे विश्व के मान चित्र मे अपना एक अलग मानचित्र बनाना चाहते हैं । मै समझता हू कि भारी उद्योगों और लघु उद्योगों दोनों का समन्वय हो और दोनो के समन्वय से ही हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं । इसी तरह से हम समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं । इसी संदर्भ मे मैं जार्ज साहिब से पूछना चाहता हूं जो कि अपने को समाजवादी नेता मानते हैं और जो कि दो वर्ष तक उद्योग मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने अनुसूचित जातियों और जन जातियों के आरक्षण पर के प्रश्न पर क्या किया ? दो वर्ष तक वे उद्योग मंत्री रहे और उन्होंने भारी उद्योगों में इन लोगों के आरक्षण के लिए कुछ भी नही किया मान्यवर आप जानते हैं कि जब हमायूं बादशाह हार कर जा रहा था तो भिश्ती ने उसे नदी पार कराया, उसने उपहार में 24 घंटे शासन का अधिकार दिया । इस पर उसने चमड़े का सिक्का 24 घटे के अन्दर ही चला दिया था । वह चमड़े का सिक्का आज भी देश के अजायबघर मे रखा हुआ है । मैं जार्ज साहब से जानना चाहता हूं जो इस तरह से हरिजनो और गिरिजनो के रोजगार की बात कर रहे है, उन्होंने अपने काल में उनके लिए क्या किया ?

मान्यवर, मै आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में 1978 में कुल 7410 कर्मियो में से 1106 और 377 कर्मी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे । यह सारी भर्ती का 14.9 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है । 1978 में 1977 की तुलना में 1.68 प्रतिशत की कमी हुई । क्या इस प्रकार से व इन लोगों को रोजगार देने की बात इस माननीय सदन में कर रहे थे ? मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय जार्ज साहब दो-ढाई वर्ष तक उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने हरिजनों और गिरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के आरक्षण को कभी पूरा नही किया । मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भारतीय संविधान में उद्घोषित 18 प्रतिशत उनका आरक्षण है उसको वे पूरा करें ।

मान्यवर, बहुत संक्षेप में मैं लघु उद्योग के बारे में भी कहना चाहता हूं । भारत गांवों का देश है और यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में

निवास करती है । लेकिन मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान किया है जिससे ग्रामीण अंचलों में रोजगार देने के लिए व्यवस्था हो सके । इससे 146 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिला गोरखपुर में एक बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र है जिसको हम सभी जानते हैं और उद्योग मंत्री भी जानते हैं यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मान्यवर, किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तम जलवायु, कच्चा माल, श्रम, आवागमन के साधन, उचित जमीन, पूंजी तथा सरकारी संरक्षण होना बहुत जरूरी है । इसी आधार पर मान्यवर बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र में दो-तीन वस्तुओं के लघु उद्योगों के आधार पर भारी उद्योग स्थापित कर सकते हैं ।

मान्यवर, आप भी जानते हैं और शास्त्री जी भी जानते हैं हमारे निर्वाचन क्षेत्र में चौरीचारी एक स्थान है जहां पर पूर्वांचल के बीसों जिलों का चमड़ा इकट्ठा किया जाता है लेकिन आज तक वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं खोला गया । मान्यवर, इसी प्रकार से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड जो बना हुआ है, उस आधार पर देश के अन्दर कागज, लुगदी अखबारी कागज के सर्वेक्षण करने के लिए एक और कारपोरेशन बने । जिससे पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जाये । उस आधार पर सोचें तो एशिया महाद्वीप में सब से बड़ी मिल हमारे यहां सरदार नगर में स्थापित की जा सकती है । वहां पर खोई बहुत पैदा होती है और खोई के आधार पर वहां कागज की मिल बड़ी आसानी से आप स्थापित कर सकते हैं ।

मैं यह भी चाहता हूं कि विद्वान उद्योग मंत्री नोट करें। चौरी चौरा में चमड़े का उद्योग बड़ी आसानी से स्थापित हो सकता है । माननीय झारखंडे राय जी जानते हैं हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर तीस तीस गांवों में केवल जुलाहे ही रहते हैं या बुनकर ही रहते हैं। पचास परसेंट के करीब वहां बुनकर होंगे । मैं मांग करता हूं कि उस आधार पर गोलाबाजार में या बड़हलगंज में या कहीं और एक कताई, बुनाई की मिल स्थापित की जाए ।

मैं यह भी चाहता हूं कि आप इस सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराएं । आप कहते हैं कि आगे आगे आवागमन के साधन दौड़ते हैं, रेलवे लाइन दौड़ती है और पीछे पीछे उद्योग दौड़ते हैं । इस दृष्टि से भी मैं विद्वान उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का वह सर्वेक्षण कराएं और वहां पर जो उद्योग आसानी से स्थापित हो सकते हैं, उनको स्थापित करने के आदेश दें ।

आप ने राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम की स्थापना की है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की है, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की भी स्थापना की है । इन तीन कारपोरेशनों की आप ने जब स्थापना की है तो उनके द्वारा आप प्रत्येक क्षेत्र का सर्वेक्षण कराएं और हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों में जहां पर क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हो गया है और उसके कारण से जो क्षेत्र पिछड़े रह गये हैं, उनको आगे लाने का आप यत्न करें, वहां उद्योग धंधों की आप स्थापना करें ।

श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, समाजवादी नीतियों पर चलते हुए निरन्तर प्रगति पथ पर वह अग्रसर है। वह विश्व के बड़े-बड़े नेताओं में से एक हैं । वह देश को आगे ले जाने में पूर्णतया सक्षम हैं। मैं आशा करता हूं कि समाजवादी व्यवस्था और समाजवाद के सिद्धांतों को सामने रखते हुए आप यह सर्वेक्षण कार्य हाथ में लेंगे और वहां लघु तथा भारी उद्योगों की स्थापना करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री गंगाधर एस० कुचन (शोलापुर) : सभापति जी, उद्योग मंत्रालय द्वारा 1980–81 के लिए जो अनुदानों की मांगें हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री जी ने स्वीकृति के लिए सदन के सामने रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और इस मंत्रालय से ग्राम लोगों की जो अपेक्षाएं उनको आपके द्वारा उन तक पहुंचाना चाहता हूं।

कृषि के बाद उद्योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और भारत को करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त करके देते हैं। इस मंत्रालय का संबंध इनसे ही है। इसके विभिन्न पहलू हैं। तरह तरह के उद्योग स्थापित करना उनको सही ढंग से चलाना, उनके प्रबन्ध को देखना, करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इस मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और वह इन सब कामों को करने की क्षमता रखता है। अब इस मंत्रालय की ओर भारत के करोड़ों शिक्षित युवक रोजगार की प्रतीक्षा में, छोटे मोटे उद्योग स्थापित करने के लिए देख रहे हैं और यह भी देख रहे है कि यह मंत्रालय क्या और किस किस किस्म के उपाय करने जा रहा है। ऐसे वक्त पर इस मंत्रालय को बड़ी सावधानी बरतनी होगी और सचेतक अपनी पालिसी रखनी होगी।

ग्राम और लघु उद्योगों के लिए 1979–80 में 71.11 करोड़ की मांग की गई थी। मगर वस्तुतः सिर्फ 37.13 करोड़ ही खर्च किया गया। इसको देखकर अब 1980–81 के बजट में 40.15 करोड़ की मांग रखी गई है। जो रकम खर्च नहीं की गई और ट्रांसफर कर दी गई उसका फल यह हुआ कि उद्योगों को बढ़ावा देने में सरकार असफल रही। इससे यह भी साबित होता है कि जनता सरकार ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और इसका यह परिणाम निकला कि देश में बेरोजगारी भी बढ़ती गई। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसका पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जाए और इस योजना को कारगर बनाने का हर प्रयत्न किया जाए। जहां सम्भव हो वहां पावरलूम सैक्टर का एक भाग इसमें शामिल किया जाए ताकि शिक्षित बेरोजगारों और युवकों को अपने ही गांव में इस तरह के उद्योग स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो सके। वहां 5 हजार बस्ती के गांव में 24 यंत्रभाग, 25,000 बस्ती के गांव में 48 यंत्रभाग और 50,000 बस्ती के गांव में 96 यंत्रभाग की यूनिटें दी जायें। अनेक प्रि और आफ्टर प्रोसेस की यूनिटें 80 मील के नजदीक के एक शहर में स्थापित कर उसके रा-मैटीरियल और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध की जाये। ऐसा होने से गांव के शिक्षित युवकों की बेरोजगारी कम हो जायेगी और शहर की ओर जाने का काम बन्द हो जायेगा।

बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करके, सरकार कई इन्सैंटिव योजना लागू करके उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। यह बहुत अच्छी बात है, मगर इसको डिक्लेयर करने का मानदंड क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि कुछ राज्यों में हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ भाग और कुछ राज्यों में सिर्फ दो या तीन डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किये गये हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ चन्द्रपुर, रत्नागिरि और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हैं। मगर हम देख रहे हैं कि इन जिलों के मुख्य सिटी के आसपास ही केवल उद्योग बढ़ गये हैं, बाकी का पूरा जिला जैसा का जैसा ही पिछड़ा रह गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट के कुछ तालुकाओं का सर्वेक्षण करके पिछड़ा क्षेत्र डिक्लेयर किया जाये तो समूचे भाग का विकास हो जायेगा और प्रादेशिक असमता का प्रश्न सुलझ जायेगा।

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैन्टर के कार्य का विस्तार सही तौर से अभी होना है, उनको और कारगर बनाना पड़ेगा, और ऐसा वातावरण निर्माण करना पड़ेगा कि गांव का बेकार युवक उनकी तरफ आकर कई बार चक्कर मारने के बजाय, इस सेंटर के सभी अधिकारी बारबार गांव में जाकर सभी सुविधाएं, वित्त और यांत्रिकी समेत, उपलब्ध कराने की कोशिश करें।

क्रैडिट गारन्टी स्कीम एक अच्छी योजना है । इसका और विस्तार किया जाना चाहिये । अभी की योजनास्वरूप प्राइमरी लेबर कांट्रेक्ट सोसाइटीज को इसमें शामिल नही किया गया है । यह सोसाइटीज भी कुछ न कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिये इनको इस योजना में शामिल किया जाये तो हर गांव में ऐसी सोसाइटीज द्वारा कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ।

नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० संस्था द्वारा हायर परचेज पर मशीनरीज सप्लाई होती रहती है । इसके लिये बजट में 4.57 करोड़ की मांग है, यह बहुत कम है । इसको बढ़ाकर इस कार्पोशन को ज्यादा से ज्यादा लघ और ग्राम उद्योगों को मशीनरी सप्लाई करने के लिये कहा जाये । इसका जो प्रोसीजर है, उसमें और सरलता लानी चाहिये ।

भारत में मेज का उत्पादन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, मगर इसका उचित मूल्य नही मिल पा रहा है । मेज स्टार्च को देश मे बहुत कमी है, विदेशों में भी इसकी बहुत माग है । देश में स्टार्च का उत्पादन बहुत कम है, यह इस मंत्रालय ने भी महसूस किया है । इसको देखते हुए, इस उद्योग को बढ़ाने के लिए कुछ खास रियायतें देनी चाहियें । मेज का भाव अभी करीबन 100 रुपये क्विंटल है और मेज स्टार्च का भाव करीबन 400 रुपये क्विंटल है । यह देखते हुए इस कृषि प्रधान उद्योग का विस्तार और विकास करने के लिए खास ध्यान देना चाहिये ।

भारत की अधिकतर गरीब जनता के लिये हमारी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहले कन्ट्रोल क्लौथ की योजना शुरू की थी, मगर जनता सरकार ने अनेक बड़े उद्योगों के फायदे के लिये इसमें बड़े पैमाने पर तबदीलियां कीं । उन सबको हटाकर जैसी पहले की स्कीम थी, उसी तरह की स्कीम लागू की जाये । इसका कुछ भार डिसैंट्रलाईज्ड पावरलूम सैक्टर के ऊपर भी कुछ खास रियायतें देकर दिया जाये जिससे हर परिवार को कम से कम कपड़ा मिलता रहे ।

भारत में डिसैंट्रलाइज्ड सैक्टर में पावरलूम की संख्या 3.47 लाख बताई जाती है । मगर मेरे ख्याल से यह पांच लाख के ऊपर है । अनअथौराइज्ड पावरलूम अथौराइज्ड किये जा रहे हैं, यह पांचवीं बार किया जा रहा है । बड़ी मिलों को आटोमैटिक लूम्स के बदले में देखा जाये तो इस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम मिलता है और मिलता रहेगा । यह देखते हुए मेरा सुझाव है कि इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, उनको पूरी तरह से हटाया जाये और जो कोई यंत्रभाग लगवाना चाहता है, उसको काटन या सिल्क के यंत्रभाग लगाने की स्वतंत्रता दी जाये ताकि देश के कपड़े के उत्पादन में बढोत्तरी हो और ज्यादा पैमाने पर निर्यात भी कर सके । इतना ही नहीं, इस उद्योग को सही तौर पर स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय निगम बनाकर वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । उस उद्योग से हाथकरघा उद्योग को धोखा है, ऐसा जो कहा जाता है, वह गलत है क्योंकि प्रोडक्शन में रिजर्वेशन किया गया है और अगर उसकी इम्पलीमैंटेशन सख्त करने की कोशिश की जाये तो उसमें उलझनें पैदा नहीं होंगी ।

कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की नीति सरकार की है, यह देखते हुए इसको जो रा-मैटिरियल चाहिये, उसके लिये काटन-यार्न की उपलब्धि बढ़ाने का अभियान खास तौर पर किया जाना चाहिये । सौभाग्य से देश में दिन-ब-दिन कपास की उपज बढ़ती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में कम-से-कम 100 सहकारी कताई मिलें स्थापित करनी चाहियें और सभी मिलों की कैपेसिटी 50,000 स्पिंडल्स तक बढ़ाने के लिये,

[श्री गंगाधर एस० कुचन]

सभी प्रकार की सुविधाएं वित्तीय सहायता आदि जल्द-से-जल्द उपलब्ध कराई जायें और इसके लिये वर्ल्ड बैंक की सहायता जरूरी हो, तो उसके लिये भी हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये । इसके अलावा, ओल्ड स्पिंडल्स बदलवाने के लिये माडर्नाइजेशन प्रोग्राम बड़े पैमाने पर लाना चाहिये और वेस्ट स्पिनिंग यूनिट को 40 काउंट तक स्पिनिंग करने की जो परमीशन दी गई है, उसको कायम करके, उनको सभी वित्तीय सहायता माडर्नाइजेशन के लिये आई० डी० बी० आई० में खास सेल बनाया जाये, ताकि ज्यादा से ज्यादा काटन-यार्न की प्रोडक्शन बढ़े, कपास की खपत बढ़े और कपास उत्पादकों को उचित मूल्य मिलता रहे । इससे परस्पर सहयोग की बात बन जायेगी ।

अभी काटन यार्न की प्राईसिज़ बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं । मेरा दावा है कि जिस प्रमाण से काटन की प्राईसिज़ बढ़ी हैं, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में यार्न की प्राईसिज़ बढ़ गई हैं । उसका जो प्राइस स्ट्रक्चर बनाने का फार्मूला है, वह गलत है और उसको सही बनाना चाहिए । वर्तमान फार्मूले से बड़ी मिलों को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है । वह शीघ्र ही बन्द होना चाहिए । इसके लिए एक गैर-सरकारी कमेटी बनानी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है ।

इसके अलावा इम्पोर्टिड विसकोस स्टेपल फ़ाइबर पर अभी जो ड्यूटी लगाई गई है, वह हटाई जाये, ताकि काटन यार्न बनाते वक्त सही मात्रा में ब्लेड करने का बढ़ावा मिले और काटन यार्न की प्राइस को काबू में रखने का प्रयास किया जाये ।

पब्लिक सैक्टर का एच० एम० टी०, बंगलौर तीन करोड़ रुपये से चालीस लाख ट्यूब लाइट बनाने का कारखाना खोल रहा है । महाराष्ट्र का शोलापुर जिला, जहां से मैं चुनकर आया हूं, बंगलौर से सड़क और रेल द्वारा सीधा जुड़ा हुआ है । मेरी प्रार्थना है कि यह कारखाना शोलापुर में स्थापित किया जाये, जो हमेशा अकालग्रस्त रहता है ।

इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं । आपने मुझे इस विषय पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका भी आभार मानता हूं ।

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): Sir, I rise to oppose the Demands for Grants under the Industry Ministry. The reason for this is that the Government has failed to bring about the industrial development of the country in a planned manner. Japan and Germany were fully destroyed by war, but they were able to rebuild the industries in an organised manner in the course of 8 to 10 years. Even 33 years after independence we have not developed industries in a planned manner and there is still much to be done to put India on the industrial may of the world. We talk of the regional imbalances. We talk of carrying industries to rural and backward areas. But no satisfactory progress is made in this direction. We have not been able to decide which industries are to be in the private sector and which industries are to be in the public sector and which industries are to be in the cooperative sector. Further, we have no classification as to the industries which are to be in the small-scale and cottage sector, and which are those to be put in the large-scale sector to be produced in big

factories. We have no detailed plan as to how to make up the shortage of essential consumer goods.

Our industrial policy should be such that we will have maximum production of consumer goods at reasonable cost by a judicious use of the large resources of raw materials we have and the unlimited manpower available. We have not yet attained self-sufficiency in the production of essential commodities. By reading the report given to us, we find that there is increased production of luxury goods like beer, wine, cigarattes, cosmetics, superfine textile goods, fans, pressure cookers, etc.—Why have we failed to achieve self-sufficiency in regard to the production of essential commodities like cement; sugar, paper, edible oil, etc.?

It is a matter of regret that we have to import cement, sugar and other commodities which we can conveniently manufacture to the extent we need in our country. Regarding cement, it is very necessary that early steps should be taken to see that we produce the cement that we require very early. With regard to sugar, it is a pity that the production of sugar is going down year after year when the demand is increasing to a great extent. The cost is also going up and it is beyond the capacity of the common man to purchase sugar. The Agriculture and Industry Ministries should work in a planned manner so that the production of these essential commodities is stepped up, and the cost is reduced.

Regarding paper industry, though the production is increasing slightly, there is scarcity of paper in the market. There is lot of blackmarket in notebooks and other books that are supplied to the students. Steps should be taken to see that this artificial scarcity is removed.

Regarding automobile industry, the cost of a car is more than half a lakh of rupees. The cost of petrol is also going up. Under these circumstances, there will be greater use of public conveyance. It is reported that chassis for buses and lorries are not available. The Government should see that supply of chassis is stepped up so that we may have more buses and lorries for the travelling public. In Karnataka, the Road Transport Corporation has placed orders about a year ago for 1000 chassis. But they have hardly got 300 to 400 chassis. To meet the demands of city and mofussil passengers and goods transport, special efforts will have to be made to produce chassis for buses and lorries.

Regarding textile industry, sick textile mills are being taken over. There is a huge liability on most of the sick mills. In these mills, most of the machinery is obsolete. It will be better if sick mills are taken over before they are beyond repairs. Steps should be taken to see that the liabilities of these sick mills are discharged and that the obsolete machinery is replaced by efficient modern machinery.

Regarding silk industry, there is a big scope in developing sick industry. If this is developed in an organised manner, it can provide employment to lakhs of people and we can earn large foreign exchange. In Karnataka, there is disturbance in the silk production and trade after the silk exchange law is brought into force. Because of this, the weavers and twisters are put to hardship. I urge upon the Central Government to take early steps to see that this valuable industry is made to run on sound lines.

The decision to shift the Khadi and Village Industry to the Department of Rural Development is not a wise decision. The Industry's Department has got the machinery to carry on the development of industries. The Industry Department could have taken over the Rural Development Corporation and then it could have seen that this institution worked in a better way. Simi-

larly, the technical department in DGTD for drugs is looked after by the Technical Wing in the Chemical Department This duplication should be avoided.

Regarding DGTD registration of drug industry, it is to be on the same line as that of other industries. For want of time, I am unable to give details of the drug industry. But I have certain problems. I will give the notes to the hon. Minister and I am quite sure that he will take suitable action in this regard.

In conclusion, I would say that the Government should see that we attain self-sufficiency in essential commodities. It is also necessary to check the rush of rural population to cities. The Government should take immediate steps to start industries in rural areas so that the growth of cities may be limited to a considerable extent.

15.00 hrs.

MR. CHAIRMAN: Before me there is a list consisting of 35 names from the Congress (I) party and there are 5 or 6 Members from the Opposition side to speak. May I request the Members to make only the salient points and finish their speeches, specially from the Congress (I) party, each in 5 minutes' time so that all Members would be able to speak.

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि उद्योग मंत्रालय एवं माननीय उद्योग मंत्री को इस समय औद्योगिक नीति निर्धारित करने में जो कठिनाई का अनुभव करना पड़ा होगा वह सभी सदस्यों की जानकारी में है, क्योंकि जनता, लोकदल शासन से हमारी सरकार को एक बिगड़ी हुई दुर्व्यवस्थित औद्योगिक नीति विरासत में मिली है और इस परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक नीति निर्धारित करने में हमारे योग्य माननीय उद्योग मंत्री ने जो दूरदर्शिता तथा जिम्मेदारी का निर्वाह किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र है ।

हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जो कि निरन्तर औद्योगिक प्रगति के पथ पर जा रहा है। इस दिशा में सफल औद्योगिक इकाइयां हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान कर सकेंगी। हमारे देश में इस समय मुख्यतया भारी, मध्यम एवं लघु उद्योगों की स्थापना की गई । इसके अलावा उद्योगो की प्रगति सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में सरकार की ओर से की जा रही है। देश में भारी उद्योग लगाए जाने अत्यन्त आवश्यक है। इनके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्य एवं लघु उद्योग भारी उद्योगो की दौड़ मे अपेक्षित न रह जायें। इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता है कि हमारे देश में लघु उद्योगो को पूरा सहयोग यानी वांछित सहयोग न मिलने के कारण वे उपेक्षित है। और मै तो यह भी कहूंगा कि लघु उद्योग आज देश मे सिसकती हुई दशा मे विद्यमान है। इस सम्बन्ध मे मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि भारी एवं मध्यम उद्योगो तथा लघु उद्योगों का कार्य-क्षेत्र अलग अलग विभाजित कर दिया जाए और इस प्रकार के उद्योगों के लिए अलग अलग धनराशि निर्धारित की जाए जिससे कि लघु उद्योगों की प्रगति में किसी कारण धन एवं साधनों का अभाव न हो सके।

मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारा प्रदेश 56 जिलों में विभाजित है जनसंख्या अधिक है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, उद्योग लगाने के लिए क्षमता विद्यमान है और अगर प्रयास किया जाए तो उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक केन्द्र बनाया जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग कारखानों को चलाने मे उपेक्षा

की गई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको मथुरा सिलिकन सेरेमिक्स काम्प्लेक्स के बारे में बतलाना चाहूंगा। इसकी स्थापना सन 1976 में की गई थी और पैकेज असिस्टेन्स स्कीम के अन्तर्गत अनेक प्रकार से साधन उपलब्ध कराने का वादा किया गया लेकिन वे सब वादे पूरे नहीं किए गए। (व्यवधान) थोड़ा सा समय और दिया जाए।

उद्योग चलाने के लिए पैकेज असिस्टेन्स की जो स्कीम रखी गई, मैं समझता हूं जिस उद्देश्य से वह निर्धारित की गई वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल धोखे की नीति निर्धारित की गई। उस क्षेत्र में भी उनको सहयोग नहीं दिया है। उनको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल डिफ्रेंशियल कारपोरेशन के माध्यम से देने का जो वायदा किया गया था, वह भी पूरा नहीं किया गया है जो कुछ कच्चा माल और रा-मैटिरीयल उनको मिलना चाहिए जैसे लोहा है, वह उनको उस मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वे बिगड़ी हुई स्थिति में पड़े हुए हैं और उद्योग मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से उनको वह माल ब्लैक में मिल जाता है, इस तरह से वे अपना काम चला रहे हैं।

बिजली का जहां तक सवाल है, वह भी उनको पूरी तरह से नहीं मिली है और इसके बावजूद भी उनसे न्यूनतम चार्जेज वसूल किए जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र बांदा जनपद के बारे में, जहां बहुत ही खनिज उपलब्ध हैं, बतलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में सिलिका सैंड काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिससे कि सिलिका सैंड की इण्डस्ट्री लगाई जा सकती है। बाक्साइट भी काफी मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे एल्यमुना उद्योग लगाया जा सकता है। इसी तरह से शजर पत्थर भी भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसका उद्योग लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में तेंदु की पत्ती भी भारी मात्रा में उपलब्ध है, जिससे बीड़ी उद्योग खोला जा सकता है।

हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में खिलौने व पत्थर का सामान बनाने के लिए काफी मात्रा में साधन उपलब्ध हैं। हमारा क्षेत्र मजदूर क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां आज तक एक भी इण्डस्ट्री खोलने के बारे में विचार नहीं किया गया, आज 30 साल की आजादी के बाद भी।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में फर्टिलाइजर का कारखाना, पेपर का कारखाना, सीमेंट का कारखाना सफलता के साथ लगाया जा सकता है।

मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि 1956 की औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और बदलती हुई परिस्थितियों में आमूलचूल और क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत गांवों में बसता है और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देश की प्रगति के लिए ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारना, गरीबी दूर करने व बेरोजगारी समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करना सरकार की सर्वोपरि नीति होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रणजीत सिंह (बतरा) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हिन्दुस्तान गांवों का देश है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग देहातों में रहते हैं। देहातों में अभी भी बहुत से लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जिस पर वे खेती कर सकें। हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करती है। इस स्थिति को देखते हुए स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हिन्दुस्तान के सभी भागों में औद्योगिकरण कर दिया जाए, जिससे हमारे गरीब और बेरोजगार नौजवान नौकरी पा सकें और हिन्दुस्तान में सभी चीजों का उत्पादन हो सके।

सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में अभी भी औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। बहुत से पिछड़े इलाकों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना नहीं की गई है। इसका एक कारण यह भी है कि हिन्दुस्तान में आज तक जो भी औद्योगीकरण किया गया है या जहां

[श्री रणजीत सिंह]

पर ग्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई है, वहां पर किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। वहां की बेरोजगारी को खत्म नहीं किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि कभी किसी उद्योग के लिए कोयले की कमी हो जाती है, कभी लोहे की कमी हो जाती है, कभी रेलवे लाइन या यातायात की सुविधायें उपलब्ध नही होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उद्योग विभाग, ट्रांस्पोर्ट विभाग, रेलवे विभाग, ग्रौर इनर्जी विभाग, इन चारों विभागों को एक साथ बैठ कर, इस समस्या का हल निकालना चाहिए ग्रौर विभिन्न स्थानो पर उद्योग लगाने के कार्य में ध्यान देना चाहिए। जिससे हमारे इलाके का विकास हो सके। मैं बिहार के चतरा क्षेत्र मे चुन कर ग्राया हूं, जहा सारे-के सारे लोग घास की रोटी खाते है, महुग्रा खा कर ग्रपनी जिन्दगी गुजारते है। वहा पर ज्यादातर ग्रादिवासी ग्रौर हरिजन लोग हैं। ऐसे पिछड़े स्थान पर न जाने क्यो ग्राज तक कोई ग्रौद्योगिक संस्थान नही है। हमारे क्षेत्र मे लातेहर एक क्षेत्र है जहां एलमुनियम फैक्ट्री लगाने का तय हुग्रा था जमीन भी ले ली गई थी, लेकिन ग्रभी तक वह फैक्ट्री नही लगी है। पूछने है तो सेन्टर कहता है कि स्टेट से कन्सेन्ट्रन मांगे जा रहे है, स्टेट कहता है कि सैन्टर से एप्रूवल नही हो पाई है। पाच-पांच वर्ष सैन्टर ग्रौर स्टेट के झगडे में बीत जाते है ग्रौर ऐसे पिछडे क्षेत्रो का कोई विकास नही हो पाता है।

सभापति महोदय, पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर, स्माल सेक्टर ग्रौर कुटीर उद्योग--ये चार महत्वपूर्ण सैक्टर्स होते हैं। पब्लिक सैक्टर मे हडताले होने की वजह से, लेबर प्राबलम की वजह से ग्रसफलता नही मिल पाती है। हमारे विरोधी दलो के लोग हमेशा वहां हड़तालें कराने में लगे रहते हैं, जिस के कारण पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है। हमारे उद्योग मंत्री का यह प्रयास होना चाहिए कि लेबर ग्रौर पब्लिक सैक्टर के बीच समझौता हो ग्रौर ऐसी नीति बने जिस से लेबर के साथ झगडा न होने पाये। इसी तरह से जो प्राइवेट सैक्टर्स हैं, जिन में टाटा, बिड़ला, मफतलाल ग्रौर दूसरे बड़े-बड़े लोग हैं, इन लोगों का भी यह प्रयास होता है कि पब्लिक सैक्टर डिस्टर्ब्ड रहे, जिस से प्राइवेट सैक्टर को ग्रागे बढ़ने का मौका मिले ग्रौर पब्लिक सैक्टर सफल न हो पाये। हमारी सरकार को यह चाहिए कि जो ऐसे बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, बड़े-बड़े घराने हैं जो पब्लिक सैक्टर को डिस्टर्ब करा रहे हैं, उनकी फैक्टरियों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। बिना राष्ट्रीयकरण के इस समस्या का समाधान नही हो सकता है। राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही गरीबों ग्रौर मजदूरो को रोजी ग्रौर रोटी मिल सकती है। इन बडे-बड़े घरानों के चलते हमारे देश का ग्रौद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। हमारी नीति मे परिवर्तन लाना चाहिए, जिस से पब्लिक सैक्टर ग्रौर स्माल सैक्टर को बढ़ावा मिल सके।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान गावों का देश है, जिस के 80 प्रतिशत लोग गावो में रहते हैं। वहां पर छोटी-छोटी फैक्ट्रीज ग्रौर कुटीर उद्योगो का निर्माण होना चाहिए। बहुत से लोग छोटी-छोटी फैक्ट्रीज में ग्रपनी पंजी लगाते हैं, लेकिन सब बेकार हो जाता है, इस का कारण यह है कि इनर्जी विभाग से उन को पर्याप्त बिजली नही मिल पाती है, वोल्टेज की कमी होती जाती है, लेबर की प्राबलम पैदा हो जाती है ग्रौर एक सब से बडी समस्या मार्केटिंग की है। वे लोग मार्केट मे ग्रपना सामान बेच नही पाते हैं। इस के लिए सरकार को मार्केटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए ग्रौर बडे-बडे उद्योगपतियों पर यह रोक लगानी चाहिए कि वे छोटे-छोटे सामान को जिन को स्माल सैक्टर मे बनाया जा सकता है, न बनावे।

हमारे इलाके में बहुत सी शुगर की फैक्ट्रीज बीमार पडी हुई हैं। हमारे उद्योग मंत्री का ध्यान इस तरफ नही जा रहा है, जब कि चीनी ग्राज 8 रुपये किलो बिक रही है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि सभी शुगर मिलों को सरकार ग्रपने हाथ में ले ले, इस से समाज का कल्याण होगा ग्रौर गरीबों को रोजगार मिलेगा।

हमारे इलाके में ग्रबरक, मैगनीज, यूरेनियम, फायर-क्ले ग्रौर तरह तरह की फोरेस्ट-प्रोडयूस मिलती है। यह सब सामान जगलों में पड़ा हुग्रा है। ग्रगर वहां पर इन चीजों के कारखाने लगाये जांय तो वहां के हरिजनों ग्रौर ग्रादिवासियों को रोजगार

मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर पेपर फैक्ट्री लग सकती है, फायर-क्ले की फैक्ट्री लग सकती है, एलमुनिया की फैक्ट्री लग सकती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरफ सरकार ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। चतरा जैसे क्षेत्र में जहां 6 कांस्टीचूएन्सीज हैं —बाराचट्टी, सातेहर, पांकी, चतरा, इमामगंज और फतहपुर— इन सभी स्थानों में आज तक कोई इण्डस्ट्री नहीं बैठाई गई है। स्टेट और केन्द्रीय सरकार आपस में कमेण्टस ही मांगते रहते हैं। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे चतरा क्षेत्र की तरफ ध्यान दें और उस इलाके में पेपर फैक्ट्री तथा एलूमिनियम फैक्ट्री का शीघ्र से शीघ्र निर्माण करायें।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि गया में एक नाइलोन फैक्ट्री बनाने का प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव को बने हुए पांच वर्ष हो गये हैं, जमीन का आवंटन हो गया लेकिन अभी तक स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच में कमेंटस चल रहे हैं और इस वजह से वह बेकार पड़ी हुई है और काम नहीं हो रहा है। इस कारण वहां के नवयुवक भी बेकार पड़े हुए हैं और उनको रोजी-रोटी नहीं मिल रही है। जब ऐसी स्थिति है तो एक विस्फोट हो सकता है और जो हमारे सिद्धान्त हैं और जो हमारी सरकार का विचार है सभी को आगे बढ़ाने का 20 प्वाइण्ट आर्थिक लक्ष्य के अन्तर्गत, आज औद्योगिक विकास न होने की वजह से सारे का सारा बेकार पड़ा है।

इतना कहते हुए मैं आप को धन्यवाद देता हूं और इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी): सभापति जी, इस देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में और आजादी के क्रम में तथा आजादी के बाद औद्योगिक नीति के पांच पहलू उभर कर सामने आए थे। पहला था एण्टी-मल्टी-नेशनल, दूसरा एण्टी-मोनोपली, तीसरा राजकीय क्षेत्र का विस्तार और कमांडिंग हाईट्स तक उस को पहुंचाना, चौथा था स्माल स्केल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन तथा प्रोटेक्शन देना, और पांचवां था समाजवादी मुल्कों के साथ दोस्ती कर के औद्योगिकरण करना, लेकिन आज जो हो रहा है और जिस बात की बहुत जोरदार चर्चा अखबारों में आती है और तमाम अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं, तमाम नीति जिस को श्री जवाहरलाल नेहरू और देश ने स्वयं आजादी की लड़ाई के बाद जो अनुभव थे, उन अनुभव के आधार पर बनाया था, उस नीति में न केवल छेद किया जा रहा है बल्कि उस को उलट कर रिवर्स गियर में काम करने का प्रयास किया जा रहा है और इस बात का बहुत प्रचार किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, उस के पास कार्यकुशलता है, उस के पास एकमीपार्टीज हैं और उस के पास मेनेजीरियल कैपेसिटी है और उस को बढ़ावा दिया जाए और इस से राजकीय सेक्टर को काफी घाटा हो रहा है। राजकीय सेक्टर की जगह पर जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की नीति चल रही है, यह न केवल देश की आजादी के लिए ही बल्कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए भी भयंकर खतरा है और इस बात का जो प्रयास चल रहा है और औद्योगिक मंत्रालय को सेबोटेज करने की बात हो रही है, मैं उस का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन नीतियों पर चल कर अगर आप यह सोचते हों कि इन से देश का औद्योगिक विकास होगा, तो यह मंत्रालय का एक दिवा-स्वप्न है क्योंकि हम ने यह देखा है कि जो मुल्क आजाद हुए हैं और जिन्होंने मल्टी-नेशनल्स को अपने देश में औद्योगिक विकास के लिए बुलाया है, उस का नतीजा क्या हुआ है, वह सब जानते हैं। उन्होंने वहां के जनमत को, वहां के अर्थतंत्र को अपने बस में कर लिया है और उन सब पर मल्टी-नेशनल्स हावी हो गये हैं और हावी होने के बाद वहां की राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और तमाम दूसरी आजादी को वे निगल जाते हैं। यह सब मल्टी-नेशनल्स की कार्यवाहियां हैं और माननीय सदस्य हम को जो कह रहे हैं वे अपने दिल में महसूस करते होंगे कि यह बात है या नहीं। इसलिए ये जो आप की नीतियां हैं, इन को आप को बदलना चाहिए। चाचना जी, जो हम लोगों के बीच मंत्री बन कर आए हैं, वे नवयुवक हैं और हम यह सोचते थे कि वे हमें कुछ प्रेरणा देंगे और कुछ करिश्मा कर के दिखायेंगे लेकिन औद्योगिक विकास में कोई करिश्मा कर के उन्होंने नहीं दिखाया है बल्कि उस में कुछ ह्रास हुआ है। आज हम यह देखते हैं कि सारा पूंजीवाद भयंकर संकट में है। अमेरिका में संकट है, पश्चिम जर्मनी में संकट है,

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

जापान में संकट है, इटली में संकट है और फ्रांस में संकट है और उस संकट में बंधे हुए सर्वतंत्र में इण्टरनेशनल मोनोपोली फण्ड और वर्ल्ड बैंक की सहायता से या हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों की सहायता से आप कुछ करना चाहते हैं, तो यह असंभव बात है। आपने हिन्दुस्तान के चीनी मिल मालिकों को किसी न किसी रूप में करीब 6 हजार करोड़ रुपया मुनाफे का दे दिया है फिर भी आज चीनी की हालत क्या है। आज देश में चीनी 8 रुपये किलो बिक रही है। क्या लाभ हुआ इस से देश को? जितनी भी चीनी मिलें महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में हैं और प्राइवेट सेक्टर में हैं वे तमाम की तमाम चीनी मिलें पिसी-पिटी हैं। रिनोवेशन के नाम से सरकार उन्हें सरकारी ऋण देती है, राष्ट्रीयकृत बैंकों से उन्हें ऋण दिये जाते हैं। वे उनका इस्तेमाल रिनोवेशन में नहीं करके अपने दूसरे प्रतिष्ठानों में करते हैं। उन प्रतिष्ठानों में भी विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों की यह बराबर मांग रही है कि तमाम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। पब्लिक सेक्टर के कारखानों में कुछ खामियां हैं, नौकरशाही का बोलबाला है। लेकिन फिर भी यह न हो कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में जितनी पूंजी लगी हुई है, और राजकीय क्षेत्र में जितनी पूंजी लगी हुई उसके अनुपात में प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा काम लोगों को राजकीय क्षेत्र में मिलता है। बहुत सारे राजकीय क्षेत्र के उद्योग आज ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि वे काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजकीय क्षेत्र को खत्म करने की दिशा में जो काम हो रहा है वह नहीं होना चाहिये। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमारा भेल कारखाना जो टरबाइन बना सकता है लेकिन बिजली बोर्डों को आदेश दिये जा रहे हैं कि बाहर से टरबाइन आयात करो। यह भेल जैसे देश के मूल उद्योगों के साथ विश्वासघात है। क्या उन टरबाइनों को भेल नहीं तैयार कर सकता है? क्या उन टरबाइनों को देश में ही नहीं बनाया जा सकता है। फिर क्यों ये टरबाइन बाहर से मंगाये जा रहे हैं। जो काम हम अपने देश में कर सकते हैं, राजकीय क्षेत्र में कर सकते हैं वे काम आज प्राइवेट कम्पनियों को दिये जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं। आप लोग जनता पार्टी, लोकदल पार्टी खूब कहते हैं लेकिन कार्यवाही क्या चल रही है? 1974 से मल्टी नेशनल कम्पनियों को हिन्दुस्तान में बढ़ावा दिया जा रहा है। आज में और जार्ज साहब में क्या फर्क है? पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 में जो औद्योगिक नीति चली थी, आज 1980 में उसको विकृत किया जा रहा है। वह नीति इसलिये बनी थी जिससे कि देश में तेजी से औद्योगिक विकास हो। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, नहीं तो मैं आप को बताता। मल्टी नेशनल कम्पनियों से देश का औद्योगिक विकास करना मात्र दिवा स्वप्न होगा। इससे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है।

इसके बाद मैं बिहार की समस्याओं पर आता हूं। हमारा बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे बिहार में 40 फीसदी खदानें हैं और उनमें जो जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उन्हें मैं गिनाऊंगा नहीं। उन खनिज पदार्थों के मिलने के बावजूद अभी तक बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उसके विकास में बाधा आपकी दे डाली है। हमारे यहां खनिज पदार्थों की रायल्टी का भी सवाल है। वहां के खनिज पदार्थों के लिये रायल्टी हमें वेल्यू में मिलनी चाहिये जबकि दी जाती है वेट पर, वजन पर। बिहार को रायल्टी वेल्यू पर मिलनी चाहिये।

इसी प्रकार से बिहार में जितने उद्योग हैं उनके हेड क्वाटर या तो कलकत्ता या बम्बई में हैं। वे हेड क्वाटर बिहार में ही क्यों नहीं हो सकते जिससे कि बिहार को फायदा हो। मेरी जोरदार मांग है कि वे हेड क्वाटर बिहार में ही होने चाहिये।

बिहार में नई कारखानों के खोलने के लिये आपके पास आवेदनपत्र पड़े हुए हैं। किशनगंज में एक जूट मिल खोलने के लिये भी है जिसकी कि

आपने कोई सुनवाई नहीं की। अल्युमिनियम कैमिकल पदार्थ का कारखाना कटिहार में खोलने के लिये महीनों से आपके यहां फाइल पड़ी हुई है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है पटना में गैस प्लान्ट खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिनिस्ट्री आफ एनर्जी में बोटलनेक की वजह से वह नहीं हो पा रहा है।

मै यह भी कहना चाहता हू कि नाइट्रोबेंजाइन एनिलीन तथा नाइट्रिक एसिड बनाने की इजाजत मैसर्स कोमरिया कैमिकल्ज को 1979 में दे दी गई और राजन प्रोप्राइटर को पटना में इस कारखाने को स्थापित करने नहीं दिया गया। यह बहुत ज्यादती हुई। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

पैट्रो कैमिकल्ज की बात भी अभी की गई है। मैं उसका समर्थन करता हूं। पैट्रो कैमिकल्ज पर आधारित उद्योग बिहार में भी खोले जाने चाहिये।

बिहार में चम्पारन जिले में रामा कास्टआयरन में करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। वह उद्योग दो साल हो गये हैं बन्द पड़ा है। मैं ने इस प्रश्न को यहां भी उठाया था और आपको भी इसके बारे में लिखा था। आपका कोई जवाब नहीं आया। आप इसको खुलवाने का प्रयास करें। मैं टेक ओवर या नेशनलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप इसको खुलवाये। इसकी वजह से हजारों मजदूर बेकार फिर रहे हैं। इसको आप दुबारा खुलवाएं।

और भी उद्योग हैं जिन की स्थापना आप बिहार में कर सकते हैं। चम्पारन में अनेक बटन बनाने के कारखाने हैं। बटन सीप से बनते हैं। सीप हिन्दुस्तान में बहुत कम जगह मिलता है। चम्पारन में बहुत ज्यादा मिलता है। किन्तु उसके लिये मार्किट नहीं मिल रही है, सरकार इस उद्योग को प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। मैं चाहता हूं कि बटन उद्योग को सरकार वहां बढ़ावा दे, उसको वहां प्रोत्साहित करे।

किशनगंज में जूट मिल की योजना है। वह वहां स्थापित होनी चाहिये इसी तरह से बाराचकियां जूट का बहुत बड़ा सेंटर है, इसको सब जानते हैं। वहां भी एक जूट मिल खुलनी चाहिये। कांटी में थर्मल पावर प्लांट आप लगा रहे हैं। जार्ज साहब के निर्वाचन क्षेत्र में वह पड़ता है। बहुत कोशिश की है तब जा कर इसको मंजूरी मिली है। भेल को इसको बनाने का काम सौंपा गया है। काम बहुत ढिलाई से चल रहा है। पता नहीं किन कारणों से वहां के जनरल मैनेजर को जो एक बहुत अच्छे और कुशल जनरल मैनेजर समझे जाते थे बदल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस प्लांट को आप जल्दी लगाये और इस काम में प्रगति की रफ्तार को तेज करे।

बिहार में बुनकरों की समस्यायें है, बीड़ी मजदूरों की समस्यायें हैं उन पर भी आप ध्यान दें।

SHRI Y. S. MAHAJAN (Jalgaon): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Industry. This Ministry has, under its supervision and regulation, a large part of the Public Sector Enterprises which account for a total investment of Rs. 960 crores and which employ about 1,60,000 persons.

The general industrial situation during the year 1979-80 had been gloomy. Though industrial production recorded an increase of 7.6 per cent in 1978-79, it deteriorated sharply in 1979-80. The overall growth during the year will be marginal or near zero. This is largely due to a decline of about 1.5 per cent in the manufacturing sector.

The causes of this decline are obvious, merely, poor performance, of infrastructure, strained labour relations and other managerial problems.

While considering the activities planned by the Ministry during the current year, I would like to emphasise the importance of the public sector. Sir, as on 31-3-79, the total investment in the industrial and commercial public enterprises of the Central Government had reached the level of Rs. 15,602 crores, consisting of Rs. 7,801 crores as equity and an equal amount of Rs. 7,801 crores as long term loans and covered in all 176 enterprises. The turnover of these enterprises was as big as Rs. 18,936 crores.

The public sector should be strengthened and expanded to capture the commanding heights of the economy, so that the transition to a socialist economy should not be a longdrawn out affairs. This sector has certain definite social and economic objectives. Not only does it lay down the foundations of an industrial state but it is also meant to provide a model for labour-management relations, correct as far as possible, the inequalities of regional development and promote industrialisation generally.

Because of the social obligations these industries should not be judged by the profit and loss method

[Shri Y. S. Mahajan]

but this does not mean we should neglect the financial results of their working because ours is a country where capital is scarce and we have to rely sometimes on foreign sources for the setting up and development of modern sophisticated industries. This point was made clear by our Prime Minister in 1970 when she was answering the debate on General Budget in March 1970. She said:

> "We do want our public sector to make profit but let us not forget that the public sector has another important objective, the building up of the infra-structure of the economy. The metallurgical, heavy engineering and heavy electrical units in the public sector are designed for this purpose."

Sir as regards these industries, they have been suffering from under-utilisation of capacity during the last three years. Admittedly, it is difficult to define capacity and various phrases have been used, various devices adopted to get over the difficulty such as using phrases like rated capacity, installed capacity, developed capacity or attainable capacity. In any case the capacity or rated capaity of a unit would depend on the number of shifts, whether it produces one commodity or a variable combination of different commodities. From the statistical information provided by the Bureau of Public Enterprises the number of manufacturing units in the public sector where capacity utilisation has been more than 75 per cent decreased from 76 in 1976-77 to 62 in 1978-79. The number of units recording less than 50 per cent capacity utilisation increased from 17 to 27 in 1978-79. The position does not appear to have improved in the last year and no exact figures are available. A crippling factor has been utter inadequacy of coal, power and transport during the last year. Attention is urgently needed to improve the working of the intra-structure. It is a matter of satisfaction that Government has already taken a number of steps in this direction. Implementation of project planning is so deficient that there is often a delay of three to four years in completing the projects with the result that the costs escalate hugely and these units become a tax burden on the millions of our people in the country.

Sir, these large and heavy industries are a base for the development of small scale industries. The small scale industries have a large employment potential. They require less capital. They can be located in any part of the country and therefore, are most suited to the development of backward areas. But, Sir, this sector is often sick and quite often a large number of units are closed down. For instance, in my State it is reported that a number of small scale units do not get even 50 per cent of steam coal or coke for their use. Some of the foundries do not get even two-fifth of the pig iron that they require for casting purposes. Distribution of these raw-materials is in the hands of Central agencies. It will be advisable to establish a coordinating agency where representatives of different States can be brought together so that distribution can be made more fairly and the requirements of these people be met in time.

As regards my State there is another problem. Our Government has taken over three textile units under the Industries (Development and Regulation) Act. It has invested large amounts with a view to bring them all back to normalcy. And now the time has come to nationalise those industries. But the Central Government has suggested that some other alternative should be considered such as merger, amalgamation, or assistance and help from other sources, etc. Sir, nationalisation is the proper remedy. In the present social and economic conditions of the country, nationalisation should be restored

to on a larger scale than what we have done so far. With these words I conclude my speech. I wish the Ministry all success.

MR. CHAIRMAN: The original plan was that the hon. Minister will reply at 3.30. But now I have got a list of 44 members given to me by the Congress (I) party. There are about 7 members from the Opposition side to speak. So, unless we extend the time, it is not possible. If we extent the time, the debate could go on till 5-30 or 6. But in that case the House will not be able to discuss the Demands of the Petroleum Ministry. What do you suggest? Shall we continue with this discussion? What is the sense of the House?

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): Instead of taking up the Ministry of Petroleum and Chemicals for one hour, it is better if we continue with this discussion on Industry.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Let there be some cut on the number of speakers on these Demands. Let us spare some time at least for the Petroleum and Chemicals Ministry.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): No, Sir, it is better to continue with this discussion till 6 O' clock.

MR. CHAIRMAN: All right, if the House agrees, we shall continue with this. I and we will forego the discussion of the Petroleum Ministry.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्री इन्द्र राज शास्त्र (फर्रुखाबाद) : सभापति महोदय, बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जो अभी तक किसी विषय पर नहीं बोले हैं । उनको सिर्फ पट्रोलियम पर बोलना है ।

MR. CHAIRMAN: This is agreed to by the House. We cannot just go on discussing each point. Order please. Now, Shri Girdhari Lal Vyas.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की डिमांडज के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हूं ।

15.36 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्राईवेट सैक्टर द्वारा जो इंडस्ट्रीज खड़ी की जाती हैं, उनके लिए 90 प्रतिशत ऋण सरकारी एजेन्सियों से मिलता है और बाकी का 10 प्रतिशत भी वे लोग गोल माल कर के उसी में से निकाल लेते हैं । लेकिन उसके बाद सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी वजह से वे एक इंडस्ट्री का पैसा दूसरी इंडस्ट्री में डाल कर पहली इंडस्ट्री को सिक बना देते हैं । इस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है । मजदूरों का तनख्वाह बोनस प्राविडेंट फंड और इ एम आई आदि के पैसे और सुविधाओं से महरूम रखने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग एक इंडस्ट्री को सिक बना कर दूसरी इंडस्ट्री खड़ी कर देते है । इसलिए इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री को खास तौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री को सरकारी एजेन्सी से पैसा मिलता है, वह बराबर खड़ी रहे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग न हो और मजदूरों का जो हिस्सा है, वह भी उन्हें मिलता रहे ।

जनता पार्टी की सरकार ने मिल मालिकों को जिस प्रकार की छूट दी थी और उन्हें आम जनता को लूटने का अवसर दिया था, उस व्यवस्था को निश्चित रूप से बदलना चाहिए । कांग्रेस शासन में हमने कपडे पर कंट्रोल इसीलिए लगाया था कि हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है, जो मोटा और कंट्रोल का कपड़ा पहनती है, इसलिए वह कपडा उसे सस्ते भाव पर उपलब्ध हो सके । जनता पार्टी ने बड़े-बड़े मिल मालिको से न जाने किस प्रकार का फायदा उठाया और सारे कंट्रोल समाप्त कर दिये, उन्हें अच्छा फाइन क्लाथ पैदा करने की पूरी छूट दे दी, जिससे जो कपड़ा कंट्रोल रेट पर गांवो के गरीब लोगों को मिलता था, वह भी मंहगा हो गया और उन्हें भयंकर तकलीफ उठानी पड़ रही है ।

तीसरी बात मैं सीमेन्ट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । सीमेंट की इंडस्ट्री खास तौर से जब कांग्रेस का शासन था तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, हर एक आदमी को सीमेंट ठीक प्रकार से उपलब्ध होता था । . . . . (व्यवधान) . . . लेकिन जनता पार्टी के शासन ने सीमेंट के उद्योग को जिस तरह से बरबाद किया है उससे सीमेंट की इंडस्ट्री जितनी भी इस देश में स्थापित थी वह तमाम की तमाम कोलैप्स करने लग गई और आज आम लोगों को सीमेंट नहीं मिल पा

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

रहा है। इसलिए सीमेंट के कारखाने ज्यादा से ज्यादा स्थापित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। राजस्थान में आपने दो तीन लोगों को सीमेंट का कारखाना लगाने की आज्ञा दी है। लेकिन अभी तक वे कारखाने स्थापित नहीं हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने का इतना स्कोप है जितना हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है। इतना रा-मेटीरियल राजस्थान में उपलब्ध है सीमेंट के लिए कि जितना और कहीं नहीं है और इसलिए राजस्थान में सीमेंट के इतने कारखाने स्थापित होने चाहिए जितने से कि देश की सीमेंट की तमाम मांग को पूरा किया जा सके।

इसी तरह से माइका के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। बिहार में सबसे ज्यादा माइका होता है मगर उसके बाद दूसरे नम्बर पर राजस्थान आता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में माइका बहुत काफी मात्रा में मिलता है मगर उस माइका के खरीदने के सम्बन्ध में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से कोई उपाय नहीं किया गया है। मिटको आप ने स्थापित किया है लेकिन मिटको माइका खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं करता। यह बात निश्चित है कि भीलवाड़ा जिले में जो माइका पैदा होता है वह उतना अच्छा और उस क्वालिटी का नहीं होता जो बिहार में होता है, उसकी किस्म कुछ घटिया है लेकिन उस हालत में भी यह इतनी मात्रा में वहां पैदा होता है कि विदेशों में उस को भेज कर उस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा जा सकता है मिटको बहुत ही सीमित दायरे में काम करता है और आज जितना भी माइका वहां से निकलता है उस का कोई खरीददार नहीं है। इसका परिणाम यह है कि जहां 15 हजार लेबर उनमें काम करना था, आज वह तमाम की तमाम खानें बन्द पड़ी हुई हैं। मुश्किल से पांच सौ आदमी उस में काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मिटको द्वारा अधिक मात्रा में उसके खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसी तरह से जिंक का बहुत बड़ा भण्डार भीलवाड़ा में निकला है। आप ने अखबारों में देखा होगा कि भीलवाड़ा जिले के आंगूचा गांव में जिंक का हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा भण्डार मिला है। मैं निवेदन करूंगा कि जिंक का इतना बढ़िया और इतना बड़ा भंडार वहां निकला है कि जिस का उपयोग हम बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते है। इसलिए जिंक के सम्बन्ध में कोई न कोई इंडस्ट्री जिंक स्मेल्टर वहां स्थापित करने की व्यवस्था आप करें, हजारों लोगों को उससे काम मिलेगा और इस पिछड़े हुए क्षेत्र को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

इसी प्रकार से क्वार्ट्ज, ऐस्बेटोस, सोप स्टोन, लाइम स्टोन, लिग्नाइट और दूसरे कई प्रकार के खनिज पदार्थ भीलवाड़े जिले में निकलते हैं। उन के सम्बन्ध में अभी तक किसी प्रकार का कोई कारखाना या कोई इंडस्ट्री वहां स्थापित नहीं की गई है। ऐस्बेस्टोस भीलवाड़े में इतना अच्छा और सुपर फाइन क्वालिटी का निकलता है कि हिन्दुस्तान में क्या, दुनिया में वैसा ऐस्बेस्टोस कहीं नहीं निकलता। उस ऐस्बेस्टोस के सम्बन्ध में भी कोई इंडस्ट्री वहां नहीं लगाई गई है। इसी प्रकार सोप स्टोन भीलवाड़ा जिले में बहुत फाइन क्वालिटी का निकलता है और बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। मगर वह तमाम का तमाम एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे देश में इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई जिस के जरिए से इन खनिज पदार्थों का उपयोग हमारे देश में हो सके और उस से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तौर से की जानी चाहिए।

एक बात खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं खादी और ग्रामोद्योग के जरिए आप ने कहा है कि हम लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मगर आप किस प्रकार का रोजगार दिला रहे हैं। खादी में कत्तिन काम करती है उस को बारह आने रोज मिलते है, जो बुनकर खादी में काम करता है उस को 2 या ढाई रुपये से ज्यादा नहीं मिलता हम ने बराबर कई बार मांगा की कि मिनिमम वेज खादी के सम्बन्ध में भी लागू कीजिए ताकि उन का जो शोषण हो रहा है वह शोषण समाप्त हो। आप एग्रीकल्चर में और दूसरी इंडस्ट्रीज में मिनिमम वेज कानून लागू करते है लेकिन खादी और ग्रामोद्योग में जो बड़े बड़े अपने को सर्वोदयी नेता कहते हैं और जो बराबर वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ तब से इन गरीब लोगों का शोषण कर रहे है उन के शोषण को समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते, बल्कि कानून लागू कर के आप ने यह व्यवस्था कर दी कि वहां पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं हो सकता जहां पूरी रोटी उन को नहीं मिलती। 12 आने एक कत्तिन को मिलते है क्या 12 आने में एक टाइम का भोजन मिल सकता है? इसी प्रकार से बुनकर को दो-ढाई रुपये से ज्यादा नहीं मिलता। इस प्रकार का शोषण जो इस खादी और ग्रामोद्योग के अन्दर संस्थाओं में मठाधीश बन कर बैठे है जिन्होंने लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति बना ली है इस प्रकार के लोगों द्वारा जो हजारों लोगों का शोषण किया जा रहा है। इसको निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा। लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा अतः इस प्रकार

की व्यवस्था निश्चित तौर से की जानी चाहिए। आप चाहे मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू न करें लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य करें कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए निश्चित तरीके से उदरपूर्ति की व्यवस्था हो जाये। अतः इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

मेरा एक सुझाव और है। काटन कार्पोरेशन के द्वारा काटन खरीदने की व्यवस्था की जाती है लेकिन काटन कार्पोरेशन अपने ऊपर जिस स्थान से चाहता है काटन की खरीददारी कर लेता है। हमारे भीलवाड़ा जिले में काफी काटन होती है लेकिन वहां पर काटन की खरीददारी के लिए काटन कार्पोरेशन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो भी काश्तकार काटन पैदा करते हैं उनका शोषण होता है। उनको अपनी उपज का बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि काटन कार्पोरेशन के द्वारा काटन की खरीददारी की व्यवस्था की जानी चाहिए। भीलवाड़ा, आसीन्द, गुलाबपुरा, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई टेक्सटाइल मिलें जहां पर स्थापित हैं वहां पर काटन कार्पोरेशन की ओर काटन की खरीददारी व्यवस्था होनी चाहिए तभी वहां पर गरीब काश्तकारों का शोषण समाप्त हो सकता है। वहां पर इसकी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा सकता है। आज भी वहां बहुत मांग है कि सूती कपड़े के उद्योग ज्यादा से ज्यादा स्थापित किए जायें। आपके पास एप्लाई भी किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर यह व्यवस्था हो जाए तो उस क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा। मुझे आशा है कि आप हमारे सुझावों पर अमल करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इन डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं।

श्री पियूष तिरकी (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में एक अशांति का वातावरण फैला हुआ है। उद्योग मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि सारे देश को सामने रखकर, सभी समस्याओं को देखते हुए अपनी नीति और अपनी योजनाओं में परिवर्तन लाने की चेष्टा करें। हमने देखा है कि जबसे देश आजाद हुआ है, बहुत सारे उद्योग-धंधे खोले गए हैं लेकिन इन उद्योगों का लाभ किस को पहुंचा है? दूसरी ओर इस दौरान कितने लोग उद्योगों में बेकार होते जा रहे हैं क्योंकि जो मामूली सी चीजें हैं, जो प्राइमरी चीजें हैं वह मोहैया नहीं हो रही हैं। जिस नीति से आज यह देश चल रहा है उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमने देखा कि अंग्रेजों ने इस हाउस को बनाया था, रेलें और दूसरे बहुत सारे कारखाने भी खोले थे। हमने समझा कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने फायदे के लिए इनको खोला लेकिन इस समय भी उद्योग-धंधों में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है क्योंकि जितना भी रुपया पैसा उद्योग-धंधों का है वह पाँच परसेंट लोगों के पास ही जमा होता जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं।

About 15 to 25 big business houses have swalloed the national exchequer. They have increased their capital thousand times more than they were on the dawn of independence. The urban population 41 per cent. and 51 per cent of the rural population live below poverty line and about 20 crores of people have become economically redundant. The wave of discontent in eastern zone has taken an ugly turn. Fellow citizens are fighting among themselves cursing each other for their miserable plight in independant India.

अब मैं आपको कुछ आंकड़े, स्टेटवाइज जो नौकरी की तालाश में हैं, देना चाहता हूं।

	लाखों में
आन्ध्र प्रदेश	12.89
आसाम	3.27
बिहार	21.69
गुजरात	4.36
हरियाणा	3.29
हिमाचल प्रदेश	1.26
जम्मू और काश्मीर	0.54
कर्नाटक	5.60
केरल	12.75
मध्य प्रदेश	7.71
महाराष्ट्र	11.23
मणिपुर	0.88
मेघालय	0 10
नागालैण्ड	0.04
उड़ीसा	4.32
पंजाब	4.14
राजस्थान	3.32
तमिलनाडु	10.10
त्रिपुरा	0.68
उत्तर प्रदेश	13.76
वैस्ट बंगाल	21.99

[श्री पियूष तिरकी]

अण्डमान एंड निकोबार आईलेंड	0.88
चण्डीगढ़	0.56
दिल्ली	2.92
गोवा	0.27
लक्षद्वीप	0.04
मिजोरम	0.17
पोडीचेरी	0.34
कुल योग	148.43

अब मैं आपको कुछ ऐसे आंकडे देना चाहता हूं जो ट्रेनिंग पा चुके हैं, जो बेकार है और काम के लिए घूम रहे हैं ।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज मे 31-12-1979 के मुताबिक थे । आकडे है

सिविल इंजीनियर	5054
मैकेनिकल इंजीनियर	7244
इलैक्ट्रिकल इंजीनियर	7368
कैमिकल इंजीनियर	1029
माइनिंग इंजीनियर	82

जो आदमी इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीचूट से पास कर चुके हैं, वे भी एम्पलायमेंट एक्सचेंज में 31-12-1979 के मुताबिक है

इंजीनियरिंग ट्रेड	3 31,382
नान-इंजीनियरिंग ट्रेड	19,920

ये लोग आज भी काम के लिए इधर उधर घूम रहे है । नान-इंजीनियरिंग ट्रेड में बुक बाइंडर, हैंड कम्पोजीशन एंड प्रूफ रीडिंग, स्टैनोग्राफर आदि ये सब लोग आते हैं । ये बच्चे पढ़ लिखकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं । मैं मंत्री महोदय से, जब वे अपना जवाब देंगे, जानना चाहता हू कि वे इनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं ।

कुछ दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र से दो आदमी आए थे । वे कह रहे थे, कि हिन्दुस्तान हमारा है । मैंने कहा ठीक है, हिन्दुस्तान हमारा है । जब वे दिल्ली घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहां बडी-बडी कोठियों पर टाटा, बिरला, डालमिया आदि के नाम लिखे हुए थे । फिर उन्होंने पूछा कि हिन्दुस्तान किस का है, तो मैंने कहा कि कुछ व्यक्तियो का है, हमारा नही है। उसके बाद वे बिरला मंदिर देखने के लिए गए, तो उसकी औरत ने पूछा कि यह कौन से देवता का मन्दिर है? मैंने कहा कि यह बिरला देवता का मन्दिर है । फिर उसने पूछा कि यह कौन से देवता हैं? मैंने कहा कि तुम को रामायण और महाभारत देखना पड़ेगा कि कहां इनका नाम है । मैंने कहा कि यह नए देवता हैं और इस तरह के 20-22 देवता और हैं, उनके मंदिर भी बन रहे हैं और शायद बनेंगे । ये देवतागण हिन्दुस्तान की चाहे अर्थ-व्यवस्था हो, राजनीति हो, हर चीज को अपने हाथ में ले चुके हैं और यहां तक कि राजनीति में भी उनके नुमाइंदे उनके पक्ष में हमेशा बोलते रहते हैं । इलैक्शन में भी रुपया-पैसा खर्च करके उनके रुपए से ही सरकार बनती है । उन के रुपये से इण्डस्ट्रीज बनती हैं, उन के रुपये से ही सारे देश की कानून और व्यवस्था चलती है । इन देवताओं की पूजा करना हमारी सरकार छोड दे । हमारे हिन्दुस्तान का हर आदमी क्या चाहता है—रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान और उस के स्वास्थ्य की निगरानी—सिर्फ इतना ही चाहता है । इन चीजों की व्यवस्था करने के लिये हमारे उद्योग मंत्री को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिये ।

आज बहुत से कल-कारखाने बन्द पड़े हैं लेकिन उन पूंजीपतियो को हमारी सरकार सख्त आज्ञा नही दे सकती, क्योंकि उन को डर है, यदि सख्ती आरम्भ हो गई तो दूसरे इलैक्शन में उन को पैसा नही मिलेगा । इस लिये उन को भाई दादा कह कर, उन के पांव का तलवा मालिश करना हमारे मिनिस्टरो का काम बन चुका है। मैं कहता हू कि आप थोडा सख्ती से बोलो, हमारी जनता मर रही है, इस को काम दो । "कुमारधोबी" कारखाने में हजारो आदमी बेकार बैठे हैं, रोटी के लिये रो रहे हैं, बिहार के लाखों आदमी आसाम और दूसरी जगहो पर गये, क्यो गये, इन को किस ने भेजा? एक्सप्लायटर्स उन को वहां ले जाते हैं । आज यहां पर शान्ति और व्यवस्था की बातें कही जाती है, शान्ति-व्यवस्था को भग करने वाला कौन है क्या हमारी सरकार को इतना भी ज्ञान नहीं है? वहां पर जितने बिजनेस हैं, सब फारेनर्स के हाथ में हैं, इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स उन से फायदा उठा रहे हैं ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि जितने भी कारखाने बनें, उन को कैपिटलिस्ट्स के हाथ में नही देना चाहिये । सरकार को अपने हाथ में रख कर चलाना चाहिये, इन लुटेरों के हाथ में वे कारखाने नही पड़ने चाहिये । आप ने समय दिया, धन्यवाद। गरीब को समय कम मिलता है, यह हम को मालूम है । यदि हम भी पूंजीपति होते तो आधा घन्टा मिलता ।

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): I fully support the demands Nos. 58, 59 and 60 of the Ministry of Industry. There is a saying as you sow, so shall you reap. The Economic Survey and the CSO have reported that the national growth rate is below 3.5 per cent; so also industrial production is below 1.5 per cent which indicate that the task before this government is very important.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are about thirty members from the ruling party; every one should take only five minutes; only points should be mentioned. Then the Minister will reply. If you take more time, the time of other Members, I will put them against you.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): When will the hon. Minister reply?.... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister will reply at quarter to five.

16 hrs.

SHRI XAVIER ARAKAL: Industrialisation is closely connected with planning and regulation, participation and economic stimulation. The budget clearly indicates the direction but I would like to give a few suggestions for the consideration of the hon. Minister.

1. The existing industrial and financial laws and existing legal systems should be evaluated.

2. We must have a close look on the entire banking and financial systems especially I.D.B.I., I.F.C., N.I.D.C. I.C I.C. and to see how far they have helped the industrial development of the nation and who are the beneficiaries of those.

3. National and regional wages-prices-income policy should be evolved. I am not going into the details.

4. We should ban all our export of raw materials. Even to-day's paper has indicated—millions and millions of tonnes of iron ore are going to be exported. Why are the people unemployed? Why is the poverty here? My submission is that the export of raw materials should be stopped.

5. We must look at the entire distribution system in our country. My suggestion is that the distribution system should be owned and controlled by the Government

6. As has been said by me in my earlier speech we should ban strikes and lock-outs in basic industries and essential services.

7. Industrial and product preferences should be spelt out. 1948 Industrial Policy Resolution was moved by Shri Mukherjee. Resolution of 1956 is there. In addition to that policy of 1977 is there. We should evaluate what is the impact of these Resolutions and policies and try to evolve a new national policy in this country.

These are my suggestions. May I make some of my requests—

The first one is related to the economy of the Kerala State. The problem of the State is acute as those of the problems of other States. The Kerala State Government is frittering away the hard earned money for social and infrastructure purposes. For what purpose? The leftist Governments in power? Therefore, I am saying that unproductive expenditure of the Kerala State Government has a detrimental effect on the industrial development of the State. Therefore, I am making these requests for your consideration—

1. In Kerala there is a vast scope for petro-Chemical industries. The one which has been pending before the Government is aromatics project. If it is established at Cochin Refinery, that will cost only Rs. 55 crores, whereas if it is established at Mathura, it will cost Rs. 200 crores. Where should it be allowed and for which place should it be sanctioned?

(*Interruptions*)

2. The second one is about the establishment of caprolactum project. It will be highly useful.

The developmental scheme in the south will sprout out if this is sanctioned. This has been pending before the Central Government for a long time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: His time is over.

SHRI XAVIER ARAKAL: I will conclude in a minute. The FACT at Udyogamandalam is over 35 years old.

[Shri Xavier Arakal]

It has not been modernised and there is no diversification. If it is not done, about 4000 employees will be thrown out of employment. Imagine what will be the impact of such a thing happening. Obsolete and redundant equipments are there. Ever since it was installed it is remaining there and there is no modernisation. This should be taken into consideration.

About Hindustan Aromatics Ltd., the Kerala Government have said in their letter dated 22-10-79 and again on 18-2-80 that they will provide the required land, water, electricity and other resources and requested the Centre to start that factory. You know what is the reply? The reply of H. A. Ltd., No. MDA/360/16/319 dated 22-2-80 was that the matter was "still under consideration of the Government of India". May I know the reason for this delay?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI XAVIER ARAKAL: In conclusion, I would like to say that I am sorry that after leaving the Congress Party, Shri Unnikrishnan has stopped reading our election manifesto. Mr. George Fernandes was telling us how he went abroad...

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am calling the next speaker—Mr. Jai Pal Singh Kashyap.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यह वह मंत्रालय है, जो पिछले 33 साल से हिन्दुस्तान में सरमायेदारों का निर्माण करता रहा है । इसके द्वारा देश की पूंजी कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठी हुई है, कुछ क्षेत्रों का ही विकास हुआ है, कुछ ही व्यक्तियों का विकास हुआ है । यहां के जो साधारण लोग हैं उनका इस मंत्रालय के द्वारा शोषण हुआ है । जिस तरह की योजनाएं मंत्रालय को बनानी चाहिए थीं उस तरह की योजनाएं यह मंत्रालय नहीं बना पाया है ।

इस देश में इतनी अधिक आबादी है कि बेरोजगारी दूर करने का इस मंत्रालय द्वारा पहले उद्योग होना चाहिए था लेकिन उद्योग इस देश में बनाये गये प्रोफिट मोटिव से जिनसे कुछ लोगों को ही लाभ मिला । कुछ लोगों की तिजोरियां ज्यादा बड़ी हो गयीं, बैंक बेलेंस ज्यादा हो गये, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में सारे स्रोत, सारा कैपिटल इकट्ठा हो गया । यही कारण है इस देश की गरीबी का ।

इस देश के किसानों को उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिली, मजदूरों की तंख्वाह नहीं मिली । इस देश में बेरोजगारों को इसलिए बेरोजगार रखा जाता है कि वे सस्ते दर पर मिल सकें । इसलिए देश में मजदूरों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है । उद्योग मंत्रालय को बेरोजगारी दूर करने की, स्थानीय रा मेटेरियल, कच्चे माल के सही तरीके से प्रयोग किये जाने की नीति बनानी चाहिये । जो किसान रा मेटेरियल पैदा करता है, उत्पादन में उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए । इस तरह की हमारी नीति होनी चाहिए ।

जहां तक इस देश में बढ़ते हुए सरमायेदारों का सवाल है, उन्होंने इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर जो प्रभाव डाला है उसके लिए उद्योग मंत्रालय विशेष रूप से जिम्मेदार है क्योंकि इन्ही सरमायेदारो से इन्हें बराबर पैसा मिलता रहा है । अगर इस देश को संभालना है तो मुख्य रूप से दस लाख रुपये से ऊपर के सारे उद्योग धंधों को हमें नेशनलाइज करना पड़ेगा । अगर आप इसको नहीं करेंगे तो देश से गरीबी और आर्थिक विषमता नहीं मिट पाएगी ।

करोड़ों लोग जो अपने हाथ से काम करते हैं, सही मानो में देश के वही कारखाने हैं । कुम्हार जो अपने हाथ से चाक पर काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, लोहार जो अपने हाथ से तरह तरह के औजार बनाता है, लकड़ी को जो तोड़ता है बढ़ई और इस देश का जुलाहा जो खड्डी पर कपड़ा बनाता है वही सही मानों में देश के कारखानें हैं, उद्योग हैं । उनकी तरफ हमारा उद्योग मंत्रालय ध्यान नही देता है । इनको आज तक उद्योग मंत्रालय नें उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिये था । जितना प्रोत्साहन इनको मिलना चाहिये था नहीं मिला । यही कारण है कि ये जो काम करनें वाले लोग देहातों में रहते हैं, उनके उद्योग धंधे ठप्प होते जा रहे हैं और वे शहरो की ओर दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है । उद्योगों का केन्द्रीकरण हो रहा है और कुछ एक हाथों में उद्योग धंधे तेजी से जा रहे हैं । हमारे देश में बहुत से काम हो सकते हैं । आलू की फसल, आम की फसल का सही उपयोग नहीं होता है । मछलियों का सही उपयोग नहीं होता है । डिब्बा बन्दी इन वस्तुओं की तथा

दूसरी वस्तुओं की हो सकती है । आलू के उत्पादन को बहुत बढ़ाया जा सकता है और इसको विदेशों को भेजा जा सकता है । इसी तरह से और भी चीजें हैं, जिन का निर्यात हो सकता है और आपको विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है । मैं चाहता हूं कि हर गांव में आप ग्राम स्तर के उद्योग धंधे खोलें और हर ब्लाक स्तर पर, विकास खंड स्तर पर एक एक कारखाना खोलें । तब जा कर जो बेरोजगारी है और आर्थिक विषमता है वह दूर होगी ।

बदायूं-बरेली क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । वहां लाखों लाख बेरोजगार हैं । देहातों से लोग भाग भाग कर दूर स्थानों पर जा रहे हैं । वहां मूंगफली, तिलहन आदि बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होता है । उन पर आधारित कारखाने आप उनके लिए खोल सकते हैं । मैं चाहता हूं कि इस की भी आप जांच करें ।

चारों ओर केन्द्रीकरण न हो कर कारखानों का, उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये । तभी देश को फायदा हो सकता है और आर्थिक विषमता दूर हो सकती है ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : उद्योग मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं । किसी भी देश के उद्योग धंधे उस देश के विकास और उसकी प्रगति के सूचक होते हैं, इस में कोई दो रायें नहीं हैं । परन्तु जहां नए नए उद्योग स्थापित करना जरूरी है वहां उतना ही जरूरी यह भी है कि वर्तमान में जो उद्योग हमारे देश में स्थापित हैं वे पूरी क्षमता से काम करें । इस को देखना भी बहुत जरूरी है । मैं परिवहन उद्योग की मिसाल देना चाहता हूं । उसके कुछ आंकड़े भी मेरे पास हैं । उन से यह साबित होता है कि हमारे देश में जो उद्योग लगे हुए हैं--वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं । कमर्शियल वीहिकल्स का उत्पादन सिर्फ चालीस प्रतिशत हो रहा है । मोपेड का 35 प्रतिशत ही हो रहा है । एग्रिकलचरल ट्रैक्टर्ज का उत्पादन 45 प्रतिशत ही हो रहा है । डीजल इंजनों का 30 प्रतिशत ही हो रहा है । कहने का मतलब यह है कि अपनी उत्पादन क्षमता से बहुत कम ये उत्पादन कर रहे हैं । उद्योग मंत्री जी से मैं कहूंगा कि इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिये और उनको एक जांच बिठाना चाहिये और पता लगाना चाहिये कि ये जो कारखाने हैं इन के उत्पादन में कमी क्यों आ रही है । एक पूर्व वक्ता ने कहा है कि आज ट्रकों के ऊपर तीस चालीस हजार की ब्लैक चल रही है । मैं समझता हूं कि यह इसी वजह से है कि हमारा उत्पादन कम हो रहा है, क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है ।

हमारे जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग हैं वे भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, पचास प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग वे कर पा रहे हैं । वित्त मंत्री जी ने यह बताया कि एक हाई लेवेल इनक्वायरी उन्होंने आर्डर की है । मुझे आशा है कि इस इन्क्वायरी में जो तथ्य सामने आएंगे उनको [illegible] हुए जो कमियां हैं उनको दूर करने में हम समर्थ हो सकेंगे ।

पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज में देखा गया है कि बड़े बड़े अफसरों को इनका संचालन करने के लिए भेज दिया जाता है । वे सरकारी आफिसर होते हैं । उनका एक पैर सरकार में होता है और दूसरा पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में । नतीजा यह होता है कि वे अपने आपको उस अंडरटेकिंग के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उस में पूरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं । ऐसे अफसर आप भेजें जो दिल लगा कर काम करें और अपने आपको उस अंडरटेकिंग के साथ आइडेंटिफाई कर सकें । जैसे आपने आई ए एस कायम किया है वैसे ही इंडियन इंडस्ट्रियल सर्विस भी आप बना सकते हैं और इन लोगों को इन अंडरटेकिंग्ज का काम सम्भालने के लिए भेज सकते हैं । इंडिजनस एक्सपर्टाइज जो हमारी हैं, उन्हें हमें रखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो विदेशी कंपनी हैं, वह अस्थायी प्रलोभन देकर इनको खत्म न कर सकें । हमने देखा है कि हमारे उद्योगपति एक गलत तरीका अपनाते हैं और वह यह होता है कि जैसे 1979-80 में 550 लैटर्स आफ इन्टैंट इश्यू किये गये, तो कुछ उद्योग वाले लैटर आफ इंटैंट हासिल कर के उसे कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं । ऐसा वह इसलिये करते हैं कि दूसरा कोई और उद्योग स्थापित न कर सके और उनके कंपीटीशन में न आ सके । इस प्रक्रिया की जांच होनी चाहिये और इसके लिये समय निर्धारित किया जाना चाहिये कि इतने दिनों में उद्योग स्थापित किया जाना चाहिये, वरना लैटर आफ इन्टैंट कैंसिल किया जाना चाहिये ।

हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैंटर के बारे में जनता पार्टी के जमाने में, लोकदल की सरकार के जमाने में बड़ा जोर दिया गया और हर जगह डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैंटर खोले गये । हमारी डिमांड्ज फार ग्रान्ट्स में भी इसका जिक्र है और जैसा इसमें दिया गया है, उससे ऐसा मालूम होता है कि यदि कोई उद्योग लगाना चाहे तो वह सीधे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैंटर में चला जावे, वहां पर उसको सारी चीजें मुहैय्या कर दी जायेंगी । यह गलत प्रचार है । मैं अपने यहां का अपने जिले और अपने स्टेट का भी बता सकता हूं कि वहां पर हमें कोई सहूलियत नहीं मिलती है, न फाइनेन्स मिलता है, न टैक्निकल नो-हाऊ मिलता है और न लाइसेंस व मशीन हासिल करने में सहूलियत मिलती है और न बिजली वहां से मिलती है, सिर्फ जिस तरह से पहले इंडस्ट्रीज आफिसर्स हुआ करते थे, उसी तरह से वे अब भी फंक्शन कर रहे हैं । मगर इनको कुछ बताना है,

[श्री जितेन्द्र प्रसाद]

तो हमें इन्हें कुछ पावर्स डैलीगेट करनी होंगी वहां के जनरल मैनेजर्स को कि वह इंडस्ट्रीज के महत्व को देखकर उसको यह चीजें एलोकेट कर सकें ।

बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि 246 डिस्ट्रिक्ट्स गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 1970-71 में बैकवर्ड डिक्लेयर किये । मैं कहना चाहता हू कि जो आज सहूलियत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई हैं, जैसे कि रा-मैटीरियल, पावर, लाइसेंस में प्रायरटी मिलेगी, फाइनेन्स में सहूलियत मिलेगी और उसमें सूद वगैरा की छूट मिलेगी, यह सहूलियतें कतई हमको नहीं मिल रही हैं । जो बैंक्स हैं, वह कतई भी सूद में छूट नहीं दे रहे हैं, 11 परसेंट सूद जो और इलाकों में वह चार्ज करते हैं, उसी तरह से बैकवर्ड एरियाज में भी चार्ज कर रहे है ।

यह जो रिफाइनेन्सिंग है, आई०डी०बी०आई० है, उसमें भी बैंक इन्ट्रेस्ट नहीं लेते हैं । यह जो लोन हमको दिये हैं, उसमें रिफाइनेन्स इश्यू किया जाये ।

इसी तरह से यू०पी०एफ०सी० में जो नार्मल मार्जिन मनी लगता है, उसी तरह से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में भी वही मार्जिन मनी लिया जाता है ।

मैं निवेदन करूंगा कि जो आपने वायदे किये हुए है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिये, जो सहूलियतें दी है, कम-से-कम यह तो देखें कि यह हर जगह इम्पलीमैंट तो हो रहे है ।

इसके साथ साथ आपने कैपिटल सब्सीडी के लिये डिस्ट्रिक्ट्स और घोषित कर दिये है जिसमें 15 परसेंट, कैपिटल की इन्वैस्टमैंट पर सब्सीडी दी जायेगी । मुझे नहीं मालूम कि यह कौनसा पैमाना आपने अख्तियार किया है जिससे 101 जिले छांटे गये है । मैं कह सकता हूं कि हमारा जिला शाहजहांपुर, सीतापुर ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उनको तो कैपिटल सब्सीडी स्कीम में नहीं लिया गया, जब कि हमारे आस-पास के जिले जो कि औद्योगिक दृष्टि से अच्छे है, उनको कैपिटल सब्सीडी स्कीम में ले लिया गया है, हम लोगों को उस स्कीम का हकदार नहीं माना गया है ।

इस तरह से पूरे देश में बहुत इकनामिक इम्बैलन्स हो रहा है । कुछ प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए है और कुछ बहुत पीछे है । मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमारी आबादी और रकबे को देखते हुए हमारे साथ ज्यादती हो रही है । मैं निवेदन करूंगा कि उद्योगों का बटवारा जिस तरह से औरों को किया जाता है, उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी पूर्ति की जाये ।

शाहजहांपुर में कारपेट इंडस्ट्री है । मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट में दिया गया है कि 30 हजार आदमी हमने ट्रेन्ड किये । कारपेट इंडस्ट्री में आपने इतने आदमी अच्छे ट्रेन्ड तो कर दिये परन्तु इसका फायदा क्या हुआ ? वह लोग 5, 7 रुपये के मजदूर हैं और वह सिर्फ मजदूरी ही पाते हैं । हमारे शाहजहांपुर के अन्दर 2 करोड़ रुपये का कारपेट एक्सपोर्ट होता है, जो गरीब लोग इसको बनाते है, उनको इसका कोई बैनिफिट नहीं जाता । मैं चाहता हूं कि वहां पर एक्सपोर्ट कार्पोरेशन का दफ्तर खोला जाये ।

आखिर मे मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आजादी से ले कर अब तक कोई भी उद्योग वहां पर स्थापित नहीं किया गया है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह खुद वहां चलें, अपने अधिकारियों को भी ले चलें और एक सैमिनार करें, ताकि सरकार और प्राईवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स वहां पर उद्योगों की स्थापना करें ।

*SHRI C. CHINNASWAMY (Gobichettipalayam): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party, the All India Anna D.M.K., I rise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Industry. I am happy that this important Ministry, which plays a pivotal role in the economic progress of the nation, is in the hands of a young energetic Minister, who, I am sure will circumvent the Energy constraints which have become the cause of concern for all in the country.

The Government is envisaging an annual growth rate of 5 per cent during the VI Plan with additional investment of 16.6 per cent in a situation of 20 per cent rise per annum. I wonder how the proposed growth rate can become a reality. In the western countries the industrial growth rate is astonishingly high. But our industrial backwardness is high-lighted by the stay-put 18 per cent contribution of the industrial output in the total output of the nation during the past fourteen years. Can we afford to remain under the euphoria of industrial advancement even after this dismal performance?

*The original speech was delivered in Tamil.

It is not enough to establish industries. In a nation of never-ending population growth, unless the industries generate employment opportunities the public purpose is not served. The number of persons employed per Rs. one crore of net output in the consumer goods is 3131 and the number of persons employed per Rs. one crore of net output in the capital goods is 2596. These statistics urge upon the need for greater investment in industries producing consumer goods bearing an impact on employment policy of our government.

The Central Government is determined to encourage the cottage sector, which will generate employment in rural areas. But it must be ensured that the products of cottage sector are properly marketed by the Khadi and Village Industries Commission, without the excuse of paucity of godown space and lack of funds for procurement. The K.V.I.C. should be strengthened adequately. It is a matter of condemnation that the country has to import sugar, cement, oil, steel, aluminium etc. at a cost of several hundreds of crores when it has large idle capacities had abundance of raw materials. Though power shortage is the cause for lesser production, it is mainly because of bad management and improper distribution. The industrial units producing these items should be allowed to utilise fully the installed capacity and even be prompted to expand further. At present only 45 per cent of the installed capacity is being utilised. The nation cannot be allowed to be held to ransom of artificial scarcity. Effective steps are the need of the hour to save nation's valuable foreign exchange.

Sir, Periyar District in Tamil Nadu, which has been recently created, is industrially backward. It should be declared as a backward district by the Centre, so that it receives much-needed financial incentives and other amenities for industrial development. In Satyamandalam, all the basic raw materials required or setting up a; paper mill are available in abundance. I demand that a paper mill should be set up in Satyamangalam. The Government of India should pay special attention to the industrial development of Dharapuram, Kangeyam, Bhavani, Bhavanisagar and Andhiyur in this area. Upto 31 May, 1980 the Tamil Nadu Government has forwarded 90 applications from entrepreneurs. So far the Government of India has not approved even one application for setting up an industrial unit.

I have been hearing some hon. Members repeatedly saying that Tamil Nadu has gone down in industrial development. I have to point out that these apprehensions are baseless because no statistics are being given to support this contention. The Government of Tamil Nadu under the dynamic leadrship of Puratchi Thalaivar M.G.R. is going to organise industries which will generate employment opportunities for 3 lakhs of youth in Tamil Nadu. The Government of India have invested Rs. 15.682 crores in public sector industrial undertakings throughout the country and Tamil Nadu's share is just Rs. 616 crores, which is not even 4 per cent. Does this not go to show industrial imblance prevalent in the country? There is a feeling in the minds of Tamil people that the Centre is callous towards the industrial needs of the State of Tamil Nadu. I request that the hon. Minister of Industry should allay these apprehensions of the people of Tamil Nadu by augmenting the allocations for the industrial development of Tamil Nadu.

With these words, I conclude my speech expressing my gratitude to you for giving me this opportunity to participate in the Debate on the Demands for Grants of the Industry Ministry.

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants relating to the Ministry of Industry. My friend, Mr. Unnikrishnan expressed some fears that we are changing our basic Industrial Policy Resolution of 1956. This fear was express-

[Shri R. L. Bhatia]

ed by Mr. Madhukar also. They need have no such apprehension. We are not going to change it. We are going to stick to it and the more fact that we have nationalised five more banks is indicative of our mind.

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North): Six banks.

SHRI R. L. BHATIA: Mr. Unnikrishnan also said that we are going to have technicians from abroad to run our power plants. It is not so. What Mr. Ghani Khan Choudhry said the other day in this House was that, with the power plants which were imported from outside, there is some trouble and that we would ask the foreign technicians to come here and set them right. No foreigner is going to come over here to run our power plants.

Mr. Jaipal Singh was talking about rural economy, which is a pet theme of his leader, Mr. Charan Singh. The country is moving fast. We want to take the country forward. Actually, the Janata and the Lok Dal Governments have ruined the economy in the past. What Mr. Charan Singh did was the worst that could happen to this country. It is the old debris that we are going to clear now. It is our lot to do so.

The Ministry of Industry apart from being responsible for the formulation of the policy, are also responsible for the development of the industries in this country. The country has already suffered in the past, as I said, just now, due to lack of policies or whatever reasons they are. So, I would like to say that we should learn from the mistakes committed by Janata and others previously. What we should do is to, first of all, identify the problems, identify the needs of the poor people, the needs of the millions, about which we are so much perturbed and for which we are bringing about so many policies and doing so many other things. After identifying the problems, we should look into this industry and try to solve the problems of the millions of people in this respect.

Ours is a huge country and we also need an equitable distribution of what we produced. That is also a part of our policy. I expect the new Minister, who has robust common-sense, a lot of initiative and who is very intelligent, to come forward with solutions to the problems and with policies by which we could achieve our objectives quickly.

Coming to the public sector, the concept of State enterprise or the public sector in the Industrial Policy Resolution is that the people of this country will progressively own the means of production. That was our objective and policy. The object was to bring about a social transformation by controlling the heights of our economy. A number of friends were asking yesterday as to what is the policy of this Government. Well, this is our policy. Our objective is not only to produce steel, but to make steel an instrument of change. In our endeavour to achieve our objective, we need to see to so many things. In the public sector, so far, it is the bureaucrats who are running the show. They have a different frame of mind. They are officers coming from, say, the Postal or Railway Departments and they have no experience of business. And you have put them as heads of these public undertakings. Naturally they are not functioning properly. They have a limitation: they have a different frame mind; they cannot be flexible for the exigencies of business; they do not have business acumen. And you have placed them there. The result is that our public undertakings are getting a bad name. So, I would suggest that you have experts from industry and trade to man these public undertakings. I do not think that these bureaucrats will like that. Some experiment was made some time back, but they forced them to leave; they created conditions in which no outsider could come and man those public undertakings. It is the monopoly of the IAS

people. They do not tolerate anybody to be above them. Therefore, I do not think that this scheme will work. But I will give you an alternative scheme, and that scheme is this. You have an Advisory Committee or Council consisting of people from industry, people from Reserve Bank, a man from the Finance Ministry, a man from the Economic Ministry, and one or two MPs; public men should also be attached; these five or six people should act as advisers to that public undertaking. May be, this experiment will be successful.

The second point I want to raise is this. All our friends in the Opposition, CPI and CPM, including Mr. Jyotirmoy Bosu, are very happy when we nationalise a concern. We are all on the same wave length so far as nationalisation is concerned; there is no difference of opinion. But the difference arises in the implementation of it. In the factories there are rivalries among the unions. They are looking at the public undertaking from the same angle as they see the private industry. They must also see that this is a social transformation. We have certain objectives, common objectives, and we want to achieve those. But the same thing which they apply to the private sector, they are applying to this sector also. In some of the factories, I find that the union-*dadas* are contractors also. That is how thefts are taking place. Therefore, it is not our responsibility alone; it is their responsibility also. If they want to see that the functioning of the public undertakings is successful, then they must mend their ways and see that the labour cooperates with the administration and not fight with them. That is how we will be able to achieve our objective.

With regard to small scale sector, I would only say that a sum of Rs. 1 lakh invested in the small scale sector gives employment to seven people, but if the same sum of Rs. 1 lakh is invested in the big sector, it gives employment to only one man. Therefore, the small scale sector must be encouraged. Fifty per cent of the total production in the private setcor is done by the small scale industries. Therefore, it should be a part of our policy to encourage them. For that, I give you a proposal. Do not permit big industries and monopolies for composite units. You should give them licence only for assembling as in the case of Phillips; Phillips can only assemble, and there are one thousand ancilliary units, which are feeding them. But in the case of Birlas and others, you have permitted composite units. They are doing ginning, they are spinning, they are weaving, they are printing, they are marketing. These processes should not be given to the monopoly sector or big sector. This is harming us because they want profit on every side. Therefore, I would suggest that all these big industries should be only assembling units; they should be given only one job. The rest should be given to the small scale sector, so that they produce more and there is no problem about marketability.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I know, while replying to the debate, the hon. Minister will start refuting at the top of his voice that they are not stepping back from the Industrial Policy Resolution of 1956. But may I point out that there is a genuine suspicion among the people from the recent pronouncements—giving power generation to the private sector, dismantling of Sindri Fertiliser and the proposal to hand over Kumardhubi Engineering Works to TISCO—that this Government, in the name of nationalisation, in the name of talking big of socialism, are going to step back and are gradually leaning more and more towards the private sector. The point is not that: what industries or which concerns would be nationalised by the Ministry of Industry. The point is how to nationalise the Ministry of Industry itself. All monopolists, all multinationals have their tentacles in the Ministry of Industry. Officers of different departments are classified with different types of vested interests.

[Shri A. K. Roy]

Then, Sir, you know there is the Bureau of Public Enterprises which recruits the officials for all the public sectors and you know who selects the officers there? The Selection Board of the Bureau of Public Enterprises—who are its members? The Managing Director of the Tatas, Mr. Rusi Modi is one of its members and he sits in the seletcion board of the Bureau of Public Enterprises and that selects the officers for our public sector. So, Sir, private sector people are sitting and selecting officials for our public sector! Those who have got no faith in the public sector are catering to or are selecting or are choosing our manpower. This is the way the Ministry of Industry is in the hands of the private sector and they are regulating its entire policies and that is why the public sector is cutting somewhere some sorry figure.

The second point to which I would like to draw the attention of the hon. Minister is my Dhanbad district. Dhanbad district is to be the industrial capital of the Eastern India. All core sectors are there: coal, steel, fertilisers, firebricks and engineering industry, all these industries are to be there and that is to be the garden of all the industries. To-day it looks like a graveyard of industries.

And among the industries closed is one Kumardhubi Engineering Works about which many hon. Members have already spoken. I would also like to request the Minister to make some categorical statement in this House. That particular industry previously was in the hands of Bird & Co. and with some paper manipulation it has come into the hands of Hilgers group of companies. This is just a paper manipulation and after that, since July 1979 the industry is lying closed and 4000 employees are under starvation. That is an important engineering industry and that industry is indebted to the Allahabad Bank to the tune of Rs. 8 crores and to Bihar Government to the tune of Rs. 2 crores and to the workmen to the tune of Rs. 14 lakhs and they cheated the government and everybody. Now the company, under an order of the Calcutta High Court, is in the custody of the Allahabad Bank. We also had talks and discussions at different levels were held—with the Bihar government, with the Central government and with the Allahabad Bank and we were all assured that the Government of India either directly or through some public sector will take charge of that particular engineering unit and run it. Now we are getting this alarming news that they are going—there is a conspiracy going on—to hand over that factory to the TISCO or some other monopoly house. That is why we say that that will be a glaring example that these people are going to dilute the Industrial Policy Resolution so far announced at the top of their voice. That is why I make an appeal to the Minister that while replying to the debate he should categorically say what he is going to do with regard to the Kumardhubi Engineering Works and how he is going to set free the Bureau of Public Enterprises from the guardianship of the Managing Directors, etc. of these monopoly Houses as I have already referred to.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): The Government, in the name of revision of the Industrial Policy Resolution of 1956, are inviting the multi-nationals to loot, the monopoly capitalists to exploit the public sector and to restrict their expansion and the small and cottage industries to ruination. My friends have mentioned that the government is inviting the private sector to construct thermal power stations. But, still, about 100 collieries are functioning at the hands of the private sector, My hon. friend, Shri A. K. Roy, mentioned that Government have decided to nationalise Kumardhubi Engineering Works. Now, they are going to hand over the concern to Tatas. This shows which way the Government is going; how they want to revise the industrial policy against the people, against the nation, against the country

Sir, you know that N.T.C. was incurring a loss. At present, of course, it has earned a profit. Now one unit of NTC in West Bengal has been closed down. I would request the Minister to reopen it as early as possible. The N.T.C. has been entrusted to produce controlled and coarse cloth. On the other hand, the private sector mills have been entrusted to produce fine and superfine cloth. At the same time, the Government is importing cotton for the private sector and financing the export varieties. The monopoly textile mills are producing less and are earning more money by monopolising the market with the price hike. In textiles both the private sector and the public sector produce nearly fifty per cent of the produce while the rest of the fifty per cent is produced by the handloom and cottage industries. But what we see is that credit given by the commercial banks to the private sector companies, both the private and public sector textiles is about Rs. 500 crores yearly. Only 100 crores is given to the handloom and cottage industries. If more money is allocated for the handloom and cottage industries, they can produce more than 50 per cent thereby more people can get employment.

So, I would request the hon. Minister to allocate more money for the handloom and the cottage industries. Protection has been given to the handloom industries in the form of rebate. But, it is just symbolic and the traders get the rebate. It does not actually help the weavers. I would suggest that the real help will be by abolishing the excise duty and it should be passed on to the weavers by the public distribution system of yarn.

Smallscale industries of West Bengal are not getting adequate raw materials quota from the Centre such as paraffin, yarn, steel etc. Smallscale industries around Durgapur, Raniganj, Asansol are not getting sufficient orders and they are starving. I would request the hon. Minister to coordinate with the Steel Ministry, the Ministry of Petroleum and Chemicals, Coal and Energy so that they can get the orders from the D.S.P., A.S.P. and Eastern Coal fields and smallscale industries which are facing crisis.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I give you two more minutes. Kindly conclude. This is the extended time.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I know that. But do not ring the bell. I am concluding.

So, steps should be taken to develop the smallscale industries in the backward districts of Bankura and Purulia. I would suggest that public sector should undertake to set up industries in the backward areas.

Sir you know in all the units of the Instrumentation Ltd. the workers are on strike for more than four months most of whom are casual; though they are working here for three to twelve years, they are not getting their wages properly and there is no regularisation of the service for them; they are not given the benefits of the labour legislation and the ministers are not intervening. I request the Minister to intervene and solve the problems.

The Bharat Opthalmic Glass Ltd., Durgapur is in a bad shape. An expert committee was formed for introducing a continuous process technology for the manufacture of ophthalmic glasses. I would request that steps should be taken for expansion to save the concern. Indian Paper Pulp Company of Titagarh which employes 1,800 to 1,900 employees can produce 45 tonnes of good quality paper daily. It is going to be closed. For the last two years its economy is in bad shape. The Chairman of the Hindustan Paper Corporation was appointed by the Government in the Board for its revival but an impression was there that it will be taken over. Chief Minister of West Bengal has written to the Prime Minister for assuring the supply of raw material and the Unions are ready to cooperate for revival of this company.

Sir, in regard to the Motor Machinery Manufacturers Company Ltd. of

[Shri Krishna Chandra Halder]

Dum Dum, the management is threatening to close it from 26th July. The company was taken over on 9th October 1974 under IDR Act. The company retrenched many employees and the Union is demanding that fifteen days gratuity should be given instead of thirteen days to retrenched employees and in future when new recuritment takes place the retrenched employees should be given employment first. They are demanding that dues in respect of pre-take over should be paid immediately.

Sir, a word about Logur Jute Machinery Ltd. It is the only concern which produces jute mill machinery. It was a viable concern. It was nationalised but it was subsidiary of M/s. James Mackle & Holding Belfast Ltd., U.K. The management is sabotaging production. The Karamchari Samiti. the recognised union, is ready to cooperate. I would like the Minister to go into the details and to take proper steps to make it viable.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir, just one minute more. Hindustan Pilkington Glass Ltd, Asansol, has declared a lock out. We had a talk with the hon'ble Minister and apprised him of the fact as to how Thapars have entered the management and company also. They violated MRTP Act and Foreign Exchange Regulation Act. So, I would request that an inquiry should be done immediately and measures should be taken to open it up immediately. Sen Raleigh group of industries employ about 5,000 workers. All the production units were taken over in 1975. There was improvement till 1978 but after that production is coming down seriously. Nationalisation of the group of industries under a single integrated administration is urgently necessary.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have to conclude now.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I wanted to say a word about Kanpur. In Kanpur three concerns are closed. The names are: J.K. Rayon, Kanpur, Kanpur Chemicals, and J.K. Manufacturers Limited. Regarding all these concerns, proper steps should be taken for reopening.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have sufficient opportunity for the next 4 1/2 years to speak on this matter. You will be given every chance.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I demand nationalisation of the foreign capital. I demand nationalisation of all the concerns of the Indian monopoly capital. All of them should be nationalised. With these words I conclude my speech.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN (Kanpur): I represent a major industrial town. I got my name deleted even from the general budget, speech list because I wanted to speak specifically on the Industry Demands. If you don't allow me, it is somewhat unfair to me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen. The time allotted has already been exhausted. What to do?. I have already said that the Minister will have to reply now.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: The Minister has agreed, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: How can he agree, it is my decision.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: He has agreed.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. You go on. Only 5 minutes.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल इसी सदन में माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस ने बड़ी शिकायत की थी कि इस सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। श्रीमन् मैं मानता हूं कि यह सरकार किसी दुर्घटनावश जन्म में नहीं आयी है। इस सरकार का जिस ढंग से जन्म हुआ है उसका

96 साल पुराना इतिहास है । महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित परम्पराएं हैं । इसलिए श्रीमन् हमारा प्रेरणा स्रोत भारत का संविधान है, हमारा प्रेरणा स्रोत 1946 में जो प्रस्ताव पास किया गया था, 1956 में जिस औद्योगिक नीति से सम्बन्धित प्रस्ताव पास किया गया था, वह है ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री से अनुरोध करूगा कि हमें उस नीति पर सख्ती से कायम रहना चाहिए । श्रीमन् हमारी नीति जो उस समय से चली आ रही है उसी पर हम कटिबद्ध रह कर समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे । श्रीमन्, उसी वक्त से हमारी नीति है कि ऐसे बड़े बड़े उद्योग धधे, बुनियादी उद्योग धंधे जिनमें कि पूंजी की जरूरत हो, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र में कायम किये जाने चाहिएं । श्रीमन् यह उस वक्त से हमारी नीति है और माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस नीति पर ज्यादा तेजी से चला जाए ।

श्रीमन् मैं कानपुर से आता हूं और वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं । कानपुर ऐसा शहर है जिसे मेनेचेस्टर आफ ईस्ट कहा जाता था । लेकिन आज वह बीमार उद्योग धंधों का केन्द्र बन गया है । माननीय उद्योग मंत्री जी के इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है । श्रीमन् मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था कि वहां एक नही चार-चार, पांच-पांच उद्योग धंधे कानपुर में बंद पड़े हुए हैं । जब हम बंद उद्योग धंधों को देखते हैं तो दो साल पहले स्वदेशी काटन मिल की तरफ हमारा ध्यान जाता है जहां दो सौ मजदूर मार डाले गए थे । कानपुर का मजदूर आज कहता है कि ठीक है दो सौ मजदूर मारे गए लेकिन पांच हजार मजदूरों को नौकरी तो मिल गई । अगर दूसरी बन्द मिलो को भी खुलवाने के लिए कुछ मजदूर जान दे दें तो कोई बुराई नही है । ऐसी नौबत न आने पाए इसकी ओर उद्योग मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

कानपुर में टैफको एक आर्गेनाइजेशन है । आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें आज के दौर में भी पिछले तीन साल से जार्ज फर्नान्डीस साहब की मेहरबानी कुछ ज्यादा रही है, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो ज्यादा एक्सपर्ट है, किसी खास काम को करने के, उन लोगों को वहां भेज दिया और वहां के मजदूर को आज भी बारह आने रोज पर मजदूरी करनी पड़ती है । उसे बारह रुपये डी० ए० तो मिलता है लेकिन उसे मजदूरी बारह आने ही मिलती है । मेरा अनुरोध है कि इस दौर में हमको खास तौर से इन मजदूरों की किस्मत को संवारने की कोशिश करनी चाहिये ।

पिछले तीन साल में कोशिश की गई छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के नाम पर इस देश की प्रगति और विकास के पहिये को मोड़ने की । किसलिए ? वे लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल ले कर आए मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने के लिए । गांवों की ओर चलने का नारा लगाया गया । यह सब इसलिए किया गया ताकि वह मजदूर जो शहर में आ कर बड़े उद्योग में लग कर अपने अधिकारों से परिचित होता है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वह लौट कर गांव वापिस चला जाए और उस दल के जो समर्थक है, जो बड़े भूमिपति हैं, उनके बंधुआ मजदूर बन कर वे काम करे । मेरा निवेदन है कि उस सरकार की जो नीतियां हैं बड़े उद्योग धंधों को बढ़ावा देने वाली, मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाली और जिन को पिछले तीन सालों में ज्यादा से ज्यादा लागू करने की कोशिश की गई थी, उनको खत्म किया जाए । उद्योगों का विस्तार किया जाए । बिना उद्योगों के विस्तार के प्रगति और विकास संभव नहीं है । लेकिन उसके साथ-साथ मजदूरों के अधिकार भी सुरक्षित रखे जाने चाहिये ।

एक सजैशन दे कर मैं समाप्त कर दूंगा । बीमार मिलों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन कर हमारे सामने खड़ी हो गई है । मैं चाहता हूं कि बीमार मिलों का अधिग्रहण करने से पहले जो ग्रुप इनको बीमार करते हैं उनको नये लाइसेंस देने से वंचित किया जाये । ऐसा आप चाहे तो कानून में संशोधन करके कर सकते हैं । उनको नया लाइसेंस बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिये । जो मैनेजमेंट किसी मिल को बीमार करता है वह अपनी अक्षमता को सिद्ध कर देता है । मैं यह भी चाहता हूं कि बीमार मिलों का अधिग्रहण करने के साथ साथ उस ग्रुप की जो अच्छी मिले भी हैं उनका भी अधिग्रहण किया जाना चाहिये ताकि घाटे में ऐसी मिलें न चल कर फायदे में चले ।

मैं आपको धन्यवाद देता कि आपने मुझे समय दिया और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर कार्रवाई करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very grateful to my friends on both my party side and on the Opposition side for having analysed and constructively criticised the situation of the industry in the country today.

With a few exceptions where people tried to base things more on verbosity and blackmailing, I would like to point out with due regards to the hon. Members on the Opposition, that they have now started realising that political discipline has to follow different

[Shri Charanjit Chanana]

principles altogether. It is no more the time, no more the situation which our country is passing through as far as industry and as far as economic growth of our country is concerned, that we involve ourselves only in political prostitution. Let us not have any phobias at all. I am not talking much about Mr. Fernandes because I just got a letter from him that he is not well. I am sorry that he is not well and he has not been able to come. As for the type of slanderous language that he used, I told him when he was a Minister, when I was on the Opposition benches, that one who is fond of that hobby forgets one thing that the other side has the potential to rebut also. But our limitation is that our party people work under a discipline and that limitation in fact regulates our behaviour and our character also. That does not exclude the hon. Members on the other side. We have friends like Shri Halder, Shri Jyotirmoy Bosu and others who do not unnecesasrily get excited... (*Interruptions*) We Welcome that criticism; sometimes I provoke friends like Shri Bosu to criticise. Criticism is not bad at all. Criticism is, in fact, a very healthy parameter in democracy.

17 hrs.

While Shri George Fernandes does not deserve a reply on the negative points that he made, I would definitely refer to those points that he raised and which generated suspicion in the minds of the people in the opposition. I only find that he tried to develop friction and he imagined friction and said that something is happening the basis of which was either whispers in the corridors or he was trying to pick up some press cuttings without any connection with them at all and he was quoting. I am not referring to them at all. I am referring to a few other things that he mentioned. The hon. Members would agree with me when I give them the data that he owed more for what he said to the lack of economic intelligence or may be that it was convenient for him to quote only a part of the data. He did not go through the whole of the performance budget or the reports which have been given to the hon. Members.

The first thing that he said and the hon. Members from the opposition followed him also was that we have generated a tilt towards monopolies and FERA companies. It would be of interest to know that during the thirty-three months of the Janata Government and its offshoot, Lok Dal which, also, more or less, represented them, they granted a total of 209 Letters of Intent and fifty letters of intent were issued to foreign major companies and this is a record issuing of these letters. This only shows that we should get rid of this langauge of FERA phobia or MRTP phobia. MRTP and FEPA were introduced by our Government. And as far as its application is concerned its implementation is concerned, the only thing is that we did not only try to lean on a slogan, or a hollow slogan, we meant business and we mean business. Here are the statistics not generated by us, but generated by the 33 months of the Government which was a miscellaneous Government, and with which, I am sorry, some friends sitting on the other side, who were also criticising, were associated.

17.02 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

The hero of the public sector yesterday also spoke of the thirty three months of the public sector undertakings. But unfortunately, whatever data is available on the performance of the public sector during those thirty three months is a very unfortunate one. I would only quote the public sector performance data published by them in their own days. The hon. Members would recall that I had raised a calling attention motion on the mal-performance of the public sector during the Janata rule and at that time, Shri Morarji Desai, the then Prime Minister, refused to reply to that because I would understand, there was a very unpleasant data. I

would only mention that they converted the profit earning units into the loss accruing units. I would like to mention one thing that it is not essentially a good symptom of the public sector performance that when it is losing, it is giving service to the people. This is because we must understand that public sector belongs to us. The public undertakings survey shows that the total net profit of the public sector which was Rs. 183.89 crores in 1976-77 declined in 1978-79 and became a net loss of Rs. 31.96 crores. Would this data provoke you to make a particular person hero of the public sector who talks of the public sector and says that we are going to damage the public sector? I am not going into details of the other data; I have the data also. Then I would like to remind the hon. House and particularly my friends on the opposite that MRTP was brought on the statute book by our party only; we are sticking on to that. Then the hon. member has talked of some figures of cement industry and of paper industry. They are figures which are partial figures. He talks of the investment of a particular industry. I would just bring to your kind notice that that particular data is regarding the Hindustan Paper Corporation. Now Mr. Fernandes spoke of an investment which, in fact, was loan of Rs. 38.38 crores. Now he only read page 24 of the Performance Budget. I would only like you and like him *in absentia*—of course, he has promised that he would read whatever I speak tomorrow—to note this thing that page 21 gives another thing, because investment does not mean investment out of your own pocket; investment also includes the loan. So, the Hindustan Paper Corporation had an investment, had a budget of Rs. 38.13 crores given on page 21 as investment and Rs. 38.38 crores on page 24. The total is Rs. 76.51 crores and not as mentioned by Mr. George Fernandes yesterday Rs. 38.34 crores. Now I would not like to accuse him of picking up these statistics for his convenience. I can only say that probably this budgetary process is a discipline in itself and the hon. member may have to get orientation in this; and then next time when he speaks about this, he should be cautious about it. Similarly, on the Cement Corporation of India, he has again given only half figures and the other half, in the same way, he has forgotten about it. Now the Cement Corporation of India's figure that he talked of was only on page 21 and he forgot to read another page; and the amount that he mentioned was only Rs. 17.69 crores. On page 21 of the same document, there is further provision of Rs. 11.56 crores under the major head 5-6 under capital outlay. This represents the equity investment in the Cement Corporation. The two together, that is loan and the equity add up to nearly Rs. 30 crores. There are other figures also on the Cement Corporation of India. I would only request that the hon. Member should go through the whole thing and if need be, he can come and discuss the whole thing with me and we will give him orientation, as far as going through this is concerned

I would not like to devote much more time on his speech, which he made yesterday. I would only like to clarify a few things I am not fond of going abroad very much, because I had been many a time to different countries; and after I have become Minister, if I go as Minister, I do not go on a holiday trip. I do not have other complexes at all; I have only one complexion and that is the national complexion. Our team, along with the Ministry team, went abroad on the official invitation of the Government of Indonesia; and the result that we had was this. The agreement of understanding that we had was a very objective one. I have already mentioned about it in a Press Conference. The hon. member only switched over and resorted to the convenient figures of his.

Now the other members have talked about a few disciplines. In fact, first of all, industry is a multi-disciplinary concept. So, I would not say anything

[Shri Charanjit Chanana]

about sugar industry or vegetable oil industry to which some hon. Members have referred. The Industries Ministry does have a forum which is a coordination forum, that is the Directorate-General of Technical Development. Otherwise, the administrative Ministries are different. So, I am not replying to the questions regarding, for example, the National Textile Corporation to which some hon. Members have referred. I am not referring to the individual cases to which I have already replied in the House. The suggestions made by the hon. Members even in individual cases have been taken down by me and I will see to it that I take the maximum advantage out of the constructive suggestions made by the hon. Members on both sides of the House. I want to mention one thing, that is not with a complex of guilt at all; it is only for the enlightenment of the Members of the House who often try to claim as if they are the only spokesmen of the workers...

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): You better cover the growth of socialism after the industrial policy resolution.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Before I start reading the statement on industrial policy, I would like to say that most of the Members have raised problems and issues which in fact are covered by the statement which I am going to make; may be we are on the same thinking wave length and perhaps all the points are covered by the statement that I am going to make. There is a fiction which the hon. Members tried to raise and I am just trying to clarify and confirm. The Industrial Policy Resolution of 1956 was a resolution built by our party; and at that time many of the Members sitting on that side probably could not digest that also. The Industrial policy resolution of 1956 has served as a cornerstone of the Congress government policy-frame for the past quarter of a century. The industrial policy announcement of 1956 in fact reflects the value system of our country and shown conclusively the merit of constructive flexibility. In terms of that resolution the task of raising the pillars of economic infrastructure in the country was entrusted to the public sector for reasons of its greater reliability, for the very large investments required and longer gestation periods of the projects crucial for the economic development. The 1956 resolutions therefore forms the basis of this statement of mine.

Coming to take-off stage, industrialisation in a developing economy has two aspects, namely, optimum utilisation of installed capacity and expansion of industries. The industrial progress of India during the past three decades can be attributed to the policies pursued by the Congress government. While the country had reached the take-off stage towards mid-seventies, both the growth channels, optimisation of utilisation of installed capacity as well as expansion of industries were choked off by the 33 months rule of the Janata Party and its successor government. The runaway of the economy has been damaged by the last two governments and the entire process of development was put in the reverse gear.. (*Interruptions*).

I am glad the hon. Members have raised one question; before I go to the next para I shall refer to it. Hon. Members yesterday talked of delay in the announcement of the policy. It was very interesting when I got the diagnosis from another colleague of mine here who said that the Janata government made the announcement of industrial policy after 9 months. A friend of mine, a doctor, said therefore that Mr. Fernandes was looking to the whole thing from a gynaecological point of view. We were in these six months trying to see how much damage has been done by the past governments and we were correcting those damages. In fact it was a huge task before us and we are on that particular thing... (*Interruptions*) We should have, therefore, revival of the

economy which is presently inhibited by infrastructure gaps and inadequacy in performance. This put the economy into a various cycle of shortage of shortages of major industrial inputs like energy, transport and coal, To normalise the situation, Government are working on war-footing, to break this vicious circle and to put the economy again on its feet.

Industrialisation and Economic Progress

Industrialisation is a *sine qua non* of economic progress. Our Government is committed to rapid and balanced industrialisation of the country with a view to benefiting the common man in the shape of increasing availability of goods at fair prices, larger employment and higher **per capita** income. A higher standard of living implies that more of industrial goods go into the consumption basket of the people. Industrialisation is also essential to provide the much-needed support for agriculture and for the development of infrastructural facilities like energy and transport. The net economic impact of industrialisation must travel down ultimately to the maximum number of people in the country.

Distribution of benefits of industrialisation

The pattern of distribution of benefits of industrialisation should be such as to cover as large a segment of the country's population, both rural and urban, while avoiding economic concentration in a few hands. New thrusts need to be made to establish a dynamic industrial economy as indicated in the election manifesto of the Congress Party. Now that the Congress Party has been entrusted with the responsibility of the Government, what is needed above all is a set of pragmatic policies which will remove the lingering constraints to industrial production and, at the same time act as catalysts for faster growth in the coming decades, within the following socio-economic objectives:

Optimum utilisation of the installed capacity.

Maximising production and achieving higher productivity.

Higher employment generation.

Correction of regional imbalances through a preferential development of industrially backward areas.

Strengthening of the agricultural base by according a preferential treatment to agro-based industries, and promoting optimum intersectoral relationship.

Faster promotion of export-oriented and import substitution industries.

Promoting economic federalism with an equitable spread of investment and the dispersal of returns amongst widely spread over small but growing units in rural as well as urban areas.

Consumer protection against high prices and bad quality Role of Public Sector:

An unfortunate development during the recent political vacuum in the country has been an erosion of faith in the public sector which has been reflected in its rather poor performance in recent years. Public sector, which was conceived to provide the pillars of the Country's economic infrastructure, was rendered hollow. The gigantic task before us, therefore, is to rehabilitate faith in the public sector. We have not only to restore people's faith in the public sector but also evolve effective operational systems of management in the public sector undertakings. The public sector has to be identified as people's sector and not as "No body's sector" as was rendered by the last Government. Public sector constitutes a substantial segment of industrial activity in the country and its contribution in terms of generating surpluses and employment for further growth of the economy needs to be improved.

[Shri Charanjit Chanana]

Unit-by-unit examination for corrective stops:

Government have decided to launch a drive to revive the efficiency of public sector undertakings. Industrial undertakings in the sector will be closely examined on a unit-by-unit basis and corrective action will be taken in terms of a time-bound programme wheever necessary. Some of the units were allowed to get into chronic problems and instead of contributing surpluses tended to put a drain on the public exchequer. Priority will be accorded to convert losing concerns into viable ones through broad restructuring of the system and by providing dynamic and competent management

Management Cadre: On the positive side, public sector will continue playing an increasingly important role. Part of the reason for unsatisfactory performance of some of the units in the public sector has been the absence of proper management cadre. It is proposed to take effective steps to build the public sector undertakings and emphasis will be placed on developing management cadres in functional fields such as operations, finance, marketing and information system.

Role of Private Sector: The Government would pursue the goal of a vibrant, self-reliant and modern economy in which all sectors and all segments of the society have a positive role to play. The Industrial Policy Resolution of 1956 assigned a role for industrial undertakings in the private sector within the framework of socio-economic policy of the State and subject to certain regulations in terms of relevant legisations. Government recognises that it would be, in general, desirable to allow private sector undertakings to develop in consonance with targets and objectives of national plans and policies but shall not permit the growth of monopolistic tendencies or concentration of economic power and wealth in a few hands.

SHRI A. K. ROY: On a point of order, Sir. If it is some announcement of policy, the Minister may read from the papers. But while replying to the debate, can he do it?

MR. SPEAKER: Let me know if there is any infringement of any rule.

SHRI A. K. ROY: While replying to the debate, the Minister cannot resort to reading from papers. So many points have been raised and he should reply to those points.

MR. SPEAKER: No point of order.

SHRI CHARANJIT CHANANA: It will be Government's endeavour to reverse the trends of the last three years towards creating artificial divisions between small and large-scale industry under the misconception that these interests are essentially conflicting. While making all efforts towards integrated industrial development, it is proposed to promote the concept of economic federalism with the setting up of a few nucleus plants in each district, identified as industrially backward, to generate as many ancillaries and small and cottage units as possible.

Nucleus Plants: A nucleus plant would concentrate on assembling the products of the ancillary units falling within its orbit on producing the inputs needed by a large number of smaller units and making adequate marketing arrangements. The nuclei will also ensure a widely spread pattern of investment and employment and will distribute the benefits of industrialisation to the maximum possible. The nucleus plants would also work for upgrading the technology of small units. Small is beautiful only if it is growing. Just as

the phased manufacturing programme with a view to reducing reliance on imported components and materials played an important role in diversifying our industrial structure, a carefully worked out time-bound programme for greater ancillarisation in certain industries will contribute considerably towards dispersanl of industry and growth of entrepreneurship.

Ancilarisation Effect: The proposed nucleus plants in industrially backward districts would generate a spread-out network of small-scale units or the existing network of small scale units in an area would acquire a faster growth by the coming up of a nucleus plant in the area. Such a two-way traffic would create an ancillarisation effect in terms of larger employment, more equitable distribution of the benefits of such an industrialisation in the shape of higher per capita income for the larger number of people in the area.

In between the nucleus large plants and the satellite ancillaries, the Government would promote a system of linkage for an integrated industrial development. The Government would evolve scheme of phased development of industrially backward areas through ancillarisation.

Redefining of small scale units: In order to boost the development of small scale industries and to ensure their rapid growth, Government have decided:

(i) to increase the limit of investment in the case of tiny units from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs;

(ii) to increase the limit of investment in the case of small scale units from Rs. 10 lakhs to Rs. 20 lakhs; and

(iii) to increase the limit of investment in the case of ancillaries from Rs. 15 lakhs to Rs. 25 lakhs.

This would eliminate the tendency to circumvent the present limit by understating the value of machinery and equipment, falsification of accounts or resort to 'benami' units. The enhancement of the limit in terms of investment in plants and machinery will also help genuine small scale units particularly those being set up by young and technically qualified entrepreneurs, to come up. This measure will also facilitate long over due modernisation of many of the existing small scale units.

One of the major constraints to the growth of de-centralised sector has been the difficulties of finance experienced particularly by industrial entrepreneurs in small, cottage and rural sectors. Although, there is adequate network of institutional finance, yet there is need for coordinating the flow of capital, both short term and long term. Government would evolve a system of coordination to ensure the flow of credit to the growing units in the de-centralised sector at the right time and on appropriate terms. Government proposes to strengthen the existing arrangements and make such changes as may be necessary to facilitate the availability of credit to the growing units in the small scale sector.

In order to assist the growth of small scale industries, it is proposed to introduce a scheme for building up of buffer stocks of essential materials which are often difficult to obtain. For this the existing set-up such as Small Industries Development Corporations in the States and the National Small Industries Corporation in the Centre will also be utilised. Special needs of States which rely heavily on a few essential raw materials will receive priority.

[Shri Charanjit Chanana]

Policies regarding marketing support to the decentralised sectors and reservation of items for small scale industries, shall continue to be in force in the interest of growth of the small scale industries.

Government is determined to promote such a form of industrialisation in the country as can generate economic viability in the villages. Promotion of suitable industries in rural areas will be accelerated to generate higher employment and higher per capita income for the villagers in the country without disturbing the ecological balance. Handlooms, handicrafts, khadi and other village industries will receive greater attention to achieve a faster rate of growth in the villages.

Industrialisation will play an important role in correcting the regional imbalances and reviving the industrial growth to lead the economy once again to the take-off stage.

PROF. N. G. RANGA: Especially in tribal areas.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Yes. For the achievement of this goal, Government have decided to encourage dispersal of industry and setting of units in industrially backward areas. Special concessions and facilities will be offered for this purpose and these incentives will be growth and performance oriented.

EVALUATION OF INCENTIVES.

In the past, numerous incentives had been provided to industries from time to time. It is Government's considered view that all incentives given to industry must be performance oriented. It is, therefore, proposed that a regular periodic assessment will be made of the impact of these incentives to see the extent to which they have fulfilled their initial purpose. Unless it is apparent that the purpose is being served, Government will review the system of incentives.

Generation of Employment and higher Production:

Industrial development has to be viewed in the broader context of generating higher production and employment. Overcoming the problems of poverty and backwardness need a multi-pronged approach. An integral part of this approach would be to create new focal points of industrial growth which have the maximum effect on the quality of life. This will have to be based essentially on the utilisation of local materials and locally available man-power. The ripple effect of substantial investments in backward districts in the past has in many cases not been adequate, mainly because such investments did not have effective linkages with local resources. Government, therefore, propose to encourage investment by public and private sector which will meet these criteria and would also promote a network of spread out ancillaries.

Endorsement of Licences to reflect existing productive capacity.

In 1975, Government had taken certain decisions in regard to the recognition of additional capacities as a result of replacement and modernisation of equipment, liberalisation of investment procedure for stimulating production in a certain selected industries and for endorsement of excess production over licensed capacity on the basis of a simplified procedure. Government feels that in several industries which are important from the point of view of national economy or are engaged in the production of articles of mass consumption, the productive capacity endorsed on the original licences or as amended in terms of the 1975 notifications may not reflect the full productive potential of the unit. As a result of increased labour productivity or technological improvements, the productive capacities may have increased.

Government propose to recognise such capacities on a selective basis. It would not be in public interest to per-

mit licensing procedures or a rigid locational policy to stand in the way of maximising production. The necessary notifications listing the industries, and spelling out the simplified procedures for such endorsements will be issued separately.

Provision for Automatic Growth:

In view of the constraints on resources in a developing country like ours, and also taking into account the considerable increases in the prices of capital goods, particularly those required to be imported, it is necessary to ensure that no avoidable restrictions are placed on the fullest utilisation of the existing industrial capacities. This is particularly true of the core industries, of industries which have direct linkages with the core sector, and industries which have a long-term export potential. All these industries are of basic, critical and strategic importance for the growth of the economy. In February 1973, Government had announced a list of such industries, following the classification of industries, mentioned in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Later in 1975, Government had permitted the facility for automatic expansion in respect of 15 industries. The extent of increased capacity permitted in respect of these industries was limited to 5 per cent per annum or 25 per cent in a five-year plan period and could be undertaken in one or more stages. This expansion was to be in addition to the normal permissible expansion in production by 25 per cent of the approved capacity. Government have now decided that this facility will also be extended to other industries included in Appendix I. In this behalf, the necessary notifications will be issued separately.

Export Oriented Units : Industry must contribute its share in creating a more favourable balance of trade by catering to the ever increasing foreign markets. Government would sympathetically consider requests for setting up 100 per cent export oriented units, requests for expansion of existing units exclusively for purposes of export and for allowing higher production for exploiting fully the emerging export opportunities.

Advanced Technology for economies of scale : In a number of cases Indian industry has not been able to compete in markets abroad because the scale of output which is related to the level of domestic demand is too small to give them the advantages of modern technology and economies of scale. In cases where a larger production base would increase the competitiveness of Indian Industry abroad, Government will consider favourably the induction of advanced technology and will permit creation of capacity large enough to make it competitive in world markets, provided substantial exports are likely. The purpose of introducing such a policy would be not only to encourage exports but also to enable industry to produce better quality products at lower costs which will ultimately benefit the consumer in terms of price and quality.

I would just briefly mention a few things. Research and Development would in fact be promoted. Transfer of Technology would be promoted. "Modernisation Packages" will be evolved to suit the requirements of each industry and will include all aspects, *i.e.*, appropriate location and optimum use of energy and the adoption of the right kind of scale and technology in order to minimise costs and improve efficiency in the use of scarce materials, the supply of which come from non-renewable sources.

Energy-Industry dovetailing would be done. Energy-saving and energy-conserving units will be given a promotional approach. The pollution control will also be promoted. While the location of industry comes in the picture, we would see to it that ecological balance is maintained and the industry does not add to the pollution in air or water.

[Shri Charanjit Chanana]

Streamlining licensing procedures: There has already been considerable simplication and streamlining of licensing procedures. Never-the-less, there is scope for further improvement and we are working on that.

Monitoring system and data bank: It is also proposed that in future, the agencies connected with the issuance of letters of intent/industrial licences will not merely concern themselves with letters of intent/industrial licences but would also evolve a comprehensive system of monitoring the implementation of the schemes. For this purpose, it is proposed to build up a Data Bank on the progress of various licensed/registered investment schemes. The objectives of this scheme will be to have in respect of all major investments proposals so that nobody sits on the investment sector.

Industrial Sickness: Devising an early warning system. The Government are concerned at the growing problem of sickness in a large number of industries. Many friends showed concern about industrial sickness. What we inherited was nearer the industrial epidemic rather than industrial sickness. We will see that industrial sickness is set right and take all possible steps to cure it.

Merger and Amalgamation: I have already said about it.

Taken-over to be in exceptional cases. It is also Government's policy to ensure that the State Governments, the financial institutions and the labour cooperate effectively for the revival of the sick units. Recourse to take-over of the management under the Industries (Development & Regulation) Act will be taken only in exceptional cases on grounds of public interest where other means for the revival of sick undertakings are not considered feasible. Where such take-over becomes necessary the State Governments will also be involved in that.

Industrial relations: Deteriorating industrial relations in the last three years affected a number of important sectors of economy and led to fall in the industrial production. Government attach great importance to the interests and welfare of labour, but they also consider that the maintenance of constructive and cordial industrial relations in which both labour and management have to cooperate in a responsible manner is essential for the sustained growth of economy. Government have decided to revive the tripartite labour Conference and it is hoped that through an attitude of mutual understanding and constructive cooperation it will be possible to establish higher standards of productivity and industrial harmony.

Industrial Pricing Policy: It is Government's policy that while all reasonable facilities and incentives will be provided to industry, it must recognise and accept its social responsibility particularly in terms of maintaining the price line, avoiding hoarding and speculation, and maximising production on an efficient basis. It is proposed to start a dialogue with the industry to ensure that within a stipulated period of time, the prices are rationalised to the benefit of the consumer.

Government have revised the scheme of district industries centres which has not produced benefits commensurate with the expenditure incurred. Government therefore propose to initiate more effective alternatives.

Industrial Investment: An Inter-Disciplinary Concept. Industrial development is an inter-disciplinary concept. It pertains not only to the manufacturing activity but to all related infrastructure development: licensing and corporate policies: financial, fiscal, trade and pricing policies; industrial relations and management; scientific and technological developments; and broad socio-economic policies. As such, the implementation of the industrial policy requires

close and effective coordination and monitoring at various levels at the Centre as well as between the Centre and the State. Its ultimate success will also depend on the extent of co-operation that Industry receives from the other sections of society.

The Government of India trust that the objectives set out in this Paper and the measures outlined herein to achieve them will receive the support of all sections of the people to enable the country to attain its larger goals, namely, faster economic growth, prosperity to its citizens and the establishment of an egalitarian society.

SHRI A. K. ROY: Sir, we had raised some points in the course of our speeches. We would like that some answers should be given to them. He has not answered. And we do not deserve to be ignored like that. The whole House has been ignored.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: This is an astonishing performance. It has never happened before like this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I want to seek a clarification. I am not going to discuss. Whatever the Minister has done. The House will sit in judgment on that whether the Minister was duty-bound to reply to the points raised or not. You are the custodian of this House, Sir, and I expect you to make suitable observations on the same.

What I want to know from the hon. Minister is this. The other day the Prime Minister, in her wisdom, had given an assurance to the House when we had raised this issue of allowing a collaboration between Brooke Bond and Gillet blade company—it is a low priority and highly profitable area—, the Prime Minister had given a specific assurance on the floor of the House, that they would look into the matter and tell the House. Now, we want to know whether you are allowing this multi-national to come and destroy all our small scale industries which are producing blades and are providing employment—it is a low priority and highly profitable area.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Mr. Speaker, Sir, while talking of the policy now, I would not go in to specific cases like Gillet blade case or Coco Cola case. I have already talked of the MRTP and FERA, and I have assured the House that all the provisions of those Acts, which were introduced by us and which were put by us on the Statute Book, will be implemented. (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The Prime Minister gave a categorical assurance during Question Hour that she did not know about the Gillet blade case and that she would look into the matter and apprise the House. I would only ask the Minister to reply to that.

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): I want to know whether the Government is considering diluting the Industrial Policy Resolution. Some of the industries reserved for the core sector are being thrown open to the public sector. . .

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No; to the private sector.

SHRI NIREN GHOSH: To the private sector..

SHRI CHARANJIT CHANANA: I would only request the hon. Member, first of all, to be sure about whether they are being thrown open to the 'X' sector or 'Y' sector. I have already replied to the question raised by the hon. Member.

The hon. Member had raised the Gillet question in the House and he was replied to that. In the policy matter we are not going to reply about some paper pulp unit which an hon. Member had raised or about NTC, etc We have talked of the policy matter, and within that policy matter. . (*Interruptions*) Let me reply.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The Prime Minister had given a specific assurance. (*Interruptions*) He should reply to it.

SHRI CHARANJIT CHANANA: I will reply, Sir.

SHRI RAVINDRA VARMA: I am constrained to say that the hon. Minister has made a totally disappointing reply. It is conceivable, Sir, that all the points raised cannot be answered in the course of the debate. But this is one of the extraordinary occasions when the hon. Minister has ignored the points raised by the Opposition and indulged in casuistic talk of gynaecology and industry and industrial gynaecology; that was an index of the standard to which he wanted to lower the debate. We are totally disappointed with the fact that he does not care to answer to the points that we have raised....

(*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: Order, please.

SHRI A. K. ROY: I would like to know whether the Kumardhubi Engineering Works about which the hon. Minister has already assured the House once, will be taken over by the Government. ...

(*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: Please sit down. What are you doing? Why are you not sitting? ...

(*Interruptions.*)

SHRI A. K. ROY: Secondly, I want to know whether the representatives of private sector and representatives of the monopoly houses would be removed from the selection Board of the Bureau of Public Enterprises ...

(*Interruptions.*)

SHRI CHARANJIT CHANANA: The constitution of this Board is not done by my Ministry at all. The hon. Member should know better that the constitution of this Board is not within my orbit. It does not fall within my Ministry. ...

(*Interruptions*)

SHRI NIREN GHOSH: Sir, it was never done like this. ...

(*Interruptions*)

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I wanted to now whether the public sector will undertake the industrial development of the backward areas. I want your answer to this simple question...

(*Interruptions.*)

SHRI RAVINDRA VERMA: The hon. Minister does not want to answer questions. In view of the fact that the reply has been flippant and unsatisfactory, we would prefer to walk out...

(*Interruptions.*)

17.55 hrs.

Shri Ravindra Varma and some other hon. Members then left the House.

MR. SPEAKER: I shall now put all the cut motions moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Industry to vote together, unless any honourable Member desires that any of his cut motions may be put separately.

SEVERAL HON. MEMBERS: No, Sir.

MR. SPEAKER: Now, I shall put all the cut motions moved to vote together.

All the cut motions were put and negatived.

MR. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Industry to vote.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1981, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 58 to 60 relating to the Ministry of Industry."

The motion was adopted.

Demands for Grants (General), 1980-81 in respect of the Ministry of Industry voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 14-3-1980		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF INDUSTRY					
58.	Ministry of Industry .	1,27,91,000	..	2,00,92,000	..
59.	Industries	14,43,48,000	89,31,64,000	14,94,12,000	190,77,29,000
60.	Village and Small industries.	9,84,39,000	71,33,000	19,17,05,000	1,42,67,000

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): With your permission, Sir, on behalf of Karnataka State I want to know whether the Vijayanagar Steel Plant is going to be implemented or not.

MR. SPEAKER: No question now.

SHRI K. LAKKAPPA: I am putting the question because it is not coming up.

MR. SPEAKER: It is all over now.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Still we have one minute. We will discuss some demands.

MR. SPEAKER: Not one minute. Only thirty five seconds are left. Now I shall have to go ahead because we are nearing six.

I am sorry—not one minute now, only ten seconds are left. I wanted to hear Shri Banatwalla. But, what can I do? We have only ten seconds left. Please bear with me.

---

18 hrs.

(ii) MINISTERS OF IRRIGATION, CIVIL AVIATION, COMMUNICATIONS, ETC. ETC.

MR. SPEAKER: I shall now put the outstanding Demands for Grants to vote.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts of Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of Indian *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1981, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against:—

(1) Demand No. 10 relating to the Ministry of Irrigation;

(2) Demand No. 14 relating to the Ministry of Civil Supplies;

(3) Demands Nos. 15 to 19 relating to the Ministry of Communications;

(4) Demands Nos. 26 to 29 relating to the Ministry of Education and Culture;

(5) Demands Nos. 32 to 43 relating to the Ministry of Finance;

(6) Demands Nos. 44 to 46 relating to the Ministry of Health and Family Welfare;

(7) Demands Nos. 61 to 63 relating to the Ministry of Information and Broadcasting;

[Mr. Speaker]

(8) Demands Nos. 64 to 65 relating to the Ministry of Labour;

(9) Demands Nos. 66 and 67 relating to the Ministry of Law, Justice and Company Affairs;

(10) Demands Nos. 68 to 70 relating to the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilisers;

(11) Demands Nos. 71 to 73 relating to the Ministry of Planning;

(12) Demands Nos. 75 to 78 relating to the Ministry of Shipping and Transport;

(13) Demand No. 79 relating to the Ministry of Social Welfare;

(14) Demand No. 80—Department of Steel and Demand No. 81—Department of Mines relating to the Ministry of Steel, Mines and Coal;

(15) Demands Nos. 83 to 85 relating to the Ministry of Supply and Rehabilitation;

(16) Demands Nos. 86 to 89 relating to the Ministry of Tourism and Civil Aviation;

(17) Demands Nos. 90 to 94 relating to the Ministry of Works and Housing;

(18) Demands Nos. 95 to 97 relating to the Department of Atomic Energy;

(19) Demand No. 98 relating to the Department of Electronics;

(20) Demands Nos. 99 to 101 relating to the Department of Science and Technology;

(21) Demand No. 102 relating to the Department of Space;

(22) Demand No. 103 relating to the Lok Sabha;

(23) Demand No. 104 relating to the Rajya Sabha;

(24) Demand No. 105 relating to the Department of Parliamentary Affairs;

(25) Demand No. 106 relating to the Secretariat of the Vice-President."

The motion was adopted.

Demands for Grants (General), 1980-81 in respect of Ministries of Irrigation, Civil Aviation, Communications, etc. etc. voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 14-3-1980		Amount of Demand for Grant to voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Captial Rs.	Revenue Rs.	Captial Rs.
MINISTRY OF IRRIGATION					
10.	Ministry of Irrigation . .	11,35,93,000*	1,93,61,000*	21,03,38,000	7,45,89,000
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES					
14.	Ministry of Civil Supplies .	2,94,20,000**	1,79,08,000**	7,63,71,000	4,10,67,000

*Amount voted on account was against Demand 'Department of Irrigation.'

**Amount voted on account was against Demand 'Civil Supplies'.

1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
15.	Ministry of Communications	83,25,000	3,32,00,000	1,69,91,000	6,65,00,000
16.	Overseas Communications Service	5,52,70,000	10,30,44,000	11,35,11,000	16,60,88,000
17.	Posts and Telegraphs—Working Expenses . . .	264,49,51,000	..	561,55,03,000	..
18.	Posts and Telegraphs—Dividend to General Revenues, Appropriations to Reserve Funds and Repayment of Loans from General Revenues . .	79,81,94,000	..	140,39,50,000	..
19.	Captial Outlay on Posts and Telegraphs . . .	148,52,91,000	..	..	303,05,84,000
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE					
26.	Department of Education .	81,23,000	..	1,16,71,000	..
27.	Education . . .	75,32,00,000	1,78,47,000	162,74,63,000	3,56,93,000
28.	Department of Culture .	3,93,45,000	..	8,32,75,000	..
29.	Archaeology . . .	2,29,33,000	..	4,74,67,000	..
MINISTRY OF FINANCE					
32.	Ministry of Finance . .	15,17,83,000	47,13,000	22,78,56,000	94,27,000
33	Customs	16,36,89,000	2,08,33,000	24,44,77,000	4,16,67,000
34	Union Excise Duties . .	20,53,33,000	..	32,33,60,000	..
35.	Taxes on Income, Estate Duty, Wealth Tax and Gift Tax	21,79,60,000	..	34,28,53,000	..
36	Stamps.	6,93,40,000	31,14,000	12,77,68,000	71,28,000
37	Audit	27,36,46,000	..	40,06,36,000	..
38	Currency, Coinage and Minf	15,76,32,000	8,11,91,000	28,74,98,000	16,23,83,000
39	Pensions . . .	21,51,39,000	..	45,72,57,000	..
40	Opium and Alkaloid Factories	23,63,54,000	29,03,000	7,22,18,000	58,04,000
41	Transfers to State Government	448,21,05,000	..	522,67,11,000	..
42	Other Expenditure of the Ministry of Finance . .	421,84,55,000	322,66,93,000	840,86,77,000	577,40,39,000
43	Loans to Government Servants, etc . . .	..	31,33,60,000	..	50,67,22,000

1	2	3		4	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE				
44.	Ministry of Health and Family Welfare .	40,62,000	..	67,40,000	..
45.	Medical and Public Health .	57,82,45,000	24,37,86,000	111,92,21,000	48,46,67,000
46.	Family Welfare . . .	51,87,22,000	..	103,22,44,000	..
	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING				
61.	Ministry of Information and Broad casting . . .	35,10,000	..	55,50,000	..
62.	Information and Publicity .	8,09,87,000	36,82,000	14,66,64,000	1,79,86,000
63.	Broadcasting . . .	26,03,29,000	5,46,79,000	47,40,60,000	9,72,88,000
	MINISTRY OF LABOUR				
64.	Ministry of Labour . .	33,63,000	..	54,53,000	..
65.	Labour and Employment .	21,04,26,000	5,25,000	43,78,26,000	10,50,000
	MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS				
66.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs . .	9,20,22,000 ..	33,000	17,37,31,000	67,000
67.	Administration of Justice .	16,07,000	..	55,11,000	..
	MINISTRY OF PETORLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS				
68.	Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers .	41,29,000	..	67,10,000	..
69.	Petroleum and Petro-Chemicals Industries . .	44,46,04,000	32,04,57,000	46,11,10,000	70,18,17,000
70.	Chemicals and Fertilizers Industries . . .	122,78,30,000	110,28,03,000	55,56,61,000	214,26,05,000
	MINISTRY OF PLANNING				
71.	Ministry of Planning . .	1,30,000	..	2,62,000	..
72.	Statistics	5,49,59,000	..	11,18,68,000	..
73.	Planning Commission .	1,61,44,000	..	3,43,60,000	..

1	2	3	4	
	Revenue Rs.	Captial Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT				
75. Ministry of Shipping and Transport	1,35,54,000	..	2,08,44,000	..
76. Roads	38,39,49,000	34,97,53,000	81,61,91,000	78,87,35,000
77. Ports, Lighthouses and Shipping	27,97,63,000	69,45,51,000	40,06,34,000	134,04,35,000
78. Road and Inland Water Transport	50,43,000	13,58,48,000	96,89,000	27,16,97,000
MINISTRY OF SOCIAL WELFARE				
79. Ministry of Social Welfare	18,62,40,000	31,00,000	52,27,27,000	62,00,000
MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL				
80. Department of Steel.	5,45,93,000	130,76,00,000	15,63,62,000	356,56,90,000
81. Department of Mines	21,51,71,000	26,21,00,000	34,57,58,000	69,42,00,000
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION				
83. Department of Supply	9,90,000	..	15,16,000	..
84. Supplies and Disposals	3,11,48,000	..	4,78,66,000	..
85. Department of Rehabilitation	8,47,41,000	3,46,37,000	16,06,65,000	6,69,38,000
MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION				
86. Ministry of Tourism and Civil Aviation	20,55,000	..	41,12,000	..
87. Meteorology	5,86,46,000	2,76,24,000	11,62,92,000	3,87,48,000
88. Aviation	10,10,95,000	14,71,17,000	23,81,90,000	44,81,33,000
89. Tourism	1,69,09,000	2,51,58,000	3,39,46,000	5,03,15,000
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING				
90. Ministry of Works and Housing	51,44,000	..	78,86,000	..
91. Public Works	38,08,46,000	9,70,95,000	72,57,51,000	20,25,40,000
92. Water Supply and Sewerage	22,16,30,000	..	87,81,70,000	..
93. Housing and Urban Development	7,46,96,000	17,97,42,000	14,63,64,000	36,27,34,000

1	2	3	4	
	Revenue	Capital	Revenue	Capital
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
94. Stationery and Printing .	15,86,94,000	..	29,02,28,000	..
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY				
95. Department of Atomic Energy	20,84,000	..	42,70,000	..
96. Atomic Energy Research, Development and Industrial Projects	32,00,45,000	22,44,66,000	64,70,90,000	67,17,01,000
97. Nuclear Power Schemes .	19,64,86,000	19,62,72,000	39,35,30,000	41,74,96,000
DEPARTMENT OF ELECTRONICS				
98. Department of Electronics.	3,78,00,000	2,16,00,000	7,56,59,000	4,33,50,000
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY				
99. Department of Science and Technology . . .	11,82,02,000	35,00,000	24,00,50,000	70,00,000
100. Survey of India . . .	9,55,75,000	..	16,37,24,000	..
101. Grants to Council of Scientific and Industrial Research . 1	79,16,69,000	..	34,98,38,000	..
DEPARTMENT OF SPACE				
102. Department of Space .	14,66,84,000	12,23,49,000	26,10,99,000	43,79,82,000
PARLIAMENT, DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION				
103. Lok Sabha . . .	2,15,17,000	..	4,24,07,000	..
104. Rajya Sabha . . .	73,05,000	..	1,46,10,000	..
105. Department of Parliamentary Affairs	8,18,000	..	15,19,000	..
106. Secretariat of the Vice-President	2,10,000	..	4,19,000	..